चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

उत्तर बंगाल के आदिवासी टकराव के मूड में

पेज 3

झारखंड चुनाव : आपके जनप्रतिनिधि ऐसे हैं !

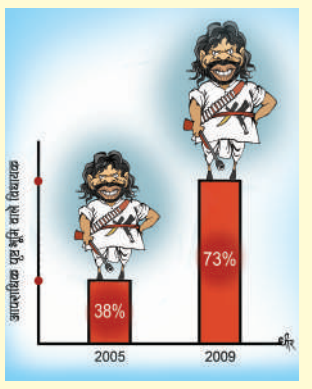

पेज 4

साईं की रहस्यमयी अज्ञात सत्ता

पेज 12

2009 के 09 खलनायक

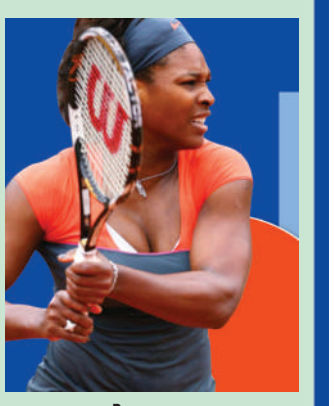

पेज 15

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 11 जनवरी–17 जनवरी 2010

सीआईए और मोसाद की हिंदुस्तान पर बुरी नज़र

काउंट डाउन शुरू हो गया है

आज से अगले पांच सालों में हिंदुस्तान को पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ्रीकी देशों जैसी स्थिति में देखने की कल्पना आपको कैसी लगती है? चौंकिए मत, यह सच होने जा रहा है. जिस तरह इन देशों के न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों और पत्रकारों की साख ख़त्म हो गई है, वैसे ही हमारे देश में भी होने वाला है. जैसे वहां लोकतंत्र पर भरोसा ख़त्म हुआ है, वैसे ही हमारे यहां भी होने वाला है. पैंतीस लोगों में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों के नेता हैं तो कुछ जुझारू और साख वाले पत्रकार भी. यह रिपोर्ट काफ़ी खोजबीन के बाद तैयार हुई है और खोजी पत्रकारिता की झलक दिखाती है. हमारे पास उन पत्रकारों, राजनेताओं के नाम आने शुरू हो गए हैं, जो इन एजेंसियों के लिए देश के लोकतंत्र पर आस्था ख़त्म करने के काम में हिस्सा बंटा रहे हैं. इसका खुलासा अगली रिपोर्ट में करेंगे, पर अभी जो लिख रहे हैं, वह भयावह है और घृणित भी...

रूबी अरुण

यह भारत को तोड़ने की बेहद ख़ौफनाक साज़िश है. जिसे रच रही हैं विश्व की दो सबसे ख़तरनाक ख़ुफ़िया एजेंसियां. मक़सद है हिंदुस्तान में गृहयुद्ध का कोहराम मचाना. यहां की ज़म्हूरियत को नेस्तनाबूद करना. संस्कृति और परंपराओं को दूषित-संक्रमित करना, ताकि इस देश का वजूद ही ख़त्म हो जाए. इसके लिए निशाने पर हैं देश की अज़ीम ओ तरीम 35 हस्तियां. इन दोनों ख़ुफ़िया एजेंसियों के एजेंट्स न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, मंत्रियों, नौकरशाहों एवं शीर्ष पत्रकारों की दिन-रात निगरानी कर रहे हैं. यहां तक कि अपने बेहद निजी पलों में भी ये 35 हस्तियां महफ़ूज नहीं हैं.

जासूसी करने वाले एजेंट्स के नाम हैं-ई जासूस, जो बग़ैर दिखे और बिना किसी कैमरे या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के शयनकक्षों तक में घुसकर अपना जाल बिछा चुके हैं. देश की सभी अहम पार्टियों के शीर्ष नेताओं की हरकतें, उनकी बातचीत सहित कुछ भी, इन ई-जासूसों की नज़रों से छुपा नहीं है. सीआईए और मोसाद मिलकर भारत के ख़िलाफ़ इस षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं. ज़रिया बना है इंटरनेट. फेसबुक, ऑरकुट, जीमेल, याहूमेल, ट्विटर सब पर पैनी नज़र है. अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए ने 20 मिलियन डॉलर निवेश करके इन-क्यू-टेल नाम की एक कंपनी बनाई है. इन-क्यू-टेल ने अमेरिका की कई जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनियों को अपने साथ जोड़ा है. यह कंपनी इंटरनेट की मुक़म्मल दुनिया पर गहरी और बारीक़ नज़र रख रही है. हज़ारों लोगों को इस काम के लिए नियुक्त किया गया है. सीआईए के 90 एजेंट इस पूरे अभियान को दिशा और गति दे रहे हैं. विश्व की 15 प्रमुख भाषाओं में काम किया जा रहा है. सीआईए ने इसके लिए भाषा विशेषज्ञों और सैन्य विशेषज्ञ इंजीनियरों की नियुक्ति की है. हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, उर्दू, फारसी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, जर्मनी, संस्कृत एवं जापानी आदि भाषाओं में इंटरनेट पर होने वाले सभी आदान-प्रदान का रिकॉर्ड सीधे सीआईए मुख्यालय में दर्ज़ हो रहा है.

भारत की गुप्तचर एजेंसियों को इस बात की पूरी ख़बर है कि सीआईए और मोसाद के ई-जासूस इंटरनेट के ज़रिए देश के पैंतीस ख़ासमख़ास लोगों के घरों में अपनी जगह बना चुके हैं. भारत या विश्व में कहीं भी ये पैंतीस लोग जैसे ही अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं, ई-जासूस सक्रिय हो जाते हैं. नेट के ज़रिए चैटिंग, ई-व्यापार, बातचीत, डाटा का आदान-प्रदान, फ्लिकर या यूट्युब का इस्तेमाल आदि सब कुछ सीआईए मुख्यालय और मोसाद मुख्यालय में सीधे रिकॉर्ड हो रहा है. बंद कमरों में की गई इनकी बातें, मुद्दों पर चर्चाएं और योजनाएं-सब. जिस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये सभी सूचनाएं इकट्ठा की जा रही हैं, वह यहां तक बताता है कि कौन सी सूचना नकारात्मक है और कौन सी सकारात्मक, कौन सी चर्चा हल्की है और कौन सी गंभीर. इन 35 लोगों के अलावा भारत के जिन अन्य लोगों का लेखा-जोखा रखा जा रहा है, उनकी बातचीत को भी यह सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड कर रहा है और उनकी श्रेणी भी निर्धारित कर रहा है. सीआईए ने जिन ख़ास लोगों को अपने निशाने पर ले रखा है, उनका वह शारीरिक नुक़सान नहीं करना चाहती, बल्कि उन शीर्ष लोगों के निजी क्षणों का ब्यौरा इकट्ठा कर उनका सामाजिक रूप से पतन करना चाहती है. सीआईए के ई-जासूस चौबीसों घंटों अनवरत सभी साइटों पर भटकते रहते हैं. छोटी से छोटी सूचना भी इनके रिकॉर्ड में प्रमुखता से दर्ज़ होती है. पॉलिग्राफ सिक्यूरिटी में दक्ष, इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरों की पूरी फ़ौज इन सूचनाओं का बारीक़ से बारीक़ विश्लेषण करती है, ताकि भारत के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के तहत देश को संभालने और आगे ले जाने वाली हस्तियों के विरुद्ध सबूत इकट्ठा हो सकें. उनकी निजी पसंद-नापसंद, शौक़ और हरकतों को औज़ार बनाकर समाज में ज़लील करने का सामां हासिल हो सके. भारत की ख़ुफ़िया एजेंसी के एक बड़े अधिकारी बताते हैं कि सीआईए और मोसाद इन दोनों की यही कोशिश है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का इस तरह से चरित्र हनन किया जाए कि वे समाज में अपना मुंह दिखाने के क़ाबिल न रहें. जब चरित्र धूल-धूसरित होगा तो नेता टूटेगा. नेता पर दाग़ लगने से पार्टी बिखरेगी. और, ऐसी हालत में देश कमज़ोर होगा. आमजनों का नेताओं से भरोसा उठेगा, अराजकता फैलेगी. तब सीआईए और मोसाद जैसी विध्वंसकारी ताक़तों को मौक़ा मिलेगा भारत पर क़ाबिज़ होने का, देश को तहस-नहस करने का.

दरअसल देखा जाए तो हो भी यही रहा है. अचानक ही अलगाववादी शक्तियों ने एक साथ अपना सिर उठा लिया है. यूं तो वक़्त-वक़्त पर अलग-अलग राज्यों की मांगें उठती रही हैं, पर ये इतनी तीव्रतर कभी नहीं थीं. तेलंगाना, बुंदेलखंड, कामतापुर, पूर्वांचल, हरित प्रदेश एवं गोरखालैंड आदि राज्यों की मांगें इतनी ज़ोर पकड़ चुकी हैं कि, इनके लिए किए जा रहे आंदोलन हिंसक हो चुके हैं. विघटनकारी तत्व देश की अखंडता पर हावी हो चुके हैं. इन विघटनकारी

(शेष पृष्ठ 2 पर)

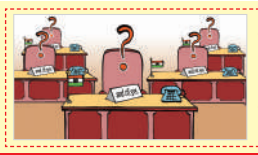

राजग के कार्यकाल में अलग-अलग राज्य सरकार द्वारा नए ज़िलों के निर्माण के बाद अधिकारियों को वहां खपा देना ही इस कमी की वजह बताई जाती है. गृह मंत्रालय ने यूपीएससी से हर साल पुलिस सेवा के अधिकारियों का बैच 130 से 150 तक रखने को कहा है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

विधि मंत्रालय की उलझन

केंद्रीय विधि मंत्रालय इन दिनों कुछ दिलचस्प अंदरूनी बदलाव करने जा रही है. विधि सचिव के रूप में टी के विश्वनाथन की आनन–फानन में की गई नियुक्ति भी उनमें से एक है. विश्वनाथन का एक वर्ष का सेवा विस्तार समाप्त होने ही वाला है. वह मंत्री के सलाहकार पद पर थे. वैसे यह अलग बात है कि इस पद का कोई अस्तित्व ही नहीं है. जबकि वह विधिक और विधायी दोनों ही मामलों का प्रभार संभाले हुए हैं. इस मंत्रालय में विधायी मामलों के सचिव वी के भसीन और विधि सचिव डी आर मीना भी हैं, लेकिन सिर्फ़ एक वर्ष के लिए. लेकिन साथ ही दूसरी ओर यह बात भी है कि विधि मंत्रालय के बाबुओं ने इस मुहिम का स्वागत नहीं किया है. उनमें से कुछ ने तो भसीन की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का मन बना लिया है. उनका मानना है कि भसीन की नियुक्ति इस पद के लिए योग्य चार बाबुओं की वरिष्ठता की अनदेखी करके की गई है. इसके बाद की स्थिति को देखकर बस इतना ही कहा जा सकता है कि मोड़ली अब शायद ख़ुद को उलझे जाले को सुलझाते हुए पाएं.

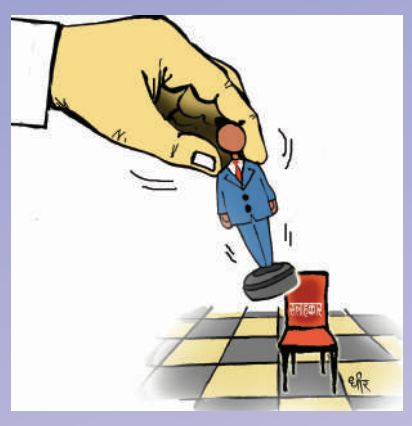

और आईपीएस चाहिए

संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में हर साल दोगुने लोगों की भर्ती का निर्णय लिया है. यूपीएससी की संभ्रांत समझी जाने वाली इस सेवा में अधिकारियों की कमी दूर करना चाहती है. हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारतीय पुलिस सेवा अपने दस प्रतिशत से ज़्यादा अधिकारी दूसरी सेवाओं के हाथों गंवा रही है. इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा भी शामिल है. गृहमंत्री पी चिदंबरम पहले ही 557 अधिकारियों के अंतर की ओर ध्यान दिला चुके हैं. भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की अधिकृत क्षमता 3,889 है, जबकि इसकी वास्तविक क्षमता 3,332 है. राजग के कार्यकाल में अलग–अलग राज्य सरकार द्वारा नए ज़िलों के निर्माण के बाद अधिकारियों को वहां खपा देना ही इस कमी की वजह बताई जाती है. गृह मंत्रालय ने यूपीएससी से हर साल पुलिस सेवा के अधिकारियों का बैच 130 से 150 तक रखने को कहा है. लेकिन, आईपीएस अधिकारियों की बढ़ती कमी को दूर करने के लिए सरकार को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी सेवा में बने रहें.

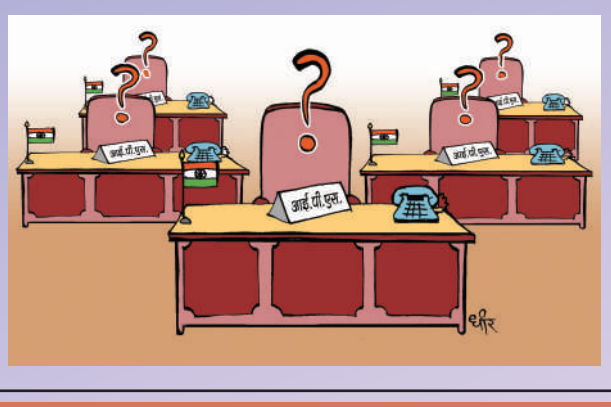

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ग़ुलाम नबी आज़ाद

स्वास्थ्य विभाग का भ्रम

चिकित्सा उपकरण का क्षेत्र काफ़ी हद तक अनियमित है और इसमें एक साथ कई एजेंसियां शामिल हैं. ज़ाहिर है, ऐसे में अंतिम प्राधिकार किसका होगा, इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति स्वाभाविक है. सबसे ज़्यादा भ्रम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच मतभेद को लेकर है. दोनों ने ही अलग बिल तैयार किए हैं.

अंत में प्रधानमंत्री कार्यालय को बीच में अपनी टांगें अड़ानी पड़ीं, तब कहीं जाकर मामला सुलझ पाया. हाल ही में स्वास्थ्य सचिव कनुरू सुजाता राव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. टी रामास्वामी और भारत के औषधि महानियंत्रक के साथ एक बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह संकेत दिया कि स्वास्थ्य मंत्रालय चिकित्सकीय उपकरण उद्योग पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा. स्वास्थ्य विभाग के बाबू अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों का अध्ययन करने में जुटे हैं, ताकि जो बिल उन्होंने तैयार कर रखा है, उसमें ज़रूरी बातें शामिल की जा सकें .

उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा और सभी इससे संतुष्ट होंगे, लेकिन बाबूगीरी के दौर में कोई भी किसी बात को लेकर आश्वस्त नहीं रह सकता.

कारवां का प्रकाशन फिर शुरू

दिल्ली प्रेस अपनी सत्तर साल पुरानी पत्रिका कारवां को ले कर फिर से बाज़ार में उतर चुकी है. नई दिल्ली के प्रेस क्लब में इस मासिक पत्रिका का अनावरण दिल्ली प्रेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनंत नाथ ने किया. जनवरी अंक की आवरण कथा द इंडियन लॉबी इन वाशिंगटन है. ग़ौरतलब है कि कारवां दिल्ली प्रेस की पहली पत्रिका है. इसका प्रकाशन 1939 में दिल्ली प्रेस के संस्थापक विश्वनाथ ने शुरू की थी.

लगभग चालीस वर्षों तक सफल प्रकाशन के बाद 1980 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था. पिछले साल दिल्ली प्रेस ने अपने इस पुराने ब्रांड को पुनर्जीवित करने का फ़ैसला लिया. यह पत्रिका मूलत: राजनीति और संस्कृति पर केंद्रित है. दिल्ली प्रेस के प्रबंध निदेशक अनंत नाथ ने बताया कि कारवां स्टोरी टेलिंग शैली की पत्रिका है और पढ़ने का जो आनंद भारतीय पत्रिकाओं से ग़ायब हो गया है, कारवां उसकी भरपाई करेगी. उन्होंने कारवां की तुलना द न्यूयॉर्कर, द हार्पर और अटलांटिक मंथली आदि विदेशी पत्रिकाओं से की. इंडियन रीडरशिप सर्वे की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक़, पत्रिकाओं की प्रसार संख्या में निरंतर गिरावट बताई गई है. अनंत नाथ ने इस पर कहा कि आईआरएस सर्वे अख़बारों के लिए तो ठीक है, लेकिन यह पत्रिकाओं की सही तस्वीर पेश नहीं करता, इसलिए प्रकाशकों को आईआरएस के सर्वे पर आपत्ति है. पत्रिका से कई जाने माने पत्रकार और नॉन फिक्शन लेखक जुड़ गए हैं.

पुनर्प्रकाशित पत्रिका के प्रथम अंक का लोकार्पण.

सीआईए और मोसाद की हिंदुस्तान पर बुरी नज़र

चरित्र हनन के ज़रिए समाज तोड़ने की साज़िश

सीआईए और मोसाद के गठजोड़ ने भारतीय राजनेताओं, न्यायाधीशों, पत्रकारों, अधिकारियों, बड़े उद्योगपतियों के चरित्र हनन की जो घिनौनी रणनीति बनाई है, उसके तहत उसने रिश्तों की सभी मर्यादाओं को तोड़कर रख दिया है. भारत की गुप्तचर एजेंसियों को कुछ ऐसी तस्वीरें हाथ लगी हैं, जो होश फ़ाख्ता कर देने वाली हैं. सीआईए और मोसाद की योजना इन तस्वीरों को विभिन्न वेबसाइट्स पर एक साथ पोस्ट करने की थी. इन तवीरों में नामचीन हस्तियां विभिन्न मुद्राओं में महिलाओं और पुरुषों के साथ नज़र आ रहे हैं. इन तस्वीरों पर नज़र पड़ते ही एकबारगी उल्टी बातें ही ज़ेहन में उभरती हैं. संबधित व्यक्ति के प्रति कुछ संशय, कुछ सवाल मन में सर उठाते हैं. चौथी दुनिया ने भी इन तस्वीरों को देखा. लाज़िमी है, अटपटा सा लगा. पर जब उन तस्वीरों की बाबत छानबीन की गई तो माज़रा कुछ और निकला. पता चला कि वे देश के प्रमुख लोग, जो तस्वीरों में किसी महिला या पुरुष के साथ नज़र आ रहे हैं, वे दरअसल उनके सगे संबधी हैं, न कि उनके आपत्तिजनक संबंध. अब ज़रा सोचिए. अगर ये तस्वीरें एक बार बाज़ार में आ जाए तो समाज की जो पहली प्रतिक्रिया होगी, वह भूचाल लाने वाली ही होगी. अब उसके बाद लाख सफ़ाई दी जाए कि जो दिख रहा है, उसकी हक़ीक़त कुछ और है, पर सुनेगा कौन? बस यहीं मोसाद और सीआईए की रणनीति कामयाब हो जाती. संस्कार और संस्कृति पर हमलाकर ये दोनों ख़ुफ़िया एजेंसियां हिंदुस्तानी समाज और उसके विश्वास को तोड़ने में सफलता पा लेतीं. 35 मशहूर लोगों के चरित्र को एक के बाद एक, दाग़दार देखने के बाद भारतीय समाज और राजनीति में वो झंझावात मचता, जो इस देश को तबाह कर ही देता. हालांकि हिंदुस्तान के दुश्मनों ने सन 1952 से ही अपनी नापाक सोच को अमल में लाना शुरू कर दिया था. 1952 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी तक का सबसे बड़ा जासूसी अभियान शुरू किया था. उत्तरी कोरिया, चीन और सोवियत संघ की तिकड़ी तोड़ने के लिए, अमेरिका ने बग़ैर भारत को भनक लगे कश्मीर, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाक़ों को तीसरे विश्वयुद्ध की रणनीति बनाने के लिए चिन्हित कर लिया था. अमेरिका के टोही लड़ाकू विमानों ने पूरे इलाक़े का नक़्शा बनाकर उसकी टोह भी ले ली थी. तभी दुर्घटनावश 29 जनवरी 1952 को सीआईए का एक टोही विमान चीन की सीमा के अंदर गिर पड़ा. उसमें सवार तीनों पायलट ज़िंदा बच गए और चीनी सेना की गिरफ्त में आ गए. तब पूछताछ में पूरी साज़िश का ख़ुलासा हुआ. सीआईए के सबसे सफल अधिकारियों में शुमार ब्रोकन रीड ने अपनी 50 साल की नौकरी पूरी करने के बाद यह रहस्य उगला है. ब्रोकन रीड ने कहा है कि अगर उस वक़्त अमेरिका का टोही विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता तो भारत तीसरे विश्वयुद्ध की चपेट में आकर तभी का बर्बाद हो गया होता.

पृष्ठ एक का शेष

शक्तियों को बड़ी आर्थिक मदद विदेशों से मिलती है. ज़ाहिर है, ये वही विदेशी ताक़तें हैं जो भारत की अस्मिता को छिन्न–भिन्न करना चाहती हैं. आज़ादी के बाद देश के 14 राज्यों का 21 राज्यों में बंटना, फिर 25 राज्यों का बन जाना, उसके बाद 28 राज्यों का गठन और अब उनके भी टुकड़े करने की आवाज़ों का उठना. भाषाई, सामाजिक और आर्थिक स्तर के आधार पर हिंदुस्तान के टुकड़े–टुकड़े कर देना. अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के इसी बिखराव का फ़ायदा उठाकर इसे अपना गुलाम बना लिया था.

आज़ादी के बाद भारत एक हुआ. मज़बूत बना. विकास के नए आयाम गढ़े गए. तरक्की के सोपानों पर चढ़ता हुआ भारत विश्वशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ. विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं तोड़ सकी. जबकि अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश की भी चूलें हिल गईं. यक़ीनन ये हालात अमेरिका को गंवारा नहीं. वह भला कैसे चाहेगा कि भारत विश्वशक्ति बन उसका मुक़ाबला करे. लिहाज़ा एक बार फिर भारत को टुकड़ों में करने की साज़िश में सीआईए अपनी सहयोगी मोसाद के साथ लग चुकी है.

सोशल नेटवर्किंग साइट इसमें बहुत बड़ी मददगार साबित हो रही है. साइबर क्राइम के मशहूर वकील पवन दुग्गल कहते हैं कि नेट के 70 प्रतिशत यूजर्स ग़ैर अमेरिकी हैं. ये अमेरिका से बाहर रहते हैं. 180 देशों में इनका जाल फैला हुआ है. 200 से ज़्यादा ग़ैर अमेरिकी भाषी ब्लॉगर ट्विटर समूह हैं. इनकी रीयल टाइम सूचना सीआईए के मिशन को बहुत फ़ायदा पहुंचा रही है. कंप्यूटर्स नेटवर्किंग की सबसे बड़ी कंपनी सिस्को की वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट 2009 में यह भी ख़ुलासा हुआ है कि स्पैम मेल ट्रैफिक के मामले में भारत इस साल दुनिया का नंबर तीन देश बन गया है. इस साल भारत में स्पैम मेल के मामले में 130 प्रतिशत का इज़ाफ़ा हुआ है. भारत में फेसबुक यूजर्स की तादाद 35 करोड़ तक जा पहुंची है. सीआईए के लिए फेसबुक मुंहमांगी मुराद साबित हो रहा है. सीआईए जिस वायरस के ज़रिए अपने ई–जासूसों को बेहद तेज़ी से फैला रहा है, उसका नाम फेसबुक का उल्टा कर कूबफेस रखा गया है. हालांकि सीआईए ने 2008 में ही इस वायरस को इंटरनेट की दुनिया में छोड़ दिया था, लेकिन यह पूरी तरह से सक्रिय 2009 के आख़िर तक हुआ. ट्विटर भी पूरी तरह इसकी चपेट में आ चुका है. शुरुआत में यह वायरस अमूमन यू ट्यूब लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसाता था, लेकिन अब फेसबुक, ट्विटर और ऑरकुट आदि पर दोस्तों के फ़र्ज़ी नाम से सूचनाएं भेजकर पढ़ने को उकसाता है.

सीआईए का सबसे घातक वायरस ट्रॉजन है, जो 2009 का सबसे ख़तरनाक वायरस माना गया है. यह नाम, पासवर्ड, और बैंकिंग डीटेल्स से भी आगे जाकर आपके दोस्तों के भी डिटेल्स चुरा लेता है. यह इतना ख़तरनाक वायरस है कि इसे कई एंटी वायरस प्रोग्राम भी नहीं पकड़ पाते हैं. 2009 में तकरीबन 62 लाख कंप्यूटर इस वायरस के शिकार हुए हैं.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक़, भारत के 172 बेहद मशहूर लोगों की बैंकिंग डीटेल्स और उनकी निजी बातें इस वायरस ने हैक कर ली हैं. इसमें कुछ ऐसे संवेदनशील मसले हैं कि जो आम हो जाएं तो देश में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट खड़ा हो जाए. भारत में गृहयुद्ध के आसार पैदा करने के लिए सीआईए और मोसाद इन्हीं उपलब्ध सूचनाओं को अपना हथियार बना रही हैं. वे बस सही मौक़े की तलाश में हैं.

ruby@chauthiduniya.com

राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला भी बने शिकार

तीन फरवरी, 2007 कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी से संबंधित बहुत सारी अश्लील सामग्री अचानक एक वेबसाइट पर नमूदार होती है. इस वेबसाइट पर राहुल गांधी के चरित्र पर कीचड़ उछालने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखी गई थी. कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया था. विपक्षी पार्टियों के नेताओं को रस तो आ रहा था, पर वे तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे. हर कोई सांस रोके सही बात जानने के इंतज़ार में था. मामला सत्तारूढ़ पार्टी के युवराज का था. लिहाज़ा ख़ुफ़िया एजेंसियों ने अपनी पूरी ताक़त छानबीन में झोंक दी. पता चला कि अमेरिका के रहने वाले दो व्यक्तियों ने वेबसाइट पर राहुल गांधी से संबंधित अश्लील सामग्री डाली थी. बेहद मशक्कत से उनका ई-मेल आईडी और पता ठिकाना भी मालूम कर लिया गया. कांग्रेस प्रवक्ता और पेशे से वकील अभिषेक मनु संघवी ने उन दोनों अमेरीकियों को क़ानूनी नोटिस भी भेजा. जांच कुछ और आगे बढ़ी तो पता चला कि राहुल को बदनाम करने के लिए वेबसाइट विजुअल टेक्नोलॉजी नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी की है. ये विजुअल टेक्नोलॉजी वही कंपनी है, जिसने सीआईए की जासूसी कंपनी आई-क्यू-टेल के लिए उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, जो इंटरनेट पर ई-जासूसी का काम करता है. यह जानकर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के हाथ पैर फूले हुए हैं.

अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की. 2006 में जम्मू कश्मीर में हुए एक सेक्सकांड में उनका नाम विरोधियों ने जमकर घसीटा. हवाला दिया गया कि उमर अब्दुल्ला का नाम सीबीआई जांच में सामने आया है. इस मसले पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ हंगामा आज भी लोगों को याद है. अपने चरित्र हनन से दुखी होकर उमर अबदुल्ला ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा तक दे दिया था. लेकिन जब जांच हुई तो उमर अब्दुल्ला को निर्दोष पाए गए. मुख्यमंत्री तो वह बने रहे, पर उनकी छवि को जो नुक़सान पहुंचा, उसकी भरपाई होनी मुश्किल है.

बाद में पता चला कि उमर अब्दुल्ला के चरित्र पर कलंक लगाने वाले पीडीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुज़फ्फर बेग ने जिस सूची के आधार पर सेक्स कांड के आरोपियों की सूची में उमर अब्दुल्ला का नाम होने का दावा किया था, वह सूची एक फ़र्ज़ी वेबसाइट से डाउनलोड थी. इस वेबसाइट की आईडी भी अमेरिका की ही थी.

हालांकि उमर अब्दुल्ला के चरित्र हनन का मामला शांत होने के बाद उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के लोगों ने भी मुज़फ्फर बेग की जमकर छीछालेदर की. मुज़फ्फर बेग का नाम कई महिलाओं से जोड़ा गया. एक बड़े पत्रकार की विधवा से लेकर एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश की बेटी तथा एक सिनेमा हॉल की मालिक की बहन और भतीजी तक से उनके अवैध संबंधों की बात कही गई. जब सफ़ेदपोश डॉन रोमेश शर्मा की गिरफ़्तारी हुई थी, तो उसके घर की तलाशी में कई नेताओं और भगवा पार्टी के प्रमुख नेत्रियों की अश्लील तस्वीरें बरामद होने की बात सामने आई थी.

वैसे देश में जब कभी आम चुनाव या विधानसभा चुनावों का वक़्त होता है तो नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुट जाते हैं. एक दूसरे पर अश्लील आरोप लगाते हैं. सपा नेता और मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा और आज़म ख़ान की सियासी जंग का शर्मनाक नज़ारा अभी भी सबको याद है. पर चुनावी फ़िजां ख़त्म होते ही ये बातें भी गई बीती हो जाती हैं. पर सीआईए और मोसाद चरित्र हनन का जो भयावह खेल खेल रहे हैं, वह हिंदुस्तान के अस्तित्व को ही ख़त्म करने वाला है.

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 1 अंक 44,
दिल्ली, 11 जनवरी–17 जनवरी 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 011–23418962
विज्ञापन + 0120–4783999
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4 बिहार व झारखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अभी हाल में ही भूटान से सटे जयगांव के विधायक विल्सन चंपामारी सहित 200 गोजमुमो समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया. रास्ता रोकने के कुछ घंटों बाद ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया.

बंद बागानों में पसरती मौत

उत्तर बंगाल के डुआर्स इलाक़े की संस्कृति बंगालियों से बिल्कुल अलग है. 1865 में यह इलाक़ा भूटान से मिलने के बाद अंग्रेजों ने 19वीं सदी में यहां चाय की खेती शुरू की और वे संथाल परगना इलाक़े से मेहनती आदिवासियों को ले गए. इसी वजह से कभी कामतापुर वाले इस पर नज़र गड़ाते हैं तो कभी गोरखालैंड वाले. बहुत कम जनाधार एवं ग्रेटर कूच बिहार की मांग करने वाले भाई लोग भी आदिवासियों की इस ज़मीन को छीनने की फ़िराक़ में रहते हैं. इन बागान श्रमिकों के लिए चाय ही उनका भूत है और चाय ही उनका भविष्य. हम साफ़-साफ़ इनका वर्तमान तो देख ही रहे हैं.

बागानों में ग़रीब आदिवासियों की पीड़ा की एक बानगी देखनी चाहिए. टेटले विश्व का सबसे ज़्यादा बिकने वाला चाय ब्रांड है. यह नोवडा नड्डी बागान अमल्गमेटेड प्लांटेशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, जिसके 49.98 शेयर टाटा चाय के पास हैं, जिसके भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बने विज्ञापन देश का ध्यान खींचते हैं. बागान में काम करने वाले 1000 कामगारों और उनके परिवार के सदस्य भुखमरी की कगार पर आ गए हैं. इस साल अगस्त से यहां लॉकआउट चल रहा है. हालात ख़राब हुए इस साल अगस्त से, जब एक 22 वर्षीय महिला आरती ओरांव को मातृत्व अवकाश न देने के प्रबंधन के फ़ैसले से बवाल मच गया. आठ महीने के गर्भ की अवस्था में उससे ज़बरन चाय की पत्ती तुड़वाई गई. 9 अगस्त को आरती बागान में ही बेहोश होकर गिर पड़ी. अस्पताल के मेडिकल अफ़सर ने एंबुलेंस भेजने से इंकार कर दिया और उसे साइकिल पर बैठाकर अस्पताल लाने के लिए कहा. आख़िर में उसे कूड़ा उठाने वाले ट्रैक्टर में अस्पताल लाया गया. काफी हील-हुज्जत के बाद उसे भर्ती तो किया गया, पर तुरंत दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया. 500 बागान श्रमिकों ने यह ख़बर सुनने के मेडिकल अफ़सर के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी शुरू कर दी. टाटा टी प्रबंधन का आरोप है कि मातृत्व अवकाश देने से इंकार करने पर श्रमिकों ने डॉक्टरों की पिटाई की. बागान प्रबंधक ने श्रमिकों से मिलकर मसले का हल निकालने का वचन दिया, पर 11 अगस्त को अचानक बागान में लॉकआउट घोषित कर दिया गया. 27 अगस्त को बागान खोलने के लिए तीन ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता हुआ. उक्त यूनियनें बागान के बहुसंख्यक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं. दूसरे ही दिन बागान फिर से खोला गया, हालांकि श्रमिकों को इसकी कोई सूचना नहीं थी. प्रबंधन ने बागान में श्रमिकों के अधिकारों की अलख जगा रहे आठ कामगारों को निशाना बनाया और उन्हें निलंबित कर दिया. 10 सितंबर की बैठक में प्रबंधकों ने कहा कि इनका निलंबन आदेश स्वीकार करो या फिर से लॉकआउट. श्रमिकों ने निलंबन की मांग मंजूर नहीं की और अभी भी ताला बंद है. जलपाईगुड़ी का रायपुर बागान 2003 से ही बंद है. कलावती बाराई पिछले चार सालों से अपने परिवार को किस्तों में मरते देख रही हैं. गत मार्च से कार्तिक बीमार है, पर इलाज के लिए पैसे नहीं हैं. तीन साल से वह स्कूल नहीं जा रहा है. पेट की आग शांत करने के लिए यहां के आदिवासी जंगली घास एवं चूहे खाकर गुज़ारा करने पर मजबूर हैं. बागानों में लॉकआउट का सिलसिला थमता नज़र नहीं आ रहा है. अभी उत्तर बंगाल के 9 बागानों में तालाबंदी है, जिससे 37 हज़ार मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं. जो बागान बंद हो जाते हैं, वहां से पानी, राशन, चिकित्सा व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी वापस ले ली जाती हैं. मजदूर भूख से मरते हैं, पर राज्य सरकार नहीं यह बात मानती.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़, 1 जनवरी 2006 से 31 मार्च 2007 तक उत्तर बंगाल के चाय बागानों में 571 मौतें हुई हैं, जिनमें से 402 लोगों की उम्र 60 साल से कम थी. इनमें 317 महिलाएं, 254 पुरुष और 10 साल से कम उम्र के 62 बच्चे भी थे. ग़ौरतलब है कि इन 571 मौतों में 465 लोगों की मौत उनके घरों में ही हुई. ग़ैर-सरकारी सूत्रों के मुताबिक़, 2003 से 2007 तक चाय बागानों में कुल 2500 मौतें हुई हैं. उत्तर बंगाल के केवल 18 चाय बागानों में भविष्य निधि के 144,842,831 रुपये, ग्रेच्युटी के 46,206,762.91 रुपये और वेतन एवं अन्य देनदारियों के मद में 175, 194,059.62 रुपये बकाया हैं. पिछले लोकसभा चुनावों में बंद पड़े चाय बागान एक प्रमुख चुनावी मुद्दा थे. जुलाई माह में केंद्रीय वाणिज्य राज्यमंत्री जयराम रमेश ने बंद पड़े 14 चाय बागानों को खोलने के लिए 15 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था. इसके अलावा 50 साल पुराने बागानों को फिर से लगाने के लिए 50 करोड़ रुपये का एक चाय कोष बनाने का प्रस्ताव है. इस तरह योजनाएं बहुत पहले से बन रही हैं, पर बहुत कम ही अमलीजामा पहन पाती हैं. उत्तर बंगाल के चाय नीलामी केंद्र में इंटरनेट से अब बोली लगती है, पर उगाने वाले श्रमिक चूहा खाकर जी रहे हैं

उत्तर बंगाल के आदिवासी टकराव के मूड में

बिमल राय

उत्तर बंगाल की हरे सोने वाली धरती डुआर्स में बवाल मचा है. गोरखालैंड की आग से निकलती चिंगारियां हरी पत्तियों को झुलसाने लगी हैं. विमल गुरुंग इस आदिवासी बहुल इलाक़े को गोरखालैंड के नक़्शे में शामिल करना चाहते हैं, जबकि यहां के बहुसंख्यक आदिवासी जैसे हैं-जहां हैं के आधार पर बंगाल में ही रहना चाहते हैं. बंद चाय बागानों की वजह से इस इलाक़े में पहले से ही भुखमरी के हालात हैं, उस पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)के पथावरोध आंदोलन ने जले पर नमक रगड़ने का सिलसिला शुरू किया है. इस आंदोलन से चाय की ढुलाई भी ठप है और पर्यटन के साथ-साथ तमाम आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं.

साल के आख़िरी दिन का सूरज भी तनाव के माहौल में ही डूबा. थोड़ी भी उम्मीद की लालिमा नहीं दिखी. एक तरफ़ जहां दार्जिलिंग में बर्फ़ पड़ी, वहीं मैदानी इलाक़े में राजनीतिक टकराव की गर्मी बढ़ी. राजमार्गों पर अवरोध आंदोलन कर रहे गोजमुमो कार्यकर्ताओं ने मालबाज़ार में एक एंबुलेंस के ड्राइवर एवं खलासी को पीटा तो सिलीगुड़ी और डुआर्स के बंगाली संगठनों ने दार्जिलिंग जाने वाले तीनों रास्तों को रोक दिया. नाराज़ विमल गुरुंग ने तुरंत 2 जनवरी को बंद का आह्वान कर दिया, हालांकि कुछ घंटों बाद दिल्ली से संदेश आने के बाद उन्होंने फैसला वापस ले लिया. गुरुंग राजनीतिक स्तर की बातचीत जल्द से जल्द शुरू करने के लिए अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं. सिलीगुड़ी और डुआर्स इलाक़े में गोरखालैंड विरोधियों ने लालगढ़ की तरह जनसाधारण कमेटी बना ली है तथा आदिवासियों के साथ मिलकर गोजमुमो को करारा जवाब देने की ठान ली है. इनमें बांग्ला एवं बांग्ला भाषा बचाओ समिति, आमरा बंगाली एवं जनजागरण मंच जैसे संगठन हैं. पिछले साल 16 जनवरी को ही जलपाईगुड़ी ज़िले में गोजमुमो और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़पों में एक पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल हो गए थे. मालबाज़ार इलाक़े में हुई एक झड़प को रोकने के लिए पुलिस को पहले लाठीचार्ज करना पड़ा और बाद में हवा में गोलियां दागनी पड़ीं. यहां मोर्चा की रैली को रोकने के लिए विकास परिषद ने बंद का आह्वान किया था. इसके पहले दोनों दलों के बीच हुई झड़पों के बाद दर्ज़नों घरों में आगजनी हुई. टकराव टालने के लिए एक दिसंबर को जलपाईगुड़ी ज़िले के मालबाज़ार में आयोजित एक शांति बैठक में परिषद ने गोजमुमो नेताओं को अपने रुख़ के बारे में बता दिया. 15 नवंबर को गोजमुमो के आग्रह पर ही यह बैठक आयोजित हुई थी और उसमें डुआर्स में अमन बहाल रखने पर दोनों दलों के बीच सहमति बनी. हालांकि यह सहमति अब टूटने के कगार पर है, क्योंकि गोजमुमो ने 26 दिसंबर से फिर गोरखालैंड की मांग के समर्थन में रास्ता रोको अभियान चला रखा है. आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं. इस आंदोलन से आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है.

कालचीनी में रास्ता जाम करते गोजमुमो कार्यकर्ता.

अभी हाल में ही भूटान से सटे जयगांव के विधायक विल्सन चंपामारी सहित 200 गोजमुमो समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया. रास्ता रोकने के कुछ घंटों बाद ही स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया और पुलिस को मजबूर होकर यह कार्रवाई करनी पड़ी. गिरफ़्तारी के विरोध में गोजमुमो कार्यकर्ताओं ने मटियाली, जयगांव एवं वीरपाड़ा थानों का घेराव किया और अपना आंदोलन जारी रखने का फ़ैसला लिया. डुआर्स इलाक़े के गोरखालैंड विरोधियों ने सरकार की इंतज़ार करो और देखो की नीति के प्रति नाख़ुशी ज़ाहिर करते हुए अपने बूते पर गोरखालैंड आंदोलन का मुक़ाबला करने की बात कही है. वैसे उत्तर बंगाल के आईजीपी के एल टामटा ने प्रभावित इलाक़ों में रास्ता रोको आंदोलनकारियों से निपटने की बात कही है. डुआर्स इलाक़े में गोजमुमो समर्थकों का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है कि हाल ही में हुए कालचीनी विधानसभा उपचुनावों में गोरखालैंड समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार चंपामारी ने आदिवासी विकास परिषद के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की. ग़ौर करने की बात यह है कि इलाक़े की 70 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी आदिवासियों की है और परिषद अपनी पकड़ मज़बूत करने के लिए हिंसा का रास्ता भी अपना सकती है. परिषद के राज्य अध्यक्ष विरसा तिर्की ने चौथी दुनिया से बातचीत के दौरान उन कारणों को साफ़ किया, जिससे उनका गोरखालैंड में शामिल होना बेमानी होगा. उनके मुताबिक़, आदिवासी समुदाय के हित की गारंटी भारत के संविधान में दी हुई है. वह कहते हैं कि 200 साल पहले हमारे पुरखे यहां आए. ज़मीन को समतल कर हमने चाय बागानों को अपने पसीने से सींचा. डुआर्स तराई की 70 से 75 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है और 8 से 10 प्रतिशत की आबादी गोरखाओं की है. फिर हमारे गोरखालैंड का समर्थन करने का कहां सवाल उठता है? गत वर्ष 29 जनवरी को परिषद ने मुख्यमंत्री को एक 13 सूत्री ज्ञापन दिया. सरकार ने जलपाईगुड़ी और डुआर्स में एक हिंदी हाईस्कूल, एक कॉलेज एवं एक पॉलीटेक्निक संस्थान खोलने का आश्वासन दिया है. आदिवासियों ने ज़मीन का पट्टा देने की भी मांग रखी है. मालूम हो कि लीज बागान मालिकों को ज़मीन देने के बाद भी जो सरकारी ज़मीन बची है, उस पर उनका ज़बरन क़ब्ज़ा है. अगर यह ज़मीन भूमिहीन आदिवासियों को दे दी जाए तो इलाक़े की तस्वीर बदल सकती है. इस पहल को लटकाने के इरादे से बागान मालिकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

वैसे गोजमुमो नेताओं ने इलाक़े के पिछड़ेपन को उजागर कर आदिवासियों को साथ लेने की पहल की. पिछले 21 दिसंबर को गोजमुमो ने पहाड़ के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले ग़रीब आदिवासी छात्रों को आर्थिक मदद मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा. इसके लिए जल्दी ही संस्थानों के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक होने वाली है. इसे आदिवासियों को लुभाने की कोशिश माना जा रहा है. परिषद की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव जुलियानी टोप्पो ने चौथी दुनिया को बताया कि आदिवासियों को गोरखालैंड में जाने की ज़रूरत नहीं है. अब तक अशिक्षा एवं पिछड़ेपन का फ़ायदा उठाते हुए इनका शोषण किया गया है. उन्होंने स्वीकार किया कि वाममोर्चा के 33 वर्षों के शासन में उत्तर बंगाल के आदिवासियों की उपेक्षा की गई. इसके लिए वह एक हद तक अफ़सरशाही को ज़िम्मेदार मानती हैं, जो कल्याण योजनाओं को निचले तबके तक पहुंचने नहीं देते.

आंकड़ों का आईना

नेशनल सैंपल सर्वे (एनएसएस) की ओर से जारी किए गए आकड़ों के मुताबिक़, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाक़ों में प्रति 10 हज़ार में 106 परिवार ऐसे हैं, जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता. आंध्र में यह आंकड़ा प्रति हज़ार 6 परिवारों का है. इनमें से भी 13 परिवारों को पूरे साल पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता. पूरे साल आधा पेट खाने वाले परिवार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र में एक भी नहीं हैं. पश्चिम बंगाल उड़ीसा से थोड़ा बेहतर हालत में हैं, जहां एक हज़ार में 13 परिवारों को भरपेट भोजन नहीं मिलता.

वर्ष 2004 में प्रकाशित वेस्ट बंगाल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे राज्य सरकार ने भी मंजूरी दी, के मुताबिक़ उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, मालदा, उत्तर दिनाजपुर एवं दक्षिण दिनाजपुर और पश्चिमी हिस्से के तीन आदिवासी बहुल पुरुलिया, बांकुड़ा एवं वीरभूम तथा दोनों 24 परगनाओं के सुंदरवन में पड़ने वाले इलाक़े सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं.

योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, बंगाल के 24.7 प्रतिशत लोग ग़रीबी रेखा के नीचे रहते हैं. बंगाल की वाम सरकार के 33 सालों के शासन पर कांग्रेस की ओर से प्रकाशित की गई एक पुस्तिका के मुताबिक़, पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाक़ों के 42.4 प्रतिशत आदिवासी ग़रीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं. एनएसएस के 1999-2000 के आंकड़ों के मुताबिक़, पुरुलिया की 78.7 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ग़रीबी रेखा के भार से दबी थी. वेस्ट बंगाल राइट टू फूड एंड वर्क की अनुराधा तलवार के मुताबिक़, किसी भी दूसरे संगठित क्षेत्र के श्रमिक कुपोषण के उतने शिकार नहीं हैं, जितने चाय श्रमिक हैं. पश्चिम बंगाल खेत मजदूर श्रमिक समिति के मुताबिक़, बंद बागानों के श्रमिकों को हर रोज़ 200 कैलोरी (निम्नतम ज़रूरत 850 कैलोरी) का भोजन ही मिल पा रहा है, जबकि बागान खुले रहने के समय उन्हें 1000 से 1200 कैलोरी का भोजन मिलता था.

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड के 81 नवनिर्वाचित विधायकों में से 59 की पृष्ठभूमि आपराधिक है. यानी जनता की नुमाइंदगी करने वाले 73 फ़ीसदी विधायकों के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमे लंबित हैं.

झारखंड चुनाव

आपके जनप्रतिनिधि ऐसे हैं!

झारखंड की राजनीति में भ्रष्टाचारी और अपराधी ऐसे घुल-मिल चुके हैं, जैसे शर्बत में चीनी. दोनों को एक दूसरे से अलग कर पाना नामुमकिन-सा हो गया है. पिछले चुनाव की तुलना में इस बार ज़्यादा बाहुबली, दाग़ी और धनबली चुनाव जीत कर झारखंड विधानसभा की शोभा बढ़ाने आ पहुंचे हैं. अगले पांच सालों तक झारखंड की जनता पर शासन करने वाले इन विधायकों और मंत्रियों की चाल, चरित्र और चेहरे के साथ-साथ धनबल और बाहुबल पर चौथी दुनिया की एक ख़ास रिपोर्ट:

शशि शेखर

झारखंड राज्य के गठन के अभी महज़ नौ साल ही हुए हैं. इन नौ सालों में अब तक यहां छह सरकारें बदल गईं और सातवीं बन चुकी है. एक के बाद एक कई सरकारें बनने के बाद भी झारखंड और झारखंड के लोगों की तक़दीर नहीं बदल सकी. बेहतर सुविधाओं की कौन कहे, वहां के लोग तो अभी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं. अलबत्ता, झारखंड में एक निर्दलीय विधायक से मुख्यमंत्री बने मधु कोड़ा और उनके जैसे कई लोग हज़ारों करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक ज़रूर बन बैठे. आख़िर खनिज संपदाओं से भरे इस छोटे राज्य की आम जनता की आर्थिक बदहाली की वजह क्या है? ज़ाहिर है, शर्बत में चीनी की तरह ही झारखंड की राजनीति में भ्रष्टाचारी और अपराधी कुछ इस तरह से घुल-मिल चुके हैं, जिन्हें अलग कर पाना नामुमकिन-सा हो गया है. बावजूद इसके, झारखंड चुनाव में इस बार भी भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं बन सका. पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कहीं अधिक बाहुबली, दागी और धनबली चुनाव जीत कर, झारखंड विधान सभा की शोभा बढ़ाने आ पहुंचे हैं. अगले पांच सालों तक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, झारखंड की जनता पर शासन करने वाले इन विधायकों और मंत्रियों के बैंक बैलेंस में भी ज़बर्दस्त इजाफा होने से इंकार नहीं किया जा सकता. ऐसे नेताओं के चाल, चरित्र और चेहरा के साथ-साथ उनके धनबल और बाहुबल के बारे में भी वहां की जनता बाख़बर रहें, चौथी दुनिया इस रिपोर्ट के ज़रिए यही कोशिश कर रही है.

(2009 का विधानसभा चुनाव)

दल	विधायकों की संख्या	विधायक, जिन पर आपराधिक मामले हैं	प्रतिशत
झामुमो	18	17	94
कांग्रेस	14	11	79
झाविमो	11	8	73
भाजपा	18	8	44
आजसू	5	4	80
राजद	5	4	80
निर्दलीय	2	2	100
जद(यू)	2	1	50
झारखंड जनाधिकार मंच	1	1	100
राष्ट्रीय कल्याण पक्ष	1	1	100
मार्क्सवादी गठबंधन	1	1	100
झारखंड पार्टी	1	1	100
कुल		59	

(आंकड़े: एडीआर)

गणतंत्र के गन-पति

झारखंड के 81 नवनिर्वाचित विधायकों में से 59 विधायकों की पृष्ठभूमि आपराधिक है. यानि, जनता की नुमांइदगी करने वाले 73 फ़ीसदी विधायकों के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमे लंबित है. इन 59 विधायकों में से भी 26, यानी 32 फ़ीसदी ऐसे हैं, जिनके ख़िलाफ़ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और चोरी इत्यादि जैसे गंभीर मामले लंबित हैं, इन 26 में से 14 लोगों के ख़िलाफ़ हत्या के प्रयास, चार के ख़िलाफ हत्या और आठ के ख़िलाफ़ चोरी जैसे मामले चल रहे हैं. झारखंड में 81 सीटों के लिए हुए चुनाव में 1491 उम्मीदवारों ने अपनी क़िस्मत आज़माई थी. इनमें से 1018 उम्मीदवारों की ओर से दाख़िल किए गए हलफ़नामे से यह जानकारी मिली है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के 329 लोगों ने विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ा. दिलचस्प तथ्य यह है कि इन 329 उम्मीदवारों में से 59 लोग अब विधानसभा की शोभा बढाएंगे. बहुत संभव है कि इनमें से कुछ को मंत्री या मंत्रियों जैसी सुविधाओं वाला कोई पद भी मिल जाए. लोकतंत्र के महापर्व में जो विजय प्रसाद बंटा है या कहें कि छीना गया है, उसमें कोई अकेला दल शामिल नहीं है. अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि इस बार नवनिर्वाचित विधायकों में आपराधिक छवि वाले लोगों की संख्या पिछले चुनाव यानी 2005 के मुक़ाबले 28 ज़्यादा है. 2005 के चुनाव में जहां 31 विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, वहीं इस बार यह संख्या 59 है. आपराधिक पृष्ठभूमि के ज़्यादातर विधायक सबसे अधिक गुरु जी यानी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार में शामिल अन्य दलों से ताल्लुक़ रखते हैं. झामुमो के 18 में से 17 विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं. वैसे कांग्रेस और राजद के भी लगभग 80 फ़ीसदी विधायकों पर कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं. इस मामले में निर्दलीय विधायक सबसे आगे हैं. इस बार की विधान सभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या दो है और दोनों पर आपराधिक मामले दर्ज़ हैं. यानी झारखंड में सौ फ़ीसदी निर्दलीय विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं. सबसे अधिक आपराधिक मामले झारखंड जनाधिकार मंच के बंधु तिर्की पर है. इन पर हत्या के प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने जैसे गंभीर मामले भी दर्ज़ हैं. गोड्डा से राजद विधायक संजय यादव, बंधु तिर्की से बस एक ही क़दम पीछे है. इन पर हत्या और चोरी सहित नौ मामले दर्ज़ हैं, लेकिन तिर्की की ही तरह अब तक इन्हें भी किसी मामले में सज़ा नहीं दी जा सकी है. झामुमो के हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और नलिन सोरेन पर भी कई आपराधिक मामले चल रहे हैं. कुल मिला कर कहें तो पिछले पांच सालों में झारखंड के नेताओं का आपराधिक मामलों में संलिप्तता बढ़ी है. अब तो यह फ़र्क़ करना भी मुश्किल हो गया है कि कौन नेता है और कौन अपराधी. ऐसे माहौल में एक सवाल यह भी उठता है कि झारखंड जैसे राज्य का विकास और यहां की जनता का कल्याण आख़िर कौन करेगा, नेता या अपराधी? ज़ाहिर है, इन दोनों के बीच अब झारखंड की जनता भी शायद फ़र्क़ न कर पाए.

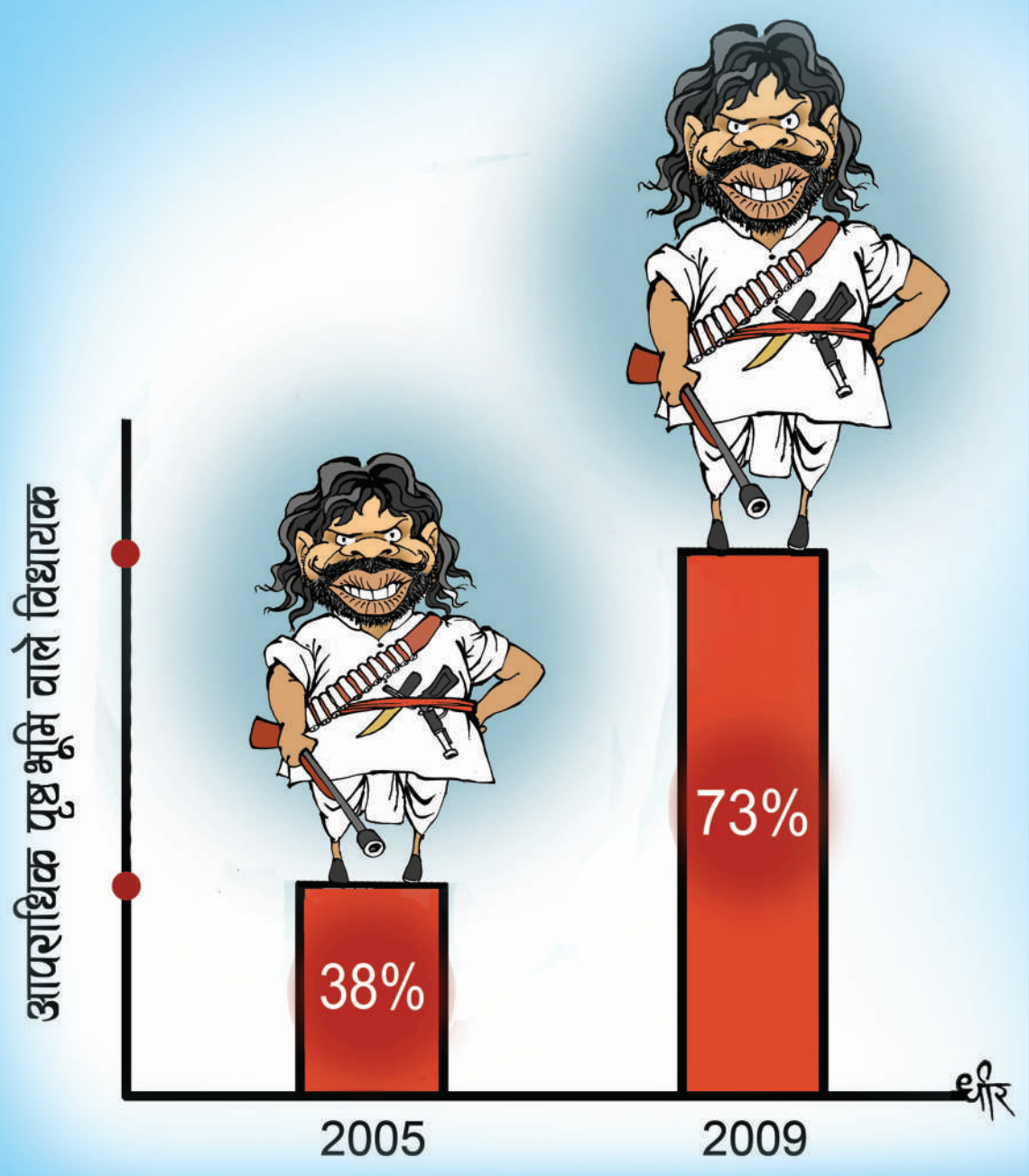

विधायकों की औसत संपत्ति

दल	विधायकों की संख्या	औसत संपत्ति
कांग्रेस	14	1,90,03,422
झाविमो	11	1,13,92,569
भाजपा	18	35,94,949
झामुमो	18	86,70,792
राजद	5	72,03,443
आजसू	5	44,98,503

(आंकड़े: एडीआर)

पैसा है तो जीत है

ऐसा नहीं है कि इस बार झारखंड चुनाव में सिर्फ़ बाहुबल का ही बोलबाला रहा. पिछले चुनाव की तुलना में इस बार विधानसभा में बैठनेवाले धनकुबेरों की संख्या भी कुछ ज़्यादा ही हैं.

2005 की विधानसभा में महज दो करोड़पति विधायक थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड 21 करोड़पति विधायक चुनावी बैतरणी पार कर विधानसभा पहुंच चुके हैं. झारखंड के नवनिर्वाचित विधायकों की औसत संपत्ति 91 लाख रुपये से भी ज़्यादा है. यानी यहां का लगभग हर एक विधायक करोड़पति है. पांच करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति के मामले में कांग्रेस गठबंधन सबसे आगे है. कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है. वह लगभग दस करोड़ रुपये की परिसंपत्ति के स्वामी हैं. झारखंड विकास मोर्चा के सत्येंद्र नाथ तिवारी के पास पांच करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति हैं. करोड़पति विधायकों की संख्या के मामले में कांग्रेस सबसे आगे है. झामुमो इस मामले में दूसरे नंबर पर है. बाबूलाल मरांडी की पार्टी भी करोड़पतियों की पार्टी कही जा सकती है. लेकिन यह देख कर किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी के खाते में सिर्फ़ एक ही करोड़पति विधायक का नाम दर्ज़ है. झारखंड चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उससे एक चीज तो साफ़ हो ही जाती है कि आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, आपके विधायक बनने के अवसर उतने ही बढ़ जाएंगे. इस बार झारखंड में आठ ऐसे लोगों ने विधायक की कुर्सी हासिल की है, जिनके पास दो करोड़ रुपये से ज़्यादा की परिसंपत्ति थी. ऐसे महज 11 लोग ही चुनाव जीत सके हैं, जिनके पास दस लाख से कम की परिसंपत्ति थी. इसके अलावा 30 विधायकों के पास 50 लाख से दो करोड़ रुपये के बीच की संपत्ति है, जबकि दस से 50 लाख के बीच की संपत्ति के स्वामी विधायकों की संख्या 32 है. एक बात और ग़ौर करने की है कि सिर्फ़ 23 उम्मीदवार ही ऐसे थे जिनकी संपत्ति दो करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि चुनावी मैदान में उतरे 512 उम्मीदवारों की परिसंपत्ति दस लाख रुपये से भी कम है.

लेकिन ऐसे उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत सबसे कम रहा. सिर्फ़ दो फ़ीसदी. यहां यह बताना भी ज़रूरी है 17 निर्वाचित विधायकों ने अपने हलफ़नामे में स्थायी खाता संख्या (पैन संख्या) का ज़िक्र ही नहीं किया है. ऐसे निर्वाचित सदस्य जिनकी परिसंपत्ति दस लाख रुपये से कम है, की संख्या महज़ 11 है. यानी बाकी विधायकों के पास कम से कम दस लाख रुपये से ज़्यादा की संपत्ति है. विधायकों द्वारा आयकर पैन का ख़ुलासा नहीं करना कई सवाल खड़े करता है. झारखंड में करोड़पतियों की बढ़ती संख्या से यह संदेह पैदा करता है कि क्या यह राज्य सच में ग़रीब है? इतना तो साफ़ है कि यहां के आमलोगों की चिंता किसी भी राजनेता को भी नहीं है, चाहे वे किसी भी दल से ताल्लुक क्यों नहीं रखते हों.

करोड़पति विधायक

दल	उम्मीदवारों की संख्या	करोड़पति विधायक	प्रतिशत
कांग्रेस	60	7	12%
झामुमो	78	6	8%
झाविमो	24	3	12%
झापा	36	1	3%
भाजपा	66	1	2%
राजद	56	1	2%
आजसू	53	1	2%
निर्दलीय	185	1	0.5%
कुल	558	21	

(2005 में महज़ दो विधायक करोड़पति थे)

(आंकड़े: एडीआर)

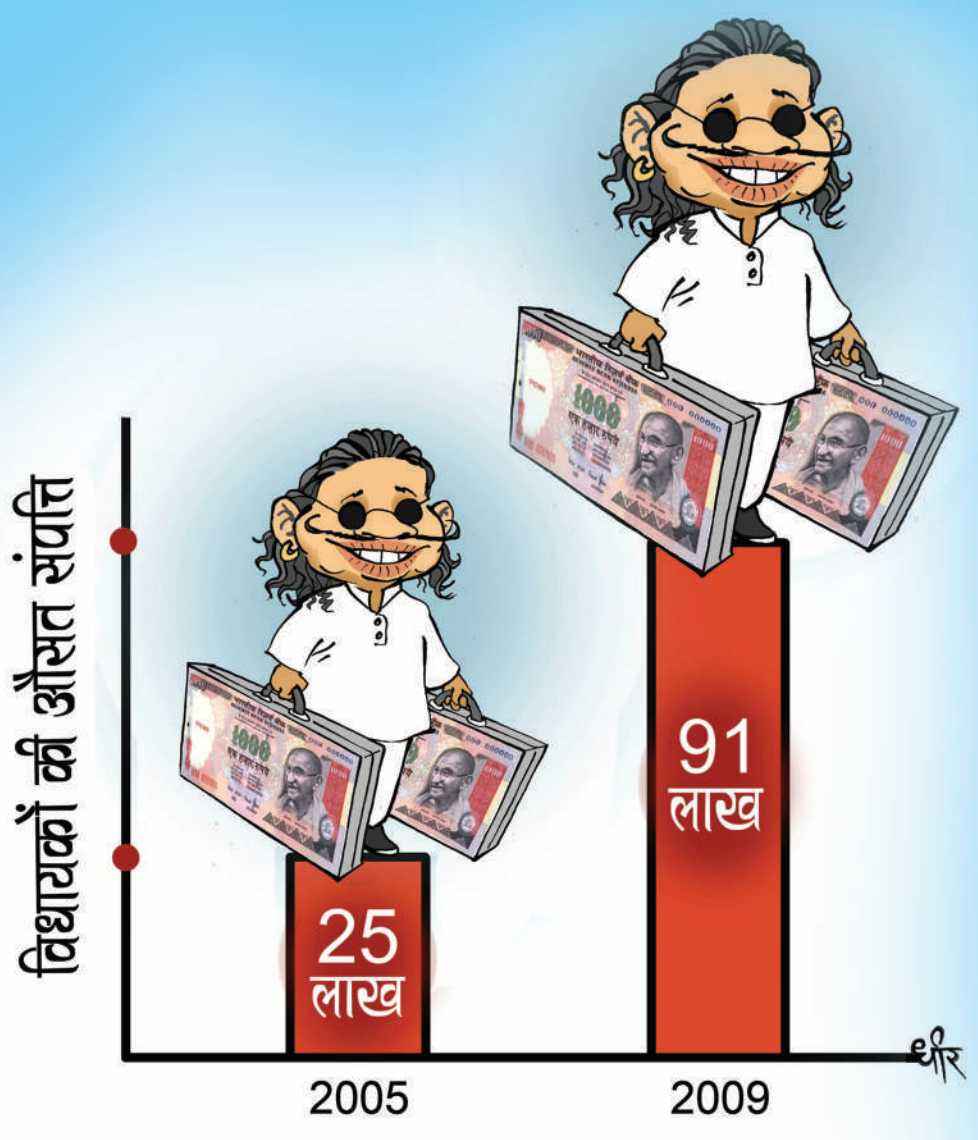

shashishekhar@chauthiduniya.com

जन सुनवाई के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की गरज से 12 दिन की पदयात्रा आयोजित की जानी थी, लेकिन हिटलरी तरीक़े से इस पर विराम लगा दिया गया.

जन सुनवाई का सामना क्यों ज़रूरी?

फोटो– प्रियंका बोरठ पुजारी

यातना की शिकार महिलाओं में से एक

गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार

आदियोग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नरसिंहन ने कभी नहीं चाहा कि केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम सात जनवरी की दंतेवाड़ा जन सुनवाई में हिस्सा लें. इस बात का गवाह है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा गया उनका वह पत्र, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से यह कहा कि गृहमंत्री जैसे अति विशिष्ट शख्स के दौरे से माओवादियों के ख़िलाफ़ जारी अभियान में रुकावट पैदा होगी. उनकी इस सतर्कता की वजह शायद यह भी हो सकती है कि वह इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशालय से सीधे रायपुर राजभवन पहुंचे हैं और अभी तक उसी पुराने मिजाज़ में हैं. लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया, जब किसी राज्यपाल ने केंद्रीय गृहमंत्री से राज्य का दौरा न करने को कहा हो. सनद रहे कि कोई दो माह पहले चिदंबरम ख़ुद ही कह चुके थे कि वह जन सुनवाई में शामिल हो सकते हैं.

दंतेवाड़ा में गांधीवादी कार्यकर्ता हिमांशु कुमार का उपवास गत 26 दिसंबर को शुरू हुआ था. उन्हें देश के विभिन्न जन संगठनों और अभियानों का समर्थन मिला. उपवास को आत्मावलोकन की प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि अब तक की उनकी कोशिशें आदिवासियों की मदद नहीं कर सकीं, इसलिए इस उपवास का मक़सद है कि बस्तर के हालात सामान्य हों, ख़ौफ़ एवं ज़ुल्मोसितम का दौर थमे, विस्थापन का बेक़ाबू ग्राफ रुके, आदिवासियों को इज़्ज़त और बराबरी के साथ जीने का अधिकार मिले. इसके लिए सरकार, लोग, संगठन, माओवादी एवं कंपनियां ख़ुद से सवाल करें कि जो हो रहा है, कितना उचित और न्यायसंगत है? सात जनवरी की जन सुनवाई हिमांशु कुमार और उनके संगठन वनवासी चेतना आश्रम की पहल से तय हुई थी. इसमें केंद्रीय गृहमंत्री के आने की संभावना से राज्य की रमन सिंह सरकार बेचैन हो उठी थी. न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी की तर्ज़ पर जन सुनवाई के आयोजन का रास्ता रोकने के लिए एक के बाद एक सरकारी रोड़ों और हथकंडों का इस्तेमाल किया गया. ताक़त की बेशर्म नुमाइश की गई. आर–पार की नौबत हो, शिक़ायत और फ़रियाद के तमाम दरवाज़े बंद हों तो हाथों में बंदूक़ आती है. या फिर अन्न त्याग का विकल्प सूझता है, जो आत्मघात नहीं, दबाव का अहिंसक हथियार होता है. ख़तरनाक मोड़ से गुज़र रहे हालात ने ही हिमांशु को उपवास का अप्रत्याशित फ़ैसला लेने के लिए मजबूर किया.

जन सुनवाई यानी जनता की आवाज़ का मंच और मौक़ा. लेकिन, मामला अगर पूंजीपतियों के हितों से जुड़ा हो तो जन सुनवाई नाटक में बदल दी जाती है. उड़ीसा और झारखंड की तरह छत्तीसगढ़ में भी इस नाटक के सफल मंचन का ठेका प्रशासन ने ले रखा है. परियोजना कहीं और की होती है और जन सुनवाई कहीं और होती है. प्रशासन सूत्रधार की भूमिका अदा करता है और कंपनियां सपना बेचते मसीहा की. ज़ाहिर है कि इसमें प्रभावित जनता का कोई रोल नहीं होता. जनता के वेश में लोग हांककर लाए जाते हैं, जो आख़िर में परियोजना के पक्ष में हंसी–ख़ुशी अपनी सहमति का ठप्पा लगा देते हैं और नाटक का सुखद अंत हो जाता है. मिसाल के तौर पर गत 12 अक्टूबर को जगदलपुर में हुए नाटक को लें. प्रेक्षागृह था बस्तर के कलेक्टर का कार्यालय. बहुत बड़ा इलाक़ा सुरक्षा के घेरे में था. लगभग 50–60 दर्शकों के सामने टाटा के प्रतिनिधि ने बताना शुरू किया कि एक सौ पच्चीस साल पहले जमशेदजी टाटा ने झारखंड के एक गांव को ख़ुशहाल बनाने का सपना देखा था और आज वह जमशेदपुर है. वह गांव तो बस्तर से भी बदहाल था. इस तरह स्वप्न लोक की सैर हुई और परियोजना की पीठ थपथपाई गई कि उसकी तकनीक पूरी दुनिया में अव्वल होगी. लेकिन हां, यह आकलन रिपोर्ट पेश नहीं की गई कि इस्पात संयंत्र से पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा और उसे रोकने या कम करने का तरीक़ा क्या होगा. क्यों? इसलिए कि उसे समझ पाना दर्शकों के लिए टेढ़ी खीर होगा. हालांकि जन सुनवाई इसी रिपोर्ट के आधार पर होनी थी. अंत में कलेक्टर ने पूछा कि किसी को कोई आपत्ति? किसी ने हाथ नहीं उठाया. आख़िर उठता भी क्यों? जिनका हाथ उठ सकता था, उनका तो प्रवेश ही वर्जित था.

मालूम हो कि दस हज़ार करोड़ रुपये की इस परियोजना के लिए टाटा को ज़िले के लोहांडीगुंडा ब्लॉक के 11 गांवों की पांच हज़ार एकड़ ज़मीन चाहिए. साथ ही संयंत्र के लिए सबरी एवं इंद्रावती के पानी का अंधाधुंध दोहन और उसे प्रदूषित करने का अधिकार चाहिए. इस परियोजना के लिए 2005 में राज्य सरकार के साथ करार हो चुका है. दबाव, तिकड़म और प्रलोभन से कोई दो तिहाई ज़मीन भी अधिग्रहीत की जा चुकी है, लेकिन भारी विरोध के चलते परियोजना फ़ाइलों से बाहर नहीं आ सकी है. सरकार नहीं चाहती कि किसी जन सुनवाई की उसकी रची पटकथा में कोई तब्दीली हो कि वह सचमुच जन सुनवाई में बदल जाए. तब, ज़ाहिर है कि भूमिकाएं बदल जाएंगी. सरकार और कंपनी ख़लनायक नज़र आएंगे. विकास का दावा और माओवाद का हौव्वा फुस्स हो जाएगा. माओवादी हिंसा पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन उससे पहले और सबसे ज़्यादा पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों, सलवाजुडूम एवं एसपीओज के ज़ोर–ज़ुल्म पर गुस्सा फूटेगा. सरकार जानती है कि ग़ैर सरकारी जन सुनवाई होगी तो विकास का फ़रेबी लबादा उतरेगा और माओवादी ख़तरे के इश्तहार के पीछे का यह नज़ारा सामने आ जाएगा कि किस तरह मछलियां बूंद–बूंद पानी के लिए तड़प रही हैं और बहुराष्ट्रीय मगरमच्छ बेधड़क तालाब पर तालाब गटक रहे हैं या अपना नंबर आने के इंतज़ार में हैं. यह कंपनियों की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा.

जन सुनवाई के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की गरज से 12 दिन की पदयात्रा आयोजित की जानी थी, लेकिन हिटलरी तरीक़े से इस पर विराम लगा दिया गया. ऐसी फिजां बनाने की कोशिश की गई, गोया यह आयोजन माओवादियों के समर्थन में आयोजित किया जा रहा हो. इसके विरोध में सलवाजुडूम पार्ट–2 उर्फ़ दंतेश्वरी आदिवासी स्वाभिमान मंच को उतार दिया गया. पदयात्रा में शामिल होने के लिए जा रहे देश के 10 राज्यों की महिला प्रतिनिधियों के जत्थे को रोक दिया गया और उस पर आतंक और बदसलूकी का डंडा चलाया गया. वनवासी चेतना आश्रम से जुड़े आदिवासी कार्यकर्ता कोपा कुंजाम को छह माह पहले हुई एक एसपीओ की हत्या के मामले से जोड़कर जेल पहुंचा दिया गया. 14 दिसंबर को, जिस दिन से पदयात्रा शुरू होनी थी, हिमांशु कुमार की नज़रबंदी कर दी गई. सरकारी आतंक और हिंसा का यह ताज़ा क़िस्सा छत्तीसगढ़ और देश के बाहर तक पहुंचा. लोकतंत्र और मानव अधिकारों के पैरोकारों ने इसकी कड़ी निंदा की. नई दिल्ली से लेकर लखनऊ, मुंबई, बंगलूर, चेन्नई, कलकत्ता तक से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन चिकने घड़ों पर पानी कहां ठहरता है. राज्य सरकार हक़ और इंसाफ़ की आवाज़ को कुचल देने की जिद पर आमादा है. ठीक वैसे ही, जैसे राज्य सरकार पर तब भी कोई असर नहीं पड़ा था, जब डॉ. विनायक सेन की रिहाई के लिए पूरी दुनिया से मांग उठ रही थी कि उनकी क़ैद ज़म्हूरियत की क़ैद है.

दो साल पहले एसपीओज ने दंतेवाड़ा से सौ किलोमीटर दूर सुकुमा ब्लॉक के समसेट्टी गांव की चार लड़कियों के साथ बलात्कार किया था. वनवासी चेतना आश्रम ने उनमें हिम्मत और हौसला भरने का काम किया और मामला अदालत तक पहुंचा. गत 16 दिसंबर को उन्हीं बलात्कारियों ने इन आदिवासी लड़कियों को पीटा और उन्हें सादे काग़ज़ों पर अपने अंगूठे का निशान लगाने के लिए मजबूर किया. इसकी शिक़ायत आला अफ़सरों से की गई. असर यह हुआ कि एक बार फिर इन लड़कियों पर गाज़ गिरी. उन्हें पकड़ कर डोरनापाल थाने ले जाया गया, जहां उन्हें पांच दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया. यह कार्रवाई इसलिए की गई, ताकि उन्हें ज़ुबान न खोलने की हिदायत क़ायदे से दी जा सके. यातनाओं के चाबुक से उन्हें यह सबक याद कराया गया कि अगर वे धड़ पर अपना सिर सलामत चाहती हैं तो अपने साथ हुए बलात्कार को भूल जाएं. जैसे–तैसे 24 दिसंबर को इन लड़कियों को रिहाई मिली. तबसे वे सलवाजुडूम की सख्त निगरानी में हैं और उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने की इजाज़त नहीं है. उधर बीते 25 सितंबर को समसेट्टी के बगल में स्थित परिया एवं बगरीगुडा गांव से पांच आदिवासियों को एसपीओज पूछताछ करने के बहाने उठा ले गए. सब जानते हैं कि एसपीओज अथवा सलवाजुडूम के कार्यकर्ता इसी तरह आदिवासियों को अपने साथ ले जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्हें माओवादी बताकर जेल पहुंचा दिया गया या फ़र्ज़ी मुठभेड़ दिखाकर दुनिया से ही विदा कर दिया गया. कोपा कुंजाम को भी पूछताछ के नाम पर ले जाया गया था. अनहोनी का अंदेशा था, इसलिए वकील होने के नाते अलबन टोप्पो भी साथ हो लिए. अंदेशा सही निकला. दोनों की जमकर पिटाई हुई. कोपा को जेल रवाना कर दिया गया. अलबन के साथ हुए सलूक पर तमाम वकीलों ने अपनी सख्त नाराज़गी फ़ौरन दर्ज़ की और तभी हवालात से उनकी रिहाई हो सकी. लेकिन, राज्यपाल की निगाह सरकारी दमन पर नहीं टिकती. उन्हें हत्या, बलात्कार, आगजनी और विस्थापन का दंश झेल रहे आदिवासियों की आह सुनाई नहीं देती. वह इस मांग पर ग़ौर फरमाना नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा की दुहाई देकर लागू किए गए काले क़ानून के डंडे पर रोक लगनी चाहिए, जिसके तहत एक हज़ार से अधिक लोग जेल में हैं और उनमें ज़्यादातर दिहाड़ी मज़दूर, खोमचे–रेहड़ी वाले, दर्ज़ी–धोबी–नाई जैसे मामूली लोग हैं.

फोटो– प्रभात पाण्डेय

बीते 6 अक्टूबर को रायपुर में विस्थापन के ख़िलाफ़ राज्य के कोने–कोने से हज़ारों लोग जुटे थे. उस दिन उन्हें दुखियारों के प्रतिनिधियों से मिलने की फ़ुर्सत नहीं मिली. बाद में जब मिले भी तो उन्होंने विस्थापन के सच को ही सिरे से नकार दिया. उन्होंने तालठोंकू दावा किया कि मुआवज़ा दिए और सहमति लिए बग़ैर कहीं भी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है. उनकी सलाह थी कि जन सुनवाई कहीं भी रखी जाए, प्रभावित लोगों को उसमें ज़रूर जाना चाहिए. कौन रोकता है उन्हें? तो, राजभवन के ख्याल से गांव का मौसम गुलाबी है. यह होहल्ला झूठा है कि पतझड़ का अंधड़ तेज़–दर–तेज़ होता जा रहा है. ख़ुशहाली की बारात में माओवादी खलल डाल रहे हैं. सरकार उन्हें देख लेने के नेक काम पर जुटी है.

दरअसल, राज्यपाल समझना ही नहीं चाहते कि मामला शीशे की तरह साफ़ है. कंपनियों को क़ुदरत की बेशक़ीमती नेमतों की खुली लूट का न्यौता बांटा जा रहा है. ये वे इलाक़े हैं, जहां आदिवासी बसते हैं और वे लोहा नहीं, अनाज चाहते हैं. ऐसा विकास नहीं चाहते, जिसकी क़ीमत उन्हें विनाश और विस्थापन से चुकानी पड़े. सीधी उंगली से घी नहीं निकल सकता, इसलिए माओवादियों के सफ़ाए के नाम पर आदिवासियों के सफ़ाए का अभियान है. उन्हें सताया और खदेड़ा जा रहा है. आदिवासियों को आदिवासियों से भिड़ाया जा रहा है. विरोध या प्रतिरोध की हर आवाज़ को बेरहमी से कुचला जा रहा है. आदिवासी इलाक़ों को छावनी में बदला जा रहा है. सच चीख रहा है कि छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक की जलती हुई पट्टी कोई लाल गलियारा नहीं, दरअसल सरकार द्वारा कंपनियों के साथ किए गए क़रार का गलियारा है.

भले ही माओवादियों के ख़िलाफ़ मोर्चा सख्त हो रहा है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कई बार माओवादियों को देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बता चुके हैं, लेकिन इधर गृहमंत्री पी चिदंबरम का सुर ज़रूर थोड़ा ढीला हुआ है. आख़िरकार, अमन–चैन की बहाली का रास्ता संवाद और संवेदनशीलता से होकर गुज़रता है, पगलाई ताक़त से नहीं.

feedback@chauthiduniya.com

सरकार इतना क्यों डरती है ?

विगत 17 मई को वनवासी चेतना आश्रम के परिसर को बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था. तब से किराए के मकान में हिमांशु कुमार का आशियाना था. इधर मकान मालिक पर प्रशासन का दबाव था कि वह अपने मकान से उन्हें बाहर कर दे. आख़िरकार, उपवास के दिन, 31 दिसंबर को उन्हें एक सप्ताह के भीतर मकान खाली कर देने की नोटिस मिल गई. प्रशासन ने ताक़ीद कर दी है कि उन्हें या वनवासी चेतना आश्रम को आश्रय देने की ज़ुर्रत कोई न करे, न कोई अपनी जगह उन्हें बेचे या किराए पर दे. दंतेवाड़ा में हिमांशु कुमार या वनवासी चेतना आश्रम की मौजूदगी से इतना डरती है सरकार.

लोक स्वास्थ्य विभाग का अमला निर्मम और क्रूर हो चुका है. भोपाल में एक वर्ष पूर्व काटजू अस्पताल में एक गर्भवती महिला को दाख़िल नहीं किया गया, नतीजतन उसे अस्पताल के गेट पर ही प्रसव कराना पड़ा.

दिल्ली, 11 जनवरी–17 जनवरी 2010 चौथी दुनिया

आंकड़ेबाज़ी नहीं, विकास कीजिए

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह जनपद सीहोर का एक गांव हैं करंजखेड़ा. यह राजधानी से 50 किलोमीटर और ज़िला मुख्यालय से केवल 17 किलोमीटर दूर है, लेकिन किसी पक्की सड़क से इस गांव का कोई नाता नहीं है. गांव स्थित नदी पर थोड़ी दूर खजूरियाकलां में एक बांध बनाकर पानी रोका गया है, जिसे पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

संध्या पांडे

किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़े हमेशा विकास की एक अकल्पनीय कहानी होते हैं. इनमें सत्यता का प्रतिशत यह तय करता है कि सरकार की नीयत नागरिकों के प्रति कितनी साफ़ है. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करोड़ों रुपये के विज्ञापनों के माध्यम से अब तक जारी किए गए आंकड़े ज़मीनी हक़ीक़त से कहीं दूर हैं. भाजपा इस सरकारी प्रचार को यदि सही मानती है तो यह भविष्य के अंधेरे की ओर एक संकेत साबित हो सकता है. केवल सपने दिखाने और झूठे वायदे करने से राष्ट्र–समाज का विकास संभव नहीं है और वह भी उस समय, जबकि सरकारी अमला अपने निजी हित साधने में लगा हो.

राज्य में सरकारी प्रचार तंत्र ने महीनों तक शोर मचाया कि हर रोज 8 किलोमीटर सड़क बन रही है. पिछले पांच वर्षों में जितनी सड़कें बनीं, उतनी पिछले 50 वर्षों में नहीं बनीं. लेकिन, राजधानी भोपाल के आसपास कई गांव ऐसे हैं, जहां सड़क का नामोनिशान तक नहीं है. कुछ गांवों में तो आज भी आदि मानव सभ्यता के नज़ारे दिखाई देते हैं.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह जनपद सीहोर का एक गांव हैं करंजखेड़ा. यह राजधानी से 50 किलोमीटर और जिला मुख्यालय से केवल 17 किलोमीटर दूर है, लेकिन किसी पक्की सड़क से इस गांव का कोई नाता नहीं है. गांव स्थित नदी पर थोड़ी दूर खजूरियाकलां में एक बंधान बनाकर पानी रोका गया है, जिसे पीने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, बंधान बन जाने से करंजखेड़ा में आवागमन सुविधा अवरुद्ध हो गई है. मुख्य मार्ग की ओर बंधान का पानी 8 महीने भरा रहता है और ग्रामीणों को रोज़ उसी पानी में से होकर सड़क पर जाना पड़ता है. बच्चे पानी में भीगने के बाद ही स्कूल पहुंच पाते हैं. मुख्यमंत्री, सांसद एवं विधायक सभी को इस बात की जानकारी है, लेकिन किसी ने पुलिया अथवा रपटा बनवाने की ज़रूरत नहीं समझी. यह केवल एक गांव की व्यथा–कथा है, लेकिन ऐसे 20 से ज्यादा गांव भोपाल और मुख्यमंत्री के गृह ज़िले में हैं, जहां छोटे–छोटे निर्माणकार्य न होने के कारण जनजीवन कष्टमय बना हुआ है. भोपाल और सीमावर्ती कई गांवों में पक्की सड़कें नहीं हैं. नागरा बस स्टैंड से 7 किलोमीटर दूर स्थित घाटखेड़ी, भोपाल से 15 किलोमीटर दूर खेजड़ादेव एवं ताराशिवनिया, 16 किलोमीटर दूर कुराना एवं पृथ्वीपुरा, भोपाल से 20 किलोमीटर दूर ताराशिवनिया से झापरिया और सूखानिपानिया को जोड़ने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है. इसी तरह कांसीबरखेड़ा, सिगोनी, देवपुर और शाहपुर जैसे गांव भी सड़क की सुविधा से वंचित हैं.

ग्रामीण इलाक़ों मे सड़कें तीन–चार साल के अंतराल में बनाई जाती हैं अथवा इनकी मरम्मत होती है. लेकिन, राजमार्गों और कुछ मुख्य मार्गों को चमकाने के सरकारी अभियान के चलते ग्रामीण इलाक़ों की सड़कों की हालत बेहद ख़राब है. गांवों में सड़क निर्माण के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश को भी भरपूर पैसा मिलता है, लेकिन 9 वर्षों में 77 हज़ार किलोमीटर सड़क निर्माण के आंकड़े काग़ज़ों में दर्ज़ हो जाने के बाद भी हक़ीक़त यह है कि इस राज्य में 20 हज़ार गांव सड़क सुविधा से आज भी पूरी तरह वंचित हैं. जानकारी के अनुसार, 500 से 999 तक की आबादी वाले 7131 और 250 से 499 तक की आबादी वाले 1529 गांवों में सड़क सुविधा नहीं है. इसी तरह 250 से कम आबादी वाले 8171 गांवों में सड़कों का नामोनिशान तक नहीं है. उल्लेखनीय है कि 500 से कम आबादी वाले ज़्यादातर गांव आदिवासी बहुल हैं. इन गांवों में कभीकभार सरकारी जीपें और मोटरसाइकिलें चलती हैं. नेता चुनाव के समय प्रचार के लिए आते हैं और फिर इन्हें भूल जाते हैं. अभी भी इन गांवों में परिवहन के लिए बैलगाड़ी सबसे तेज़ वाहन माना जाता है. शिक्षक, पंचायत सचिव, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और अन्य कर्मचारी भी यहां आने–जाने के लिए बैलगाड़ी का ही सहारा लेते हैं.

राज्य के लोक स्वास्थ्य विभाग का अमला निर्मम और क्रूर हो चुका है. राजधानी भोपाल में एक वर्ष पूर्व काटजू अस्पताल में एक गर्भवती महिला को दाख़िल नहीं किया गया, नतीजतन उसे अस्पताल के गेट पर ही प्रसव कराना पड़ा. जब हंगामा हुआ तो कुछ डॉक्टरों पर कार्यवाही की गई, लेकिन जल्दी ही मामला ठंडा पड़ गया. इसी तरह गंजबसौदा के पास स्थित एक गांव में रहने वाली एक महिला को प्रसव के लिए गंजबसौदा से विदिशा भेजा गया और जब वहां भी सरकारी अस्पताल में दाख़िला नहीं मिला तो घर लौटते समय उसका प्रसव रेलगाड़ी में ही हो गया. जयप्रकाश ज़िला अस्पताल में गत 30 दिसंबर को एक महिला ने अस्पताल के बरामदे में बच्चे को जन्म दिया. ग्राम कालापानी निवासी रामवती बाई नामक यह महिला प्रसव के लिए अस्पताल आई थी, लेकिन जांच और भर्ती में टालमटोल के दौरान प्रसव पीड़ा से कराहती महिला ने बरामदे में ही बच्चे को जन्म दे दिया. बाद में वहां पहुंचे एक डॉक्टर ने महिला को अस्पताल में दाख़िल कराया. भोपाल के सरकारी अस्पतालों में ग़रीबों को मुफ़्त दवा न मिलने, डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के ग़ायब रहने जैसी कई समस्याएं हैं. भ्रष्टाचार, घपलों–घोटालों और डॉक्टरों–कर्मचारियों के लालच के चलते सरकारी अस्पताल अपनी साख खो चुके हैं.

मुख्यमंत्री, मंत्री एवं सरकारी अधिकारी अपना और परिवार का इलाज निजी अस्पतालों में कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी अस्पतालों में मनमानी चरम पर है. पिछले दिनों भोपाल पुलिस ने निशांतपुरा में एक फ़र्ज़ी दवा फैक्ट्री का पर्दाफ़ाश किया. 12वीं तक पढ़े अनिल अग्रवाल नामक शख्स ने हाउसिंग बोर्ड कालोनी के दो छोटे कमरों में शक्कर, गुड़ के शीरे एवं आरारोट के घोल से कई प्रकार की नकली दवाइयां बनाकर भोपाल और आसपास के सरकारी–ग़ैर सरकारी अस्पतालों, डॉक्टरों और दुकानों में खपा दी. मालूम हो कि राज्य सरकार का अपना ड्रग्स कंट्रोलर विभाग है, ज़िला स्तर पर ड्रग्स इंस्पेक्टर तैनात हैं और ज़िला अस्पतालों में फार्मेसिस्ट भी हैं, बावजूद इसके राजधानी में नकली दवाइयों का कारोबार चल रहा है. सरकारी अस्पतालों में घटिया और स्तरहीन दवाइयां खपाई जाती हैं. कभी–कभी तो एक्सपायर्ड दवाएं भी ख़रीद ली जाती हैं. जब–तब ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं, मीडिया में कुछ दिनों तक शोर मचता है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण घपले–घोटालों का खेल फिर शुरू हो जाता है. हमीदिया अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉ. डी के वर्मा कहते हैं कि बाज़ार नकली दवाओं से पटा पड़ा है, जिनके सेवन से लोग कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी के शिकार हो सकते हैं. प्रशासन को इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए. डॉक्टर भी मरीज़ों द्वारा ख़रीदी गई दवा को देखने के बाद ही उन्हें उसके सेवन के बारे में बताएं. यदि डॉक्टर दवाइयों का निरीक्षण करेंगे तो नकली दवाइयों पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है.

भारतीय जनता पार्टी ने 2003 और फिर 2008 के विधानसभा चुनाव में जारी अपने घोषणापत्र में आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उनकी उपचार सुविधा के विस्तार–विकास के वायदे किए थे. साथ ही आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त डॉक्टरों की भर्ती के भी वायदे किए गए थे, लेकिन उक्त सारे वायदे चुनाव के बाद भुला दिए गए. नतीजा यह हुआ कि इन वायदों पर भरोसा करके राज्य के हज़ारों युवा इन चिकित्सा पद्धतियों की पढ़ाई पर लाखों रुपये ख़र्च करने के बाद भी दर–दर भटक रहे हैं. राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग की अनदेखी से आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा का निजीकरण होना तय माना जा रहा है. सात आयुर्वेदिक कॉलेजों में से छह की मान्यता न होने के कारण पिछले दो शिक्षा सत्र शून्य घोषित हो चुके हैं. नए सत्र के लिए भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद भी मान्यता संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं. जबकि आगामी सत्र के लिए सीसीआईएम की टीम आयुर्वेदिक चिकित्सा कॉलेजों के निरीक्षण के लिए फिर आने वाली है. जबलपुर सहित प्रदेश के छह आयुर्वेदिक कॉलेजों, जिनमें रीवा, इंदौर, ग्वालियर, बुरहानपुर और उज्जैन आदि शामिल हैं, की मान्यता समाप्त कर दी गई है. अब उक्त कॉलेज नया सत्र शुरू नहीं कर सकते. प्रदेश में सात शासकीय आयुर्वेद कॉलेजों के मुक़ाबले सात निजी आयुर्वेद कॉलेज संचालित हैं. सातों आयुर्वेद कॉलेजों में प्रोफेसरों के कुल 88 पद हैं, जिनमें 63 रिक्त हैं. रीडर के कुल स्वीकृत 108 पदों में से 46 रिक्त हैं. यही नहीं, व्याख्याताओं के भी 123 स्वीकृत पदों में से 57 रिक्त हैं.

feedback@chauthiduniya.com

वन्यजीव तस्करों ने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठजोड़ से जंगलों पर अवैध क़ब्ज़े करके अपने खेल को आसानी से अंजाम देने का रास्ता निकाल लिया है.

तस्करों के निशाने पर बेज़ुबान

सुरेंद्र अग्निहोत्री

चांदी के चंद चमकते सिक्कों ने दुर्लभप्राय वन्यजीवों का जीवन संकट में डाल दिया है. येन केन प्रकारेण पकड़कर या मारकर उन्हें विदेशों में बेचा जा रहा है. तस्करों के हौसले बुलंद हैं. वे अपनी तिज़ोरी भरने की ख़ातिर सारी इंसानियत कहीं दफन कर चुके हैं. अफ़सोस तो इस बात का है कि शासन-प्रशासन सब कुछ जानते-समझते हुए भी मूकदर्शक की भूमिका में है.

उत्तर प्रदेश में इन दिनों वन्यजीव तस्करों की तूती बोल रही है. वन भूमि पर अवैध क़ब्ज़े किए जा रहे हैं. जंगल सिमट रहे हैं तो जानवर शहर की ओर निकल आने को बाध्य हैं. और, तस्कर यही चाहते हैं कि जानवर कब उनकी निगाह में आएं और कब उन्हें निशाना बनाया जाए. शासन और प्रशासन को इस संदर्भ में माकूल जानकारी है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा है या फिर करना ही नहीं चाहता है. ऐसे में वन्यजीव तस्करों और जंगलों पर अवैध क़ब्ज़ा करके उसका व्यवसायिक इस्तेमाल करने वाले दबंगों के हौसले बुलंद हैं. देश के अन्य हिस्सों से भी इसी तरह की ख़बरें आ रही हैं. विभिन्न चिड़ियाघरों पर तस्करों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है. वहां पर घुसपैठ करके जानवरों की चोरी की जा रही है. कोलकाता प्रकरण इसका ताज़ा प्रमाण है.

वन्यजीव तस्करों ने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठजोड़ से जंगलों पर अवैध क़ब्ज़े करके अपने खेल को आसानी से अंजाम देने का रास्ता निकाल लिया है. पूर्वी देशों में वन्यजीवों के व्यंजन और उनके अंगों से बनने वाली दवाइयों के चलते देश में कुछ ख़ास प्रजातियां ख़तरे में आ गई हैं. कछुआ, मोर, शेर, सल्लू सांप, अजगर, कोबरा, गंगा डॉलफिन, सांडा, जंगली कबूतर, किंगफिशर, सारस, साईबेरियाई पक्षी और जल मुर्गी आदि तस्करों के निशाने पर हैं. छोटे तोते की भी तस्करी में तेज़ी आई है. भारतीय वन्यजीवों की तस्करी करने वाले इतने हाईटेक हो गए है कि वे इंटरनेट के ज़रिए देश भर में कहीं भी किसी भी समय सौदा कर लेते हैं और इसकी भनक तक किसी को नहीं लगती. इसका खुलासा क्राइम ब्रांच ने किया है. हालांकि इस तरह की ख़रीद-फरोख्त पर कड़ा प्रतिबंध है, लेकिन इसके बाद भी चोरी-छुपे यह कारोबार जारी है. वन्यजीवों की तस्करी विदेशों तक की जाती है और इसके लिए मेरठ एवं लखनऊ काफ़ी चर्चित हैं. पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने छापा मारकर साइबर वन्यजीव तस्करी का खुलासा किया था. इस छापेमारी में मेरठ के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया था, जिसके पास से मैना, मोर के बच्चों, कोयल और छोटी चिड़ियों को मुक्त कराया गया था. हस्तिनापुर क्षेत्र में भी हिरन, मोर और घड़ियाल के शिकार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन वन्यजीव संरक्षण अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं. मखदूमपुर क्षेत्र के गंगा घाट पर बड़ी संख्या में घड़ियाल छोड़े गए थे. इन्हें वहां छोड़ने का उद्देश्य यह था कि अवैध रूप से होने वाला मछलियों का शिकार रुक जाए और मानव अस्थियों के विसर्जन से गंगा में होने वाली गंदगी घड़ियालों की मदद से साफ़ की जा सके. अगस्त माह में सैन्य क्षेत्र में चार हिरन मिल चुके हैं. उक्त हिरन कहां से और कैसे आए, किसी को कुछ पता नहीं. मेरठ के सोतीगंज में रोज़ाना भारतीय एवं विदेशी चिड़ियों, तोता, कबूतर, छोटी चिड़िया, गौरैया और कोयल आदि की बिक्री होती है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. वन्यजीव संरक्षण अधिकारियों का कहना है कि विदेशी चिड़ियों को बेचने की अनुमति है, लेकिन भारतीय पक्षियों की नहीं.

नेपाल के सीमावर्ती बहराइच ज़िले में पक्षियों की तस्करी का मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने इस संबंध में आधा दर्ज़न लोगों को गिरफ़्तार किया है. इनके पास से 400 तोते बरामद हुए हैं, जिन्हें वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है. यह तोते ज़िले के जंगलों से पकड़े गए थे. विशेश्वरगंज थानाध्यक्ष श्रीराम ने बताया कि बहराइच नगर के चांदपुरा निवासी इंद्रेश और मूर्तिहा थाना क्षेत्र के ककरहा निवासी एक अन्य व्यक्ति इन तोतों को लेकर बिहार जा रहे थे. इनके साथ अली हसन, छोटकन्ने पुत्र अली अहमद, मंगरू पुत्र यूसुफ, मुन्ना पुत्र ईसा, अनीस अहमद पुत्र मुईद अहमद को भी गिरफ़्तार किया गया है. इनके तार अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोह से जुड़े हैं. मिश्रिख (सीतापुर) में पुलिस ने सांप बरामद किए. पुलिस ने तीन लोगों को तीन दोमुंहे सांपों, एक राइफल और कुछ अन्य सामान के साथ गिरफ़्तार किया. उक्त बरामदगी परसौली चौराहे पर सफारी गाड़ी एचआर-51वाई 1121 से की गई. गिरफ़्तार किए गए लोगों में वाहन चालक सत्यवीर सिंह पुत्र राजेंद्र त्यागी निवासी दलेलपुर जनपद फरीदाबाद, कुंवरपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी शांति कालोनी फरीदाबाद और इंद्रपाल सिंह उर्फ़ पप्पू पुत्र शिवदत्त सिंह निवासी अहतयाद सराय ज़िला बुलंदशहर हैं. जामा तलाशी के दौरान पुलिस को नगदी, मोबाइल और अन्य सामान भी मिला है. पकड़े गए लोगों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9/51 और भारतीय दंड संहिता की धारा 41/411 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज़ किया गया है.

सिद्धार्थनगर जनपद का दक्षांचल कछार क्षेत्र मोरों का अभयारण्य माना जाता है. कछार के लगभग 1500 गांवों के बीच नदियों और झाड़ियों के आसपास हज़ारों की संख्या में राष्ट्रीय पक्षी मोर विचरण करते हैं. पैसों के लालच में कुछ लोग उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं. वन विभाग की अनदेखी और पंख एवं नाख़ूनों की अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ती मांग के चलते मोरों के ऊपर ख़तरा मंडराने लगा है. मुज़फ़्फ़रनगर के खतौली, इटावा जनपद से निकलने वाली यमुना और चंबल नदी आदि क्षेत्र में इन दिनों कछुओं की तस्करी जोरों पर चल रही है. पिछले दिनों कानपुर में एक व्यक्ति को चार बोरों में कछुओं के बच्चे ले जाते हुए पकड़ा गया था. तस्कर बच्चों के माध्यम से वन्यजीवों को नदियों से पकड़ कर बाज़ारों में चोरी-छिपे बेच रहे हैं. राजधानी लखनऊ के चौक क्षेत्र में लगने वाले बाज़ार में अनेक दुर्लभ क़िस्म के पक्षी खुलेआम बिकते हैं. लखनऊ में एक ऐसा गिरोह है, जो ऑर्डर पर गंगा डॉलफिन से लेकर घड़ियाल और हाथी दांत आदि उपलब्ध करा रहा है.

तस्करी के खेल में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नेपाल और चीन की 800 किलोमीटर लंबी खुली सीमारेखा वरदान साबित हो रही है. तस्कर नेपाल से चीन के रास्ते अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में वन्यजीवों को बेचकर मालामाल हो रहे हैं. तस्करों ने चिड़ियाघरों के अंदर घुसपैठ के ज़रिए मनचाहे जानवर चोरी करवा कर अथवा उन्हें मौत की नींद सुलाकर उनके अंगों के व्यापार की ख़तरनाक साज़िश शुरू की है. कोलकाता के चिड़ियाघर से बहुमूल्य ब्राजीलियाई बंदरों की चोरी सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है. पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोपीय देशों में सक्रिय तस्करों की निगाह अब भारत के चिड़ियाघरों पर आ टिकी है. कोलकाता में कछुआ, कई तरह के पक्षियों, वन्यजीवों की हड्डियों और उनके अंगों की तस्करी की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन उनका दायरा स्थानीय तस्करों तक सीमित माना जाता रहा है. ब्राजीलियाई बंदरों की चोरी से साफ़ हो गया है कि तस्करों का नेटवर्क जापान, मलेशिया आदि के साथ ही इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका तक फैल चुका है.

अगस्त के मध्य में कोलकाता चिड़ियाघर में पिंजड़ा काटकर आठ ब्राजीलियाई बंदरों (मरमोसेट) को चुरा लिया गया. इनमें तीन वयस्क नर, तीन वयस्क मादा और दो शिशु शामिल थे. इनकी क़ीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तीन हज़ार डॉलर प्रति जोड़ा और भारतीय बाज़ार में कम से कम सवा लाख रुपये जोड़ा आंकी गई है. मरमोसेट के दिमाग़ से बने व्यंजन चीन और मलेशिया में बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण अमेरिका की दवा बनाने वाली कंपनियां शोध कार्य में कर रही हैं. कोलकाता पुलिस की जांच में इन बंदरों के बारे में कोई सुराग़ नहीं लग सका है. वन्यजीव प्रेमी संगठनों का कहना है कि बग़ैर मिलीभगत के मूल्यवान जीवों की इस क़दर चोरी नहीं हो सकती. दो हफ़्ते पहले मुंबई हवाई अड्डे पर एक थाई नागरिक को गिरफ़्तार कर उसके क़ब्ज़े से पांच बंदर बरामद किए गए थे. उसने बंदरों को बक्से में पैक कर रखा था. तीन बंदर मर चुके थे. थाई नागरिक कहीं बाहर से आया था. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसायटी ऑफ इंडिया की संस्थापक बेलिंडा राइट के अनुसार, मुंबई की बरामदगी का कोलकाता की घटना से कोई संबंध ज़रूर हो सकता है. इस प्रजाति के बंदरों की यूरोप के तस्करों में काफ़ी मांग है. इंग्लैंड के चिड़ियाघरों से अक्सर दर्ज़नों की संख्या में ऐसे बंदरों की चोरी की ख़बरें आती हैं. इसी साल जुलाई में दक्षिणी लंदन के चिड़ियाघर में चोरी की घटना हुई थी. पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में ऐसे बंदरों के ख़रीददार बहुत हैं.

पश्चिम बंगाल के प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट अतनुराहा के अनुसार, कोलकाता चिड़ियाघर से चोरी में अंतरराष्ट्रीय तस्करों का हाथ है. यहां की चोरी विश्व भर में हुई कुछ बड़ी चोरियों से मेल खाती है. अगस्त 2004 में स्कॉटलैंड के ओबान जूलॉज़िकल वर्ल्ड से 16 बंदर चुराए गए थे. जून 2006 में पूर्वी ससेंक्स प्रांत से पांच मरमोसेट, उसी दौरान इंग्लैंड के एक्सूमर चिड़ियाघर से 11 मरमोसेट और जून 2007 में अमेरिका के सेवियरचिले से कई मरमोसेट चुराए गए थे. वन्यजीव विशेषज्ञ प्राणवेश सान्याल कहते हैं कि अब शेर की खाल, पंजे और मगरमच्छ की खाल के अलावा भारतीय चिड़ियाघरों की अमूल्य प्राणी संपदा पर भी तस्करों की नज़र है. उक्त वन्यजीव कोलकाता से मुंबई और बंगलौर, फिर वहां से विदेशों को भेजे जा रहे हैं. उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी होकर नेपाल के रास्ते आसान हैं. ये बंदर आकार में छोटे होते हैं और इन्हें छुपाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है. सेंट्रल जू अथॉरिटी ने कोलकाता चिड़ियाघर के निदेशक को बर्ख़ास्त करते हुए राज्य सरकार से कैफ़ियत तलब की है. अथॉरिटी ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा चिड़ियाघर चलाने के अधिकार पर भी सवाल उठाए हैं. वन विशेषज्ञ वेद प्रकाश दुबे कहते हैं कि जब तक जंगलों की रक्षा नहीं की जाएगी, वन्यजीवों को बचाए रखना कठिन है. सिमटते वन क्षेत्र वन्यजीवों के लिए ख़तरे की घंटी हैं. यदि समय रहते इस ओर ध्यान न दिया गया तो वह दिन दूर नहीं, जब हम वन्यजीवों को सिर्फ़ चित्रों में देखेंगे. विधायक विनोद चतुर्वेदी कहते हैं कि बुंदेलखंड में खनिज माफ़ियाओं को सरकारी संरक्षण मिलने के कारण वन्यजीवों और वनों पर ख़तरा मंडराने लगा है. बुंदेलखंड को पहाड़ विहीन करने की साज़िश रची जा रही है. पश्चिमी देशों से आने वाले मेहमान पक्षियों का शिकार प्रतापगढ़, उन्नाव, बलिया, बांदा एवं ललितपुर के बड़े-बड़े तालाबों और पक्षी विहारों में खुलेआम हो रहा है, लेकिन वन विभाग आंखें बंद किए बैठा है. ग़रीब निषाद जाति के लोगों का उत्पीड़न किया जाता है, जबकि शिकार करने वाले ताक़तवर लोग मौज कर रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

अतिक्रमण की चपेट में जंगल

उत्तर प्रदेश के जंगल अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं. लगभग 26993,93 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध क़ब्जा हो चुका है. बीते सात वर्षों में 2692,72 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध क़ब्ज़े हुए हैं. प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2001-02 में 24301.21 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण का शिकार थी, जो 2008-09 में बढ़कर 26993,93 हेक्टेयर हो गई. अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद हैं. वर्ष 2007-08 में वन भूमि पर क़ब्ज़ों के 14428 मामले सामने आए थे. 2008-09 में यह गिनती बढ़कर 14798 हो गई. प्रदेश में बाघों की एकमात्र रिहायश दुधवा टाइगर रिज़र्व में भी 827.21 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध क़ब्ज़े हो चुके हैं. वन भूमि पर सर्वाधिक अतिक्रमण तराई क्षेत्र में हुए. उत्तरी खीरी वन प्रभाग में 7868.37 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध क़ब्ज़े हैं. यहां अतिक्रमण के 3063 मामले हैं. दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में 1762 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण का शिकार है. यहां अवैध कब्जे के 749 मामले हैं. रामपुर प्रभाग में 2028.80 हेक्टेयर और शाहजहांपुर प्रभाग में 1485.28 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध क़ब्ज़े हैं. यहां 862 मामले चिन्हित हैं. पीलीभीत प्रभाग में 137.07 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण लील चुका है. यहां अवैध क़ब्ज़े के 420 मामले हैं. बिजनौर प्रभाग में 698.59 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण की गिरफ़्त में है. यहां 224 मामले चिन्हित हैं. फैज़ाबाद के अंतर्गत आने वाले सोहागीबरवा प्रभाग में 1359.34 हेक्टेयर, गोरखपुर प्रभाग में 975.60 हेक्टेयर, लखनऊ प्रभाग में 124.52 हेक्टेयर और बहराइच प्रभाग में 135.35 हेक्टेयर ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़े हैं. दक्षिणांचल के रेणुकूट प्रभाग में 1938.95 हेक्टेयर ज़मीन अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है. तराई क्षेत्र में वन भूमि पर बड़े पैमाने पर खेती हो रही है. अवैध तरीक़े से क़ाबिज़ लोग गन्ना, चावल और गेहूं की खेती कर रहे हैं. वर्षों से वन भूमि पर क़ाबिज़ लोगों को हटाना अब विभाग के लिए दुश्वार हो रहा है. वन भूमि पर अवैध क़ब्ज़ा भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत संज्ञेय अपराध है.

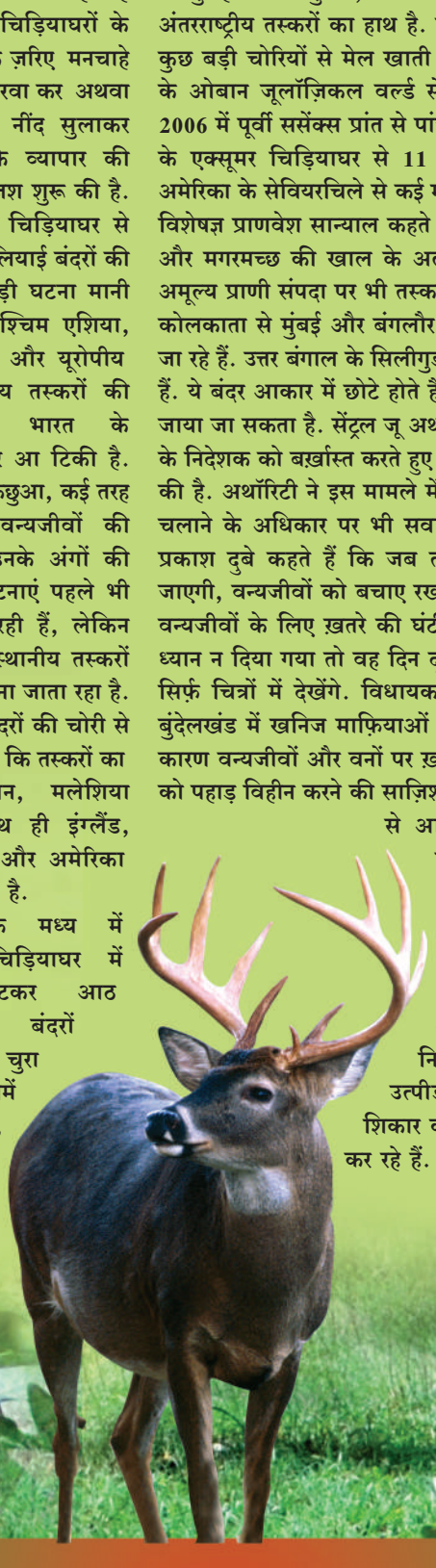

रुचिका के साथ दुर्व्यवहार की घटना से यह प्रमाणित हो जाता है कि एक पीड़ित परिवार किस तरह भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार बन जाता है.

शुक्र है कि भारत में अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, जहां हमें छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मॉल में जाने की ज़रूरत हो.

शांति बहाली के लिए कश्मीर समस्या का समाधान ज़रूरी

एम जे अकबर

पिछली बार आपने क्रिसमस कार्ड कब पढ़ा था? यह मौसमी उत्सव एक पेचीदे सवाल को जन्म देता है कि कौन सी चीज़ दुनिया में सबसे पहले आई? धरती पर शांति अथवा मनुष्यों में सद्भावना? पाकिस्तान की यात्रा करने वाला कोई भी भारतीय इस बात की तस्दीक करेगा कि उसकी ख़ातिरदारी बढ़िया तरीक़े से होती है. हम सभी भावुक इंसान हैं और जबसे भारत-पाकिस्तान की सभी समस्याओं को एक शानदार डिनर पर ही सुलझाने की मुहिम चली है, तबसे क्रिकेट इनकी शत्रुता के लिए एक आदर्श पिच बन गया है. लेकिन भारतीयों एवं पाकिस्तानियों के बीच गर्मजोशी भरे माहौल को भारत और पाकिस्तान के बीच शांति में तब्दील नहीं किया गया है. इन दोनों देशों के बीच संबंधों की शुरुआत इनके जन्म के छह सप्ताह के भीतर ही कश्मीर मसले पर जंग से हुई. इसकी वजह यह है कि इन दोनों मुल्कों की नींव राष्ट्रवाद के विरोधी अवधारणाओं पर पड़ी थी.

पाकिस्तान द्विराष्ट्रवादी सिद्धांत का ही नतीजा है. यह मसला भौगोलिक नहीं है. इसका आधार यह है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग मुल्कों के बाशिंदे हैं. मोहम्मद अली जिन्ना ने लाखों बार दोहराया कि हिंदुओं के अत्याचार की वजह से उनके साथ रहना मुसलमानों की मजबूरी थी. जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बहुविश्वासी धर्मनिरपेक्ष राज्य का अस्तित्व मुमकिन ही नहीं, बल्कि ज़रूरी भी है तो जिन्ना ने उनका मख़ौल उड़ाया था. इसी आधार पर हर पाकिस्तानी कश्मीर घाटी को पाकिस्तान का वाजिब अंग मानता है. उसका यह भी मानना है कि कश्मीर में भारतीय शासन वहां के लोगों पर क्रूर अत्याचार के कारण ही है.

भारत ने पाकिस्तान की असलियत को क़बूल लिया है. अफ़ग़ानिस्तान की मुख़ालफ़त के बावजूद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की सदस्यता का समर्थन किया, लेकिन भारतीय विचारधारा यह क़बूल नहीं कर सकती कि दो धर्मों के आधार पर दो मुल्क होने चाहिए. इसका संविधान और छह दशकों का लोकतांत्रिक तजुर्बा भी यही कहता है. भारतीय विचारधारा कश्मीर को भारत का अविभाज्य हिस्सा और पाकिस्तानी विचारधारा उसे पाकिस्तान का हिस्सा मानती है. पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और यदि कोई उसे हिंदू बहुल जम्मू देने की पेशकश करे तो वह स्वीकार नहीं करना चाहेगा. उसका संविधान ग़ैर मुसलमानों को राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनाने से मना करता है.

कश्मीरियों ने पूरे मसले में त्रिराष्ट्रीय सिद्धांत को शामिल कर एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है. कश्मीरी आज़ादी की अवधारणा का सूत्रधार कोई मुसलमान नहीं था. 1947 में महाराजा हरि सिंह ने एक अलग राज्य की उम्मीद से ही भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी राज्य में विलय की संधि पर दस्तख़त करने में विलंब किया था. वक़्त के साथ-साथ और ख़ासकर घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद आज़ादी की मांग कश्मीरियों के बजाय कश्मीरी मुसलमानों का मुद्दा बन गई है. यह कौन सा उपाय है, जिससे दोनों परस्पर विरोधी आकांक्षाओं या विलय की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है? सद्भावना चाहने वाले आशावादी लोगों को इन समस्याओं को स्पष्ट तौर पर सामने लाना चाहिए. मौजूदा नतीजों को देखते हुए इन तीनों में से एक को अपनी हठधर्मी विचारधारा छोड़नी चाहिए.

दिल्ली यह मानती है कि बातचीत का सबसे आसान तरीक़ा त्रिपक्षीय सिद्धांत में निहित है. इसने अपने चिर-परिचित शांति नीतियों से स्वायत्तता की आड़ में कश्मीर के लिए एक नया शिगूफ़ा छोड़ा है. इसने कश्मीर को एक वर्चुअल नेशन के विकल्प के तौर पर पेश किया है. दिल्ली की कोशिशों के बाद इस्लामाबाद पूर्व नियोजित संकेतों से विवाद बढ़ा करेगा और ... की हक़ीक़त जाने बग़ैर कश्मीरियों को आज़ादी का एक टुकड़ा दे दिया जाएगा. क़ानूनी और संवैधानिक सशक्तिकरण के अभाव में इस तरह के समाधान भ्रामक ही होंगे. यह समाधान कई मामलों में बेहद ही खोखला साबित होगा. बहुत से पाकिस्तानी इसे समाधान के तौर पर नहीं देखते हैं. उनके मुताबिक़, कश्मीर पर पूर्ण अधिकार की दिशा में यह महज़ आंशिक जीत ही होगी.

निश्चित तौर पर आतंकी नेटवर्कों और सरकार में उनके सहयोगियों का यह घोषित मक़सद है. और, अपने इस मक़सद के लिए वे ख़ुद ख़ूनख़राबा करेंगे. लश्कर-ए-तैय्यबा और उसके सहयोगी भारत के साथ शांति समझौते पर दस्तख़त करेंगे, इसकी संभावना बेहद कम है. दिल्ली में सरकार या उसके मिज़ाज में भी बदलाव हो सकता है. दिल्ली में ही पंडित नेहरू ने शेख़ अब्दुल्ला के साथ कई वायदे किए, लेकिन बाद में उससे पीछे हट गए. इसकी वजह यह थी कि वे सभी वायदे संघीय ढांचों की कसौटी पर असंगत ठहरते थे और उनसे भारतीय एकता को गहरा धक्का पहुंचता.

पाकिस्तान के विचारधारा को उसकी गलियों में बंदूकों और आत्मघाती हमलावरों द्वारा हर रोज़ चकनाचूर किया जा रहा है. समान विचारधारा भी बांग्लादेश की क्रांति, बलूचिस्तान में विद्रोह अथवा पिछले सप्ताह शिया मुसलमानों के नरसंहार को नहीं रोक सकी. इस बात का पता लगाना बेहद दिलचस्प होगा कि आज शिया मुसलमान ख़ुद को लखनऊ में ज़्यादा महफ़ूज़ महसूस करते हैं या कराची में? पाकिस्तानी मुसलमानों ने एक अलग देश बनाया, क्योंकि हिंदू और सिखों के साथ नहीं रह सकते थे. आज वे अपनों के साथ भी नहीं रह पा रहे हैं. सारे सबूत हमारे सामने हैं. हालात इतने संवेदनशील हैं कि उन्हें बयां नहीं किया जा सकता है.

कश्मीर का मसला असफल सिद्धांत में निहित नहीं हो सकता है. और, वाक़ई कश्मीरी इस बात को समझते हैं कि आज़ादी का विकल्प मुमकिन नहीं है. शायद इस महाद्वीप को एक आख़िरी बार विभाजित करने की ज़रूरत है. पंजाब और बंगाल का विभाजन बेहद ही दर्दनाक था, लेकिन इससे शांति क़ायम हुई. आज इस दशक बाद भारत के किसी भी राज्य की अपेक्षा पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की सबसे घनी आबादी है. और, धर्मनिरपेक्षता की मज़बूती ने बिहारी मुसलमानों को पंजाब की ओर पलायन के लिए मजबूर किया.

1947 में कश्मीर का विभाजन युद्ध विराम की क़ीमत पर हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने बातचीत के ज़रिए जंग का विकल्प चुना. यदि पाकिस्तान घाटी पर अपना दावा वैचारिक आधार पर करता है तो वहां शांति की बहाली नामुमकिन है. यदि समस्या के समाधान के लिए कोई व्यवहारिक उम्मीद हो सकती है तो इस्लामाबाद और दिल्ली इस नए साल में एक-दूसरे पर बग़ैर उंगली उठाए आपस में हाथ मिला सकते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

रुचिका प्रकरण : अपराधी को देर से नाममात्र की सज़ा

रवि किशोर

रुचिका गिरहोत्रा के साथ अभद्रता, जिसे बाद में जिंदगी समाप्त करने को मजबूर होना पड़ा था, के मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस पी एस राठौर को मिली छह माह के कारावास की सज़ा के बारे में बस यही कहा जा सकता है कि दोषी को एक शर्मनाक कृत्य के लिए जो सज़ा मिली है, वह देर से मिली है. दूसरी बात यह है कि उसकी सज़ा अपराध की दृष्टि से बिल्कुल कमतर है. ग़ौर करने वाली बात यह है कि मुजरिम हरियाणा राज्य में क़ानून को लागू करने वाली एजेंसी पुलिस का प्रमुख ओहदेदार रह चुका है. इस पूर्व पुलिस महानिदेशक को केवल छह माह क़ैद की सज़ा ही मिली, क्योंकि 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी भारतीय दंड संहिता में कई ख़ामियां और कमियां हैं. वास्तव में भारतीय दंड संहिता में बच्चों के साथ अभद्रता को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. इस शर्मनाक घटना के बाद एक बार फिर से यह बात सामने आई कि किस तरह समाज के दबंग लोग न केवल ऐसी कारगुज़ारियों को अंजाम देते हैं, बल्कि वे राज्य के शासन तंत्र को अपने साथ कर लेते हैं और क़ानून के चंगुल से ख़ुद को बचा लेने में कामयाब हो जाते हैं. यह घटना 12 अगस्त 1990 को हुई थी और लंबे समय तक दबी रही. क़ानून को फ़ैसला सुनाने में तक़रीबन 19 साल लग गए. एक ऐसे जघन्य अपराध, जिसके कारण एक बच्ची को दुर्भाग्यपूर्ण तरीक़े से मौत का शिकार होना पड़ा और उसके पूरे परिवार को सदमे के दौर से गुजरना पड़ा, में अपराधी को मिली सज़ा किसी भी दृष्टि से पर्याप्त नहीं कही जा सकती है. इन 19 सालों के दरम्यान राठौर ने सभी विशेषाधिकारों का लाभ उठाया और राज्य के पुलिस महकमे में सर्वोच्च पद हासिल किया. प्रदेश के राजनीतिक नेतृत्व ने भी पूर्व पुलिस महानिदेशक के ऊपर लगे आरोप के प्रति अपनी आंखें मूंदे रखीं. आरोपी को पदोन्नतियां मिलती रहीं और उसे पुलिस मेडल से भी नवाज़ा गया.

रुचिका के साथ उस दिन क्या हुआ था, आइए ज़रा इस पर एक नज़र डालें. 12 अगस्त 1990 की उस बदक़िस्मत दोपहर को राठौर ने रुचिका को पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित हरियाणा लॉन टेनिस एसोसिएशन के दफ़्तर में कोचिंग के बारे में बात करने के बहाने बुलाया. वह उस समय टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के दायित्व को भी निभा रहा था. रुचिका और उसकी सहेली आराधना दोनों लॉन टेनिस एसोसिएशन के दफ़्तर में राठौर से मिलने गईं. राठौर ने आराधना से कोच को बुलाने को कहा और जब रुचिका वहां अकेली रह गई तो राठौर ने उसके साथ बदसलूकी की. आराधना जब थोड़ी देर बाद लौटी तो उसे पता चला कि राठौर ने रुचिका के साथ कुछ आपत्तिजनक करने का प्रयास किया. रुचिका ने हरियाणा के तत्कालीन राज्यपाल को घटना की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखा. पत्र के आधार पर ही राठौर के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ किया गया. मुकदमे की सुनवाई हुई और आख़िरकार वह दोषी करार दिया गया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तक़रीबन 19 साल लग गए. वास्तव में इस मामले में नौ वर्षों के बाद 1999 में भारतीय दंड विधान की धारा 354 के तहत प्राथमिकी दर्ज़ की गई. महिलाओं के साथ ज़्यादती और शारीरिक हमलों से जुड़े अपराध का उल्लेख धारा 354 के अंतर्गत किया गया है.

रुचिका द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद उसके परिवार के लोगों ने जब आपत्ति ज़ाहिर की तो राठौर के विरुद्ध पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी आरोप दर्ज़ किया गया. ट्रायल कोर्ट ने 2001 में राठौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राठौर को क्लीन चिट दे दी थी. जांच एजेंसियों ने किस तरह पक्षपात किया और दोषी का साथ दिया, वह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि सीबीआई ने उच्च न्यायालय पर आरोप के बारे में कोई दबाव ही नहीं डाला. जांच एजेंसी ने ऐसे कई तथ्यों की पूरी तरह से अनदेखी की, जिस पर उसे ग़ौर करना चाहिए था. सीबीआई ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की. रुचिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच रिपोर्ट में अंतर था. सीबीआई ने इस पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा. इसके अलावा रुचिका के पिता ने जांच रिपोर्ट पर जिन परिस्थितियों में दस्तख़त किए, इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया. रुचिका की मौत के बाद पुलिस ने उसके भाई आशु को प्रताड़ित किया था, सीबीआई ने इस पर ध्यान देना भी मुनासिब नहीं समझा.

बात सिर्फ़ इतनी नहीं है कि तथ्यों की अनदेखी की गई और उनके साथ छेड़छाड़ हुई, बल्कि बात यह है कि सत्ता के गलियारे के वैसे मित्रों और शुभचिंतकों, जो क़ानून के नियमों को तोड़ने-मरोड़ने की ताक़त रखते हैं, की मदद से यह भी सुनिश्चित किया गया कि दोषी व्यक्ति पर सही और वैसे आरोप न लग सकें, जो वास्तव में लगने चाहिए.

रुचिका के साथ दुर्व्यवहार की घटना, जिसके चलते वह आत्महत्या के लिए बाध्य हुई, से यह प्रमाणित हो जाता है कि एक पीड़ित परिवार किस तरह भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार बन जाता है और प्रभावशाली लोग अपने फ़ायदे के लिए तमाम सही तथ्यों की अनदेखी कर परिस्थितियों को अपने पक्ष में कैसे कर लेते हैं? बात सिर्फ़ इतनी नहीं है कि तथ्यों की अनदेखी की गई और उनके साथ छेड़छाड़ हुई, बल्कि बात यह है कि सत्ता के गलियारे के वैसे मित्रों और शुभचिंतकों, जो क़ानून के नियमों को तोड़ने-मरोड़ने की ताक़त रखते हैं, की मदद से यह भी सुनिश्चित किया गया कि दोषी व्यक्ति पर सही और वैसे आरोप न लग सकें, जो वास्तव में लगने चाहिए. क्या किसी को आत्महत्या करने के लिए बाध्य करने के कारण राठौर के ख़िलाफ़ भारतीय दंड विधान की धारा 354 के अंतर्गत मामला दर्ज़ किया गया? दंड विधान की धारा 354 के अलावा उस पर धारा 306 के अंतर्गत भी आरोप लगाया जाना चाहिए था. अगर पूरा मामला कुछ इस तरह का होता तो ट्रायल कोर्ट अपराधी को अधिक सख़्त और लंबी सज़ा दे पाने की स्थिति में होता. दंड विधान की धारा 306 के अंतर्गत अधिकतम दस वर्षों के क़ैद की सज़ा का उल्लेख है. इसके साथ ही अपराधी पर आर्थिक दंड लगाए जाने का भी प्रावधान है. पूर्व पुलिस महानिदेशक ने क़ानून में कमी का भी क़ायदा उठाया. क़ानून के अंतर्गत बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से जुड़े अपराध के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है. हां, बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों में ज़रूर विशेष प्रावधान हैं. ऐसे मामलों में दस साल क़ैद की सज़ा का प्रावधान है.

वर्तमान क़ानून के मुताबिक़, बलात्कार को छोड़ दें तो बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार से जुड़े तमाम मामलों को क़ानून की उस धारा के अंतर्गत ही रखा गया है, जिसमें किसी औरत की गरिमा को कलंकित करने वाले अपराधों को रखा गया है. विधि आयोग ने वर्ष 2000 में प्रस्तुत अपनी 172वीं रिपोर्ट में बाल यौन अपराध के मामले में अपराध की पहचान और अपराधी को दंडित करने के संबंध में विशेष प्रावधान की अनुशंसा की थी. आयोग ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा के ज़रिए बलात्कार की परिभाषा को बदलने और बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में कठोर दंड की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था. अगर सरकार ने भारतीय दंड विधान में बदलाव लाने के संदर्भ में विधि आयोग की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया तो राठौर जैसे लोगों को उनके अपराध के लिए ज़्यादा कठोर सज़ा मिल सकेगी. जैसे सात वर्ष की क़ैद. बहरहाल, वर्तमान क़ानूनी प्रावधानों के मुताबिक़, भारतीय दंड विधान की धारा 354 के अंतर्गत अपराधी को अधिकतम दो वर्ष क़ैद की सज़ा ही दी जा सकती है.

इसे घटना के बाद का प्रभाव ही कहिए कि विधि मंत्रालय ने क़ानून में वांछित बदलाव लाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया. सरकार ने तो यह भी कहा कि रुचिका मामले की नए सिरे से जांच की जा सकती है और राठौर को सींखचों के पीछे भेजा जा सकता है. सीबीआई भी पहले की अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय हो सकती है. इस प्रकरण के बाद सरकार मामले की जांच को लेकर ज़्यादा सकारात्मक रुख़ अख़्तियार कर सकती है. वह न केवल वर्तमान मामले में ज़रूरी कदम उठा सकती है, बल्कि निष्पक्ष और त्वरित न्याय के मार्ग में रुकावट बने पुराने क़ानूनों में ज़रूरी सुधार के लिए क़दम उठाने के बारे में भी सोच सकती है.

(लेखक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं)

feedback@chauthiduniya.com

कुसूरवार कौन?

28 दिसंबर के बिहार परिशिष्ट में प्रकाशित आलेख-दवा को दारू बना डाला पढ़कर मालूम हुआ कि नशेबाज़ी समाज को किस कदर नुक़सान पहुंचा रही है. इस तरह की दवाएं लोगों को बिना किसी डॉक्टरी पर्चे के मिल कैसे रही हैं, यह जांच का विषय है. दवा विक्रेताओं की मिलीभगत के बिना किसी भी दवा-इंजेक्शन की कालाबाज़ारी नहीं हो सकती है. प्रशासन को इस ओर अविलंब ध्यान देना चाहिए.

राजेंद्र कुमार राय, *सहरसा, बिहार.*

पृथक राज्य की राजनीति

तेलंगाना पर केंद्र सरकार की सहमति के बाद कई नए राज्यों की मांग ज़ोर पकड़ने लगी है. छोटे राज्यों के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन देश के इतने टुकड़े करना भी बुद्धिमानी नहीं है कि हर तरफ़ बिखराव ही दिखने लगे. पूर्वांचल, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, गोरखालैंड और न जाने कौन-कौन से पृथक राज्यों की मांग उठ रही है. इनमें क्षेत्र विशेष के फ़ायदे कम और नेताओं के फ़ायदे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं.

रविकांत, *ई-मेल से.*

आवाज़ दबती नहीं

28 दिसंबर-03 जनवरी 2010 के अंक में प्रकाशित लेख इंसाफ़ की आवाज़ पर पाबंदी में लेखक आदियोग जी ने छत्तीसगढ़ में आंदोलनकारियों के साथ हुए दुर्व्यहार का जो वर्णन किया है, उससे शासन-प्रशासन की नीयत का पता चल जाता है. लेकिन, न्याय के पथ पर चलने वाले लोगों के क़दम कभी डिगते नहीं हैं और हक के लिए उठी किसी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, भले ही सामने वाला कितना ताक़तवर क्यों न हो.

विनोद विश्नोई, *सतना, मध्य प्रदेश.*

यौनपेशे को क़ानून की मान्यता

देह व्यापार को वैधता प्रदान करने की मांग काफ़ी समय से चल रही है. देश के विभिन्न प्रबुद्धजनों का मत रहा है कि इस पेशे को क़ानूनी मान्यता दे दी जानी चाहिए. तब ऐसे में व्यवस्था को आख़िर क्या परेशानी है? अजब विडंबना है कि इस सवाल पर समाज को आड़ बना लिया जाता है, जबकि उसी समाज में रहने वाले कथित इज़्ज़तदार लोग अपने निजी सुख की ख़ातिर रेडलाइट एरिया में जाने से गुरेज़ नहीं करते, लेकिन यौनकर्मियों को समाज में सम्मान और उनके पेशे को क़ानूनी मान्यता देने के नाम पर उन्हें परेशानी होने लगती है.

आलोक निगम, *आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

जनता समझदार है

चौथी दुनिया के 28 दिसंबर 2009 के अंक में तोप मुकाबिल के अंतर्गत आपने आगाह किया कि हमें देश तोड़ने वाले तत्वों से सावधान रहना चाहिए. सच भी है कि ऐसे तत्व किसी के हितैषी नहीं हो सकते. लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी जनता का संयमित रहना इसी बात का प्रतीक है कि अब लोग राजनीतिज्ञों की चाल को अच्छी तरह समझने लगे हैं. उन्हें मालूम है कि देश और समाज का भला आपसी विश्वास, एकता और अखंडता से होगा, बिखराव से नहीं. जनता को अब किसी के बहकावे-उकसावे में नहीं आना चाहिए.

विनीता अग्रवाल, *ई-मेल से.*

बुज़ुर्ग और हमारा समाज

बड़े-बुज़ुर्ग हमारे सिर के ताज हैं. आपने बहुत सटीक विषय का चयन किया. बुज़ुर्गों के प्रति सभी गैर जिम्मेदार शीर्षक से प्रकाशित आलेख ने मन को छू लिया. देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति घर-परिवार, समाज और सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया वाकई चिंतनीय है. हम सभी को इस बारे में गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि जीवन की अंतिम अवस्था में हमारे बुज़ुर्ग ख़ुद को असहाय, लाचार और अकेला न महसूस करें.

खड़क सिंह थपलियाल, *देहरादून, उत्तराखंड.*

शुभकामनाएं

मैंने चौथी दुनिया के करीब चार अंक पढ़े, अच्छा लगा. यह आकर्षक और ज्ञानवर्द्धक है. कृपया पुस्तक समीक्षा के अंतर्गत पुस्तकों का प्राप्ति स्थल और मूल्य अवश्य छापा करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मंगाया जा सके. आपको एवं चौथी दुनिया टीम को नववर्ष और उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं.

रामदास धुसिया, *जवाहरनगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश.*

हिम्मत को सलाम

रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट के संदर्भ में चौथी दुनिया की सजगता के चलते ही प्रधानमंत्री जी को इसे पेश करने की घोषणा करनी पड़ी. पत्रकारिता के क्षेत्र में यह एक साहसिक क़दम है.

वरना कई लोग और संचार माध्यम सरकार से ख़ुद कुछ पाने की अभिलाषा पाले रहते हैं. लेकिन चौथी दुनिया ने जनता की आवाज़ बनकर उसका दिल जीत लिया है. हम आपके साहस को सलाम करते हैं. विद्यार्थियों और बेरोज़गार युवाओं के लिए एक पन्ना निर्धारित कर सकें तो अच्छा रहेगा.

शंकर शर्मा, *चिलमिल, बेगूसराय, बिहार.*

चौथी दुनिया से प्रभावित

मैं आपके प्रतिष्ठित साप्ताहिक समाचारपत्र चौथी दुनिया से खासा प्रभावित हूं.

सपन सतनालिका, *एमजी रोड रानीगंज, पश्चिम बंगाल.*

पाठक हूं, प्रशंसक नहीं

चौथी दुनिया का मैं नियमित पाठक हूं, पर प्रशंसक नहीं. लोकतंत्र में देश और जनता के पक्ष को उठाना अगर जनप्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी है तो इसके लिए उन्हें प्रेरित करना मीडिया का दायित्व है.

प्रो. वी डी कृष्णन नंपियार, *काकुंभागम, तिरुवल्ला, केरल.*

पाठक अपने विचार और सुझाव हमें इस पते पर भेज सकते हैं-
संपादक, चौथी दुनिया, एफ़-2, सेक्टर - 11
नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

शशि थरूर की सराहना होनी चाहिए

संतोष भारतीय

पुराने दौर में बादशाह के फ़रमान को ख़ुदा का फ़ैसला माना जाता था. शासन के फ़ैसले सिर्फ़ एक शख़्स के हाथ में होते थे. वही राज्य का पहला और आख़िरी न्यायाधीश होता था. समय के साथ-साथ शासन चलाने का तरीक़ा बदला. फ़ैसला कौन करे, इस निर्णय प्रक्रिया में लोग जुड़ने लगे. दुनिया के कई देशों में फ़ैसले का अधिकार अब आम जनता के हाथों में आ गया है, जिसे हम प्रजातंत्र कहते हैं. ऐसे कई देश हैं, जो ख़ुद को प्रजातंत्र तो कहते हैं, लेकिन वहां जनता की हिस्सेदारी सिर्फ़ काग़ज़ों और आंकड़ों तक ही सीमित है. नई सदी में भारत में जब नई पीढ़ी की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि राजनीतिक दलों, चाहे वे कांग्रेस हों या भाजपा, क्या नई पीढ़ी के पास कोई दूरदृष्टि है? या फिर यह कि क्या उनमें बड़े बदलाव लाने की क्षमता है? इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि भारत की नई पीढ़ी के नेता अपने इर्द-गिर्द बुने आडंबर के मायाजाल को ग़लत मानते हैं और मौजूदा शीर्ष नेताओं से इनका प्रजातंत्र में विश्वास अधिक है.

विदेश राज्यमंत्री शशि थरूर से कांग्रेस नाराज़ है. वह बीजेपी के निशाने पर भी हैं. इतना ही नहीं, मीडिया भी उन पर हमला कर रहा है. वह वीजा रेगुलेशन पर अपने लेखन की वजह से फिर सुर्ख़ियों में आ गए. शशि थरूर ने सिर्फ़ इतना कहा कि सुरक्षा देने के नाम पर हम अपने देश में ग़लत बदलाव की पहल कर दें. 26/11 के आतंकी मुंबई में बिना वीजा के आए थे. यह बात भी सही है कि डेविड कोलमैन हेडली के मामले में यह उजागर हुआ कि वीजा रेगुलेशन की कमियों की वजह से ही वह भारत में लंबे समय तक रहने में कामयाब रहा. बहरहाल, मामला वीजा से जुड़ा था तो वैसे ही यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का हो गया. टेलीविज़न चैनलों को फिर से एक मुद्दा हाथ लग गया. राजनीति में मौजूद सामंती सोच के लोगों को बोलने का मौक़ा मिल गया कि सरकार का यह कैसा मंत्री है, जो सरकार के मत के ख़िलाफ़ अपना दिमाग़ दौड़ाने का दुस्साहस कर रहा है. बीजेपी भी शशि थरूर के बहाने कांग्रेस की खिंचाई करने मैदान में कूद पड़ी. विदेश मंत्री ने अपने तेवर कड़े कर लिए. मीडिया ने भी शशि थरूर को कठघरे में उतार दिया. शशि थरूर ऐसा क्यों करते हैं? कुछ लोग यह कह सकते हैं कि वे जानबूझ कर वक़्त-बेवक़्त सुर्ख़ियां बटोरने के लिए ऐसा करते हैं. वीजा को लेकर शशि थरूर ने कुछ लिखा तो टीवी चैनलों पर एंकर्स चीखते-चिल्लाते नज़र आने लगे. टीवी चैनलों का भी दोष नहीं है, क्योंकि राई को पहाड़ बनाना तो उनकी फितरत बन गई है. अफ़सोस की बात यह है कि शशि थरूर ने जो बात कही, अगर उस पर सार्थक बहस होती तो अच्छा होता, लेकिन बहस यह होने लगी कि शशि थरूर ने सरकार के नीतिगत फ़ैसले के बारे में अपने विचार सार्वजनिक क्यों किए. जिस विषय पर बहस होनी चाहिए, उस पर बहस नहीं हुई. शशि थरूर ने बस इतना ही कहा था कि वीजा नीति में बदलाव करने से पर्यटकों को परेशानी होगी. शशि थरूर ने जो कहा, उस पर बहस की जा सकती है. आख़िर प्रजातंत्र की पहचान भी तो इसी अधिकार से होती है. किसी मुद्दे पर बहस होना ही प्रजातंत्र की पहचान है.

प्रजातंत्र की एक और ख़ासियत है कि यह जनता और सरकार की दूरियों को ख़त्म करता है. इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार के पास ऐसे माध्यम हों, जिनसे दूरियां ख़त्म हो सके . इंटरनेट ऐसा ही माध्यम है. यह टीवी की तरह नहीं है, जो सिर्फ़ नेताओं के भाषण सुना सकती है. शशि थरूर की तरह भारत सरकार को भी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जिससे सरकार एवं जनता के बीच संवाद स्थापित हो और दोनों ही अपनी बातों को साफ़-साफ़ रख सकें.

शशि थरूर से सोशल नेटवर्क ट्विटर पर पांच लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं. इसका मतलब यह है कि वह किसी भी वक़्त और कहीं से भी एक साथ पांच लाख लोगों तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं. आज ऐसे कितने नेता हैं, जो दो महीने की तैयारी करके भी अपनी रैली में पांच लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं? इंटरनेट ने लोगों को जिस तरह से आपस में जोड़ा है, उसका इस्तेमाल सरकार चलाने में कैसे हो, यही समझने की ज़रूरत है. शशि थरूर का जुर्म क्या है? क्या थरूर को भारतीय राजनीति और इससे जुड़े पर्दा सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं है? क्या वह यह नहीं जानते कि सरकारी फ़ैसले बंद कमरे में किए जाते हैं और जिसके बारे में जनता को वक़्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा बताने का रिवाज़ भारत में नहीं है. क्या उन्हें पता नहीं है कि देश की राजनीतिक पार्टियों के अंदर वैचारिक मतभेद की जगह नहीं है. भारतीय दलगत राजनीति स्वतंत्र विचार बर्दाश्त नहीं करती. शशि थरूर ने इन्हीं रिवाज़ों को ललकारा है, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है. एक विशेष मुद्दे पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, भले ही वह राय अपने वरिष्ठ मंत्री के ख़िलाफ़ ही क्यों न हो. यह बात अलग है कि शशि थरूर को उनके वरिष्ठ मंत्री एस एम कृष्णा ने सरकारी तौर तरीक़ा बता दिया कि उन्हें अपनी राय मंत्रालय के बंद कमरे के अंदर ही देनी चाहिए.

राजनीतिक दलों की समस्या यह है कि समय के साथ वे ख़ुद को बदलने की तक़लीफ़ नहीं उठाते हैं. हमारी सरकार और सरकार चलाने वाले नेताओं को नए ज़माने की मीडिया और उसकी ताक़त को समझने की ज़रूरत है. हमारे देश में नेता मीडिया को सिर्फ़ पार्टी की अंदरूनी ख़बर को लीक करने और अपने प्रतिद्वंद्वियों को सबक सिखाने का एक ज़रिया भर समझते हैं. थरूर पढ़े-लिखे हैं और नए ज़माने की सोच रखते हैं. वह नेता के साथ-साथ एक सुलझे हुए राजनायिक हैं. शशि थरूर को प्रजातंत्र की समझ और विश्वास ज़्यादा है. सरकार की नीति तय करने में वह जनता की भी भागीदारी को महत्व देते हैं. कुछ दिन पहले वह मुंबई यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच थे. वहां उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया कि विदेश नीति में देश के नौजवानों की भागीदारी की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि छात्रों को इस काम में आगे आना चाहिए और पत्र एवं मेल के ज़रिए विदेश मंत्रालय को अपनी राय पहुंचानी चाहिए. प्रजातंत्र को अगर बचाना है तो शशि थरूर जैसे नेताओं का मज़बूत होना ज़रूरी है. भारत में प्रजातांत्रिक विकास तभी होगा, जब सरकारी नीति देश की जनता की आशा एवं अपेक्षाओं के मुताबिक़ हो. उनकी भागीदारी हो. इंटरनेट का इस्तेमाल करके अगर कोई नेता या मंत्री यह काम करने की शुरुआत करता है तो उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है. कम से कम देश का एक तो मंत्री ऐसा है, जो जनता से सीधे बात करने की हिम्मत रखता है. शशि थरूर की आवाज़ को बंद करने का मतलब प्रजातांत्रिक विकास का गला घोटने के बराबर है.

शशि थरूर ने जैसे ही पार्टी और सरकार की नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, मानो हड़कंप मच गया. कांग्रेस और दूसरे दलों को शशि थरूर का स्वागत करना चाहिए. ख़ासकर विभिन्न दलों के युवा नेताओं को शशि का साथ देना चाहिए कि वे बेझिझक पार्टी और पार्टी लाइन के बंधन को पार कर अपनी बात रखते हैं. उस अधिकार का उपयोग करते हैं, जो हमारे संविधान ने दिए हैं. विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान ही तो प्रजातंत्र का असली रूप है. अफ़सोस इस बात का है कि ज़्यादातर नेताओं और पार्टियों को लगता है कि विषयों को गुप्त रखना, पार्टी संगठन की सार्वभौमिकता, पार्टी लाइन की हद और अपनी विचारधारा को सर्वोपरि मानना ही सरकार चलाने का मूलमंत्र है. वे प्रजातंत्र को विरोध और वाद-विवाद का मंच नहीं मानते. हमारे देश के राजनीतिक दलों का विकास उस स्तर तक नहीं हो पाया है, जहां पार्टी के अंदर और पार्टी लाइन के बाहर के विरोध को सहज रूप में स्वीकार कर लिया जाए. विरोध को किस स्तर तक बर्दाश्त किया जाए, नई पीढ़ी के नेताओं के सामने यह एक चुनौती होगी.

इसके साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट हमारे देश के गांवों तक नहीं पहुंचा है, इसलिए असली भारत में रहने वाले लोगों की बात इन साधनों द्वारा सरकार तक नहीं पहुंच सकती है. अब सरकार पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी कर रही है तो इसके ज़रिए ग्रामीण जनता भी अपनी भूमिका निभा सकती है. इसलिए फ़िलहाल यह एक अच्छी शुरुआत है.

प्रजातंत्र की एक और ख़ासियत है कि यह जनता और सरकार की दूरियों को ख़त्म करता है. इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार के पास ऐसे माध्यम हों, जिनसे दूरियां ख़त्म हो सके . इंटरनेट ऐसा ही माध्यम है. यह टीवी की तरह नहीं है, जो सिर्फ़ नेताओं के भाषण सुना सकती है. शशि थरूर की तरह भारत सरकार को भी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जिससे सरकार एवं जनता के बीच संवाद स्थापित हो और दोनों ही अपनी बातों को साफ़-साफ़ रख सकें. ऐसा करने से जनता को यह लगेगा कि देश की नीतियों को तय करने में उसकी भी भागीदारी है. इससे सरकार की विश्वसनीयता तो बढ़ेगी ही, पारदर्शिता में भी इज़ाफ़ा होगा. यही प्रजातंत्र को मज़बूत करने का मूलमंत्र है. इंटरनेट पर ट्विटर जैसी साइट्स के इस्तेमाल से हमारे अधिकारी और नेता अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं. साथ ही लोगों की प्रतिक्रिया से भी वाक़िफ़ हो सकते हैं. ज़रूरत इस बात की है कि हमारे नेता और अधिकारी सरकारी फ़ैसले में जनता की भागीदारी को महत्व दें. समय बदल रहा है. परिवर्तन की इस लहर का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र रास्ता है. और, जो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, वे नई पीढ़ी के इस विजय रथ को हाथ पर हाथ रखकर देखते रह जाएंगे.

संपादक
editor.chauthiduniya.com

मॉल यानी आधुनिक युग की नई इमारतें

कांची कोहली

क्रिसमस के भीड़भाड़ वाले दिन दिल्ली में नए युग की इमारतों के बीच टहलते हुए मुझे एक बार फिर महसूस हुआ कि इस जगह से मेरा कोई रिश्ता नहीं है. महज़ इतना ही नहीं, टहलते वक़्त मेरा एक पुराना डर एक बार फिर से सामने आने लगा. अपने इस डर को मैं कभी कोई नाम नहीं दे पा रही थी. मैं अशांत रही, कभी कुछ प्रतिक्रिया हुई और कभी-कभी तो अस्वीकृति के दौर से भी गुजरी, लेकिन मैं यह ज़ाहिर तौर पर नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है. हाल ही में अपने परिवार के साथ एक यात्रा के दौरान मुझे अपनी इस परेशानी के कारणों का एहसास हुआ. मैं मॉल फोबिया या फिर कहें कि शॉपिंग मॉल के भय से ग्रसित हूं. यह डर मेरे जैसे उन लोगों को होता है, जो शहरों में लगातार बढ़ रहीं गगनचुंबी इमारतों से परेशान तो होते हैं, लेकिन उसे रोकने की दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठा सकते.

उत्सवों के दौरान हमारा उत्साह और भी अधिक हो जाता है. ऐसा लगता है कि आकर्षण और दिखावा लोगों को नशीला बना रहा है. शुक्र है कि भारत में अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, जहां हमें छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मॉल में जाने की ज़रूरत हो. आज भी हम पड़ोस में सब्ज़ी बेचने वाले, किराने की दुकान, जूता बनाने वाले या दूध वाले के पास जा सकते हैं.

आज हमारे शहरों और कस्बों अथवा उनके आसपास की जगहों का अधिग्रहण किया जा रहा है, ताकि वहां बड़े-बड़े मॉल या आवासीय परिसर बनाए जा सकें. हर दफ़ा हर किसी को एक नई इमारत खड़ी नज़र आती है. इससे ताज्जुब होता है कि किसी एक इंसान के लिए और कितनी इमारतों या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक के बाद एक होने वाले निर्माण के लिए अनुमति देने से पहले क्या प्रशासन कोई आकलन करता है? किसी एक जगह पर आख़िर किस हद तक निर्माण कार्य हो सकता है? गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए सीमेंट और पत्थरों के लिए आख़िर कितने पहाड़ों को काटा जाएगा?

लेकिन, मेरे कई शहरी दोस्तों को इससे किसी भी तरह की तक़लीफ़ नहीं होती है? आवासीय क्षेत्रों और दूसरी जगहों पर इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं. साथ ही धीरे-धीरे हमारे आसपास नए मॉल भी बन रहे हैं. उत्सवों के दौरान हमारा उत्साह और भी अधिक हो जाता है. ऐसा लगता है कि आकर्षण और दिखावा लोगों को नशीला बना रहा है. शुक्र है कि भारत में अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, जहां हमें छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मॉल में जाने की ज़रूरत हो. आज भी हम पड़ोस में सब्ज़ी बेचने वाले, किराने की दुकान, जूता बनाने वाले या दूध वाले के पास जा सकते हैं. हर बाज़ार की अपनी एक ख़ासियत और आकर्षण है. यदि इन चीज़ों में बदलाव होता है तो मैं क्या करूंगी? यह सोचते हुए भी मैं सिहर जाती हूं. अपनी दैनिक ज़रूरत के सामानों को ख़रीदने के लिए क्या मुझे बड़े बाज़ारों में जाने की ज़रूरत पड़ेगी? ये सारी चीज़ें पहले कहां तैयार होंगी? इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक के थैलों में इन्हें कहां फेंका जाएगा? क्या स्थानीय दुकानदार बड़े ख़ुदरा विक्रेताओं की तुलना में वस्तुओं की क़ीमतों के निर्धारण और छूट के स्तर पर मुक़ाबला कर पाएंगे? क्या मुझे अधिकतम खपत वाले उपभोक्ता समाज का हिस्सा होना चाहिए, जहां ऐसी सुविधाएं होती हैं कि बस मॉल में जाइए और अपनी पसंद की बनी-बनाई वस्तुएं ले आइए?

जो क्षेत्र पहले से ही आबादी बहुल हैं, वहां भी विशालकाय इमारतें अपनी जगह बनाती जा रही हैं. ऐसी कई मिसालें हैं, जहां कॉलोनियां गाड़ियों में वृद्धि और पानी की कमी का बोझ उठा रही हैं. और, यदि इन जगहों पर नए व्यापार शुरू होते हैं तो उन्हें चलाने के लिए भी ऊर्जा की ज़रूरत होगी. उनके लिए बिजली या एयर कंडीशनर की ज़रूरत होगी. बिजली जाने की स्थिति में जेनरेटर चलाने के लिए लाखों लीटर डीज़ल की जरूरत होगी. यही नहीं, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए असंख्य गैलन पानी की भी आवश्यकता होगी. इन जगहों पर तीन मंजिला पार्किंग व्यवस्था हो सकती है, लेकिन फिर भी पार्किंग के लिए सड़कें हमारी निगाहों से दूर नहीं होंगी. पहले से ही दम घुटने वाली क्रॉसिंग शासकों को और अधिक ट्रैफिक बढ़ाने के लिए आकर्षित करती है.

कुछ लोग कहते हैं कि भारत जैसे देश में ऐसा कभी नहीं होगा. मैं आशा करती हूं कि वे सही हैं. लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, जब वे कहते हैं कि यूरोप या अमेरिका में ऐसे सभी बदलाव पहले ही हो चुके हैं. मेरा अनुमान है कि मेरे जैसे लोग इस स्तर के सवाल पर ध्यान नहीं देंगे. तब तक मैं अपने पड़ोस के सिनेमाहॉल को उपेक्षा की मौत मरता देखती रहूंगी और यदि एक मॉल की पांचवीं मंजिल पर मुझे फ़िल्म देखने जाना पड़ता है तो तब तक मैं अपने भय से सामना करना सीखती रहूंगी. मैं अभी सीढ़ियों के विमान पर चढ़ने की अभ्यस्त नहीं हुई हूं!

यह जानती हूं कि मैं भी इसी व्यवस्था का हिस्सा हूं, जो उच्च उपभोग और खपत की जीवनशैली को स्थिरता देती है, लेकिन यह मेरी अंतर्रात्मा को झकझोरती भी है और मेरे लिए सवाल पूछने का कारण बनती है. मैंने कई सवालों को उठाया और यहां भी वही सवाल कर रही हूं, लेकिन यह मेरे भय का स्पष्ट संकेत है और मुझे आश्चर्य है कि कई दूसरों में भी इसी तरह का भय बना हुआ है!

(लेखिका ग़ैर सरकारी संस्था कल्पवृक्ष से जुड़ी हैं)

feedback@chauthiduniya.com

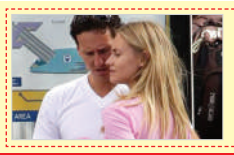

ग़रीब तबके की महिलाएं औसतन चार साल पहले सेक्सुअली ऐक्टिव हो जाती हैं. इस तरह उनमें कम उम्र में ही एचपीवी वायरस से इंफेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है.

ख़ुफ़िया एजेंसियों के सीक्रेट

जब केजीबी ने अपने ही जासूस का शिकार किया

वर्ष 1917 में एक इतिहास लिखा गया. सोवियत क्रांति का इतिहास. फिर एक और इतिहास तक़रीबन 37 वर्षों बाद लिखा गया, जब सोवियत संघ ने दुनिया की सबसे ख़तरनाक और रहस्यमयी ख़ुफ़िया एजेंसी केजीबी की नींव रखी. काग़ज़ों पर लिखे जाने वाले ख़ुफ़िया एजेंसियों के ख़ौफ़नाक इतिहास को इस एजेंसी ने हक़ीक़त में और भी ख़तरनाक साबित किया. कई दफ़ा इसके रहस्यमयी मंसूबे को समझना ख़ुद केजीबी के जासूसों के बूते की बात नहीं होती थी. ये बातें कुछ इस तरह की लगती हैं, मानों कोई जासूसी की कहानियां सुना रहा हो. यक़ीनन यह दास्तां तो जासूसी की ही है, पर है सौ फ़ीसदी सच. इतना ही नहीं, हद से भी ज़्यादा ख़ौफ़ पैदा करने वाली यह कहानी केजीबी के जासूसों के दिलों में भी दहशत पैदा करती है.

बात दूसरे विश्वयुद्ध के ख़त्म होने के बाद की है. इस महायुद्ध के अंजाम के बाद भी पूरी दुनिया दहशत में जी रही थी. दरअसल इसके बाद ही दुनिया में दो सुपर पावर देशों का जन्म हुआ था. ये दोनों देश थे साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका. अपने वर्चस्व को लेकर दोनों के बीच ख़ूब खींचतान होती रहती थी. यह दौर था शीतयुद्ध का. दोनों मुल्क हमेशा एक-दूसरे के यहां ख़ुफ़िया घुसपैठ की कोशिशें करते थे, ताकि शीतयुद्ध की यह जंग जीती जा सके. इसी मक़सद को अंजाम देने के लिए केजीबी ने अपने कई क़ाबिल एजेंटों को इस मिशन पर लगाया. केजीबी के इन्हीं शातिर और तेज़तर्रार एजेंटों में था, एनातोली गोलित्सियन. एनातोली गोलित्सियन केजीबी के सबसे ख़ास जासूसों में एक था. अपने ख़ुफ़िया मिशन को बख़ूबी अंजाम देने में केजीबी का यह एजेंट सबसे माहिर था. अपनी इसी क़ाबिलियत के बूते वह रणनीतिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले विभाग में मेजर पद तक पहुंच चुका था. उसकी इसी ख़ूबी को देखते हुए 1961 में उसे एक छद्म नाम इवान क्लिमोव से फिनलैंड की सोवियत एंबेसी भेजा गया. इवान यानी एनातोली को ज़िम्मा तो एंबेसी में काम करने का सौंपा गया, लेकिन यह किसी ख़ास मिशन को अंजाम देने के इरादे से फिनलैंड पहुंचा था. दरअसल केजीबी के इस एजेंट का काम अमेरिकी संवेदनशील विभागों में सेंध लगाना था, ताकि उसके ज़रिए सोवियत संघ अमेरिकी वर्चस्व की चुनौती को धराशायी कर सके. उसने अमेरिका में घुसपैठ के लिए स्टॉकहोम के रास्ते उड़ान भरने की योजना बनाई. इसके लिए सबसे पहले उसे फिनलैंड के ही एक शहर के लिए ट्रेन पकड़नी थी. एनातोली अपनी पूर्व निर्धारित योजना के मुताबिक़ काम कर रहा था. 15 दिसंबर 1961 को ट्रेन पकड़ने के लिए वह स्टेशन पहुंचा, लेकिन उसे इस बात की कहां ख़बर थी कि जिस मुल्क में वह घुसपैठ करने वाला था, उसकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए की शातिर नज़र उस पर पहले ही पड़ चुकी है. यानी स्टेशन पर ही वह अपने बीवी-बच्चे समेत अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए की गिरफ़्त में आ चुका था. उसे किसी और ने नहीं, बल्कि सीआईए के काउंटर इंटेलिजेंस निदेशक जेम्स जीसस एंगल्टन ने धर दबोचा था. सोवियत संघ के लिए यह वाकया ठीक उसी तरह था, मानों काटो तो ख़ून नहीं. आख़िर इससे उसकी इज़्ज़त जो दांव पर लगी थी. इस नुक़सान की भरपाई केजीबी ने जिस तरह से करने की कोशिश की, यह जानकर उसके अपने जासूसों की भी रूह एक बार कांप गई होगी. हुआ कुछ यूं कि 15 दिसंबर 1961 को पकड़े जाने के बाद 1962 के जनवरी महीने में केजीबी ने पूरी दुनिया में स्थित सोवियत संघ के 54 दूतावासों में मौजूद अपने जासूसों से इस नुक़सान की भरपाई करने का निर्देश दिया. एनातोली के पकड़े जाने के बाद केजीबी ने अपने सभी ख़ास एजेंटों के साथ मीटिंग रद्द कर दी. केजीबी के इस फ़ैसले ने सभी को चौंका दिया. वाक़ई यह हैरान करने वाला फ़ैसला था. आख़िर एक एजेंट के पकड़े जाने के बाद केजीबी ने क्यों अपने सभी ख़ास जासूसों के साथ ख़ुफ़िया जानकारियों पर होने वाली बैठक को टाल दिया. दरअसल केजीबी के काम करने का यही रहस्यमयी तरीक़ा है, जिससे उसके मंसूबों और गतिविधियों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है. लेकिन, हम आपको बताते हैं कि केजीबी के उस फ़ैसले की वजह क्या थी?

बात 1962 के नवंबर महीने की है. उस वक़्त केजीबी के मुखिया व्लादिमीर सेमिचस्नी थे. उन्होंने एक ऐसे मिशन को मंजूरी दी, जिसने केजीबी के सभी एजेंटों के होश फ़ाख्ता कर दिए. दरअसल व्लादिमीर ने एनातोली गोलित्सियन और उसके दूसरे सहयोगियों की हत्या की योजना को मंजूरी दी थी. मुमकिन है कि इस बात पर किसी को यक़ीन न हो, पर केजीबी के काम करने का हमेशा यही तरीक़ा रहा है. पहले वह अपने जासूसों से काम लेती है, उसका ख़ूब इस्तेमाल करती है और जब वह पकड़ा जाता है तो उसका काम तमाम कर देती है, ताकि उसका कोई भी राज़ बाहर न आने पाए. इस मामले में भी केजीबी ने ठीक यही किया. हालांकि यह काम उसके लिए इतना आसान नहीं था. केजीबी को भी यह बात मालूम थी कि एनातोली की हत्या कर वह अपनी साख पर ही बट्टा लगाएगी. नतीजतन इसके लिए भी उसने भरपूर तैयारी की, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे. केजीबी ने बेहद ही शातिर और असरदार तरक़ीब निकाली. उसने एनातोली के बारे में कई अफ़वाहें फैलाना शुरू कर दिया. मसलन वह सोवियत संघ में ग़ैर क़ानूनी वारदातों में शामिल होने के साथ-साथ कई स्मगलिंग ऑपरेशन को भी अंजाम देता था. एनातोली को बदनाम करने की साज़िश में केजीबी ने उसे डबल एजेंट तक करार दे दिया. यानी केजीबी के तरकश का यह ऐसा तीर था, जो बिल्कुल सही निशाने पर लगा. केजीबी की इन कोशिशों ने एनातोली की साख मिट्टी में मिला दी. इस तरह अपने इस एजेंट को बदनाम कर केजीबी ने पहले उसे दुनिया की नज़रों में एक गुनहगार साबित किया. फिर उसकी हत्या की साज़िश रची. अपनी जान पर ख़तरे को भांपते हुए एनातोली, जो अब सीआईए की गिरफ़्त में था, ने सीआईए से एक सौदा किया. हालांकि यह बात उसकी मजबूरी भी बन चुकी थी. एनातोली ने अपनी जान का सौदा सोवियत संघ की ख़ुफ़िया जानकारियों से किया. यानी उसने सोवियत संघ के कई राज़ अमेरिका को बता दिए. इसके बदले एनातोली को मिली अमेरिकी नागरिकता. यानी उसकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त. इस तरह दुनिया की सबसे ख़तरनाक एजेंसी ने अपने ही जासूस को रास्ते से हटाने के लिए साज़िश रची, लेकिन केजीबी का यह जासूस उससे भी दो क़दम आगे निकला और उसने केजीबी को उसी के खेल में मात दे दी.

सोवियत संघ का ख़ुफ़िया आतंक

सीआईए के काउंटर इंटेलिजेंस प्रमुख जेम्स एंगल्टन एवं सोवियत जासूस एनातोली.

कोई ख़ुफ़िया एजेंसी अपने ही जासूस के क़त्ल की योजना बना सकती है? आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है. लेकिन यह सच है. केजीबी प्रमुख व्लादिमीर ने एक बार अपने जासूस एनातोली गोलित्सियन और उसके सहयोगियों की हत्या की योजना को मंजूरी दी थी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

टीनएज में सेक्स से सर्वाइकल कैंसर का ख़तरा

ब्रिटेन में हुए एक ताजा शोध के अनुसार, टीनएज में सेक्स से गर्भाशय के कैंसर का ख़तरा दोगुना बढ़ जाता है. कम उम्र में पहले बच्चे का होना भी इसका एक अहम कारण है. शोध में क़रीब 20 हज़ार महिलाओं ने भाग लिया. नेतृत्वकर्ता एवं इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की डॉ. सिल्विया फ्रेंचेस्की का कहना था कि जिन लड़कियों ने 20 साल की उम्र में पहली बार शारीरिक संबंध बनाए, उनमें उन लड़कियों की तुलना में सर्वाइकल कैंसर होने की आशंका ज़्यादा थी, जिनकी उम्र 25 साल थी.

डेली मेल में छपी रिपोर्ट में डॉ. सिल्विया के हवाले से कहा गया है कि ग़रीब तबके की महिलाएं औसतन चार साल पहले सेक्सुअली ऐक्टिव हो जाती हैं. इस तरह उनमें कम उम्र में ही एचपीवी वायरस से इंफेक्शन होने का ख़तरा बढ़ जाता है. इससे वायरस को भी पनपने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है. एचपीवी सेक्सुअली ट्रांसमिटिड वायरस है, जो अधिकतर मामलों में सर्वाइकल कैंसर के लिए ज़िम्मेदार है.

सबसे ठंडी जगह चंद्रमा पर

अमेरिकी अंतरिक्ष की पड़ताल से पता चला है कि सौरमंडल की सबसे ठंडी जगह शायद चंद्रमा पर है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के टोही यान ने चंद्रमा पर मौजूद गड्ढों की जांच-पड़ताल के लिए डिवाइनर नामक एक उपकरण का इस्तेमाल किया. इस दौरान पता चला कि सर्दियों के मध्य में उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र के सबसे ठंडे गड्ढों का तापमान रात में गिरकर -249 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं डिवाइनर के प्रमुख खोजकर्ता डेविड पेजी ने कहा कि सौरमंडल में सबसे गर्म वातावरण भी चंद्रमा पर ही है. उन्होंने कहा कि दोपहर के समय चंद्रमा का भूमध्य रेखा पर तापमान बढ़कर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में ध्रुव काफ़ी ठंडे हो जाते हैं.

प्रोफेसर पेजी ने डिवाइनर की ओर से भेजी गई ताज़ा जानकारियों को सैन फ्रांसिस्को में हुई अमेरिकी जियोफ़िजिकल यूनियन (एजीयू) की बैठक में साझा किया. एजीयू की यह बैठक दुनिया के भू-वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा जमावड़ा होती है. डिवाइनर उन उपकरणों के समूह का हिस्सा है, जिन्हें इस साल जून में एलआरओ पर लांच किया गया था. यह समूह जुलाई से लगातार काम कर रहा है. इस साल अक्टूबर में अंतरिक्ष यान इस अवस्था में था कि वह चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्द्ध पर होने वाली ग्रीष्म संक्रांति और उत्तरी गोलार्द्ध पर होने वाली शीत संक्रांति को देख सके. डिवाइनर ने दक्षिणी गोलार्द्ध के सबसे अंधेरे गड्ढे में गर्मियों के दौरान सबसे कम तापमान -238 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर यह 249 डिग्री सेल्सियस था. प्रोफेसर पेजी के मुताबिक़, आप किसी भी चीज़ के ऊर्जा स्रोतों को मिटाकर उसे इस तरह ठंडा बना सकते हैं.

राशिफल

11 जनवरी–17 जनवरी 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है. पारिवारिक कलह की स्थिति आ सकती है. संतान के दायित्व की पूर्ति होगी. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे. आर्थिक मामलों में प्रगति होगी.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
अधीनस्थ कर्मचारी या किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है. स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहे. धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी. व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. संबंधों में मधुरता आएगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
स्वास्थ्य प्रभावित होगा. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. पारिवारिक समस्या आ सकती है. किसी के बीच हस्तक्षेप न करें, नहीं तो विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा. पारिवारिक जन से तनाव मिल सकता है. नेत्र या उदर विकार के प्रति सावधानी रखें. आर्थिक मामलों में जोख़िम न उठाएं, हानिकारक हो सकता है.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
पत्राचार करते समय सावधानी अपेक्षित है. व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. धन-सम्मान में वृद्धि होगी. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे. दांपत्य जीवन सुखमय होगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. पिता या संबंधित अधिकारी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में किसी तरह का जोख़िम न उठाएं. यात्रा- देशाटन का भरपूर आनंद मिलेगा. धन, पद और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में प्रगति होगी.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है. अनचाहे रिश्तेदारों से भेंट होगी. मन खिन्न रहेगा. उदासी अनुभव करेंगे. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
दांपत्य सुख में वृद्धि होगी. व्यर्थ के कार्यों में व्यस्तता रहेगी. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. साथ ही मनोरंजन के अवसर भी प्राप्त होंगे. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. आर्थिक पक्ष मज़बूत होगा. निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
यात्रा-देशाटन सुखद और व्यस्ततापूर्ण रहने के आसार हैं. धन-सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. आर्थिक मामलों में जोख़िम न उठाएं.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
कुछ व्यवसायिक समस्या आ सकती है या अप्रिय समाचार मिल सकता है. किसी मूल्यवान वस्तु के चोरी होने या खोने की आशंका है. स्वस्थ मनोरंजन की संभावना है, लेकिन वाहन प्रयोग में सावधानी रखें.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. किसी कारणवश आपको चुनौती के लिए संघर्ष से जूझना पड़ सकता है. विरोधी नई समस्या उत्पन्न करेंगे, लेकिन परास्त होंगे. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आय के नए रास्ते खुलेंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
उपहार, सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी. भागदौड़ अधिक रहेगी. व्यर्थ की उलझनों और तनाव का सामना करना पड़ सकता है. कोई ऐसी बात हो सकती है, जो आपके हित में न हो.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तान में राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो चुका है. यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रपति के सभी अधिकार उनसे ले लिए जाएं और प्रधानमंत्री युसूफ़ रज़ा गिलानी को दे दिए जाएं.

ज़िम्मेदारियों से मुक्त होंगे ज़रदारी !

डी आर आहूजा

पाकिस्तान के कुछ सियासतदानों के मुताबिक़ राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी का भविष्य ख़ात्मे की कगार पर है. वह राष्ट्रपति पद पर तमाम जोड़तोड़ और उपायों के चलते बने हुए हैं, लेकिन अपनी इस कोशिश में वह ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं होंगे. पाकिस्तान के कुछ अख़बार दावा कर रहे हैं कि ज़रदारी राष्ट्रपति पद छोड़कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. इसकी वजह यह है कि राष्ट्रपति को संविधान प्रदत्त सर्वोच्च अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और उनके सभी अधिकार प्रधानमंत्री को सौंप दिए गए हैं. लेकिन, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी उन्हें संविधान के मुताबिक़ दो साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा. जिस पल ज़रदारी राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा देंगे, उसी पल से उनकी आज़ादी भी छिन जाएगी और भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है. उन पर यह आरोप भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने मुर्शरफ़ के साथ मिलकर अपनी बीवी बेनज़ीर भुट्टो की हत्या की साज़िश रची, ताकि वह पार्टी प्रमुख के साथ-साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी बन सकें.

पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ पहले से ही मुसीबतों में घिरे हैं. अपनी इन्हीं समस्याओं की वजह से वह ब्रिटेन में छिपे हुए हैं, क्योंकि यदि वह पाकिस्तान लौटते हैं तो वहां की धरती पर क़दम रखते ही उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है. ब्रिटेन में ज़रदारी की अपनी संपत्ति है और जब उन्होंने वहां का रुख़ किया तो वह भी इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे थे. पाकिस्तानी सेना को ज़रदारी पर ज़रा भी यक़ीन नहीं है और वह उन्हें अमेरिकी कठपुतली मानती है. वहीं जबसे ज़रदारी ने राष्ट्रपति का पद संभाला है, तभी से नवाज़ शरीफ़ उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की जुगत में लगे हुए हैं.

पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ पहले से ही मुसीबतों में घिरे हैं. अपनी इन्हीं समस्याओं की वजह से वह ब्रिटेन में छिपे हुए हैं, क्योंकि यदि वह पाकिस्तान लौटते हैं तो वहां की धरती पर क़दम रखते ही उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है.

युसूफ़ रज़ा गिलानीः राष्ट्रपति से बढ़ता तनाव

पाकिस्तानी अख़बारों के मुताबिक़, ज़रदारी नए साल की शुरुआत में ही अपने पद से हटा दिए जाएंगे. ज़रदारी की किस्मत के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं और उनके पास अब कोई रास्ता भी नहीं है. वह बेहद चालाक रहे हैं और उन्हें मालूम है कि अब उनका वक़्त ख़त्म हो चुका है. अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी दूसरे देश में शरण या कहीं और भागने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है. राष्ट्रपति ज़रदारी के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के कई मामले लंबित हैं और जिस अध्यादेश के तहत वह अभी तक ख़ुद को आज़ाद महसूस कर रहे थे, उसे पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है. इसके बाद से ही ज़रदारी की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गईं. न्यायालय के इस आदेश के साथ ही पाकिस्तान में राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो चुका है. यह प्रस्तावित है कि राष्ट्रपति के सभी अधिकार उनसे ले लिए जाएं और प्रधानमंत्री युसूफ़ रज़ा गिलानी को दे दिए जाएं. पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कई धड़ों के साथ-साथ ज़रदारी और प्रधानमंत्री गिलानी के बीच तनाव काफ़ी बढ़ चुका है.

यह उम्मीद जताई जा रही है कि ज़रदारी के इस्तीफ़े की मांग को लेकर तनाव और भी तेज़ी से बढ़ेगा. पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ और उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सहयोगियों ने यह संकेत दिया है कि वे ज़रदारी पर इस्तीफ़ा देने के लिए दबाव बनाएंगे. इसके लिए वे एक अभियान की भी शुरुआत करेंगे. नवाज शरीफ़ का यह भी मानना है कि भुट्टो और मुशर्रफ़ के बीच हुए समझौते और उसकी वजह से ज़रदारी को मिली सुरक्षा के पीछे अमेरिका का हाथ है. हालांकि नवाज़ शरीफ़ भी दूध के धुले नहीं हैं. भुट्टो परिवार की तरह उनका परिवार भी भ्रष्टाचार का आरोपी है. शरीफ़ द्वारा ज़रदारी की आलोचना और ख़ुद को उनके विकल्प के तौर पर पेश करना सही मायनों में हास्यास्पद ही लगता है. पाकिस्तान के कुलीन वर्ग, चाहे वे राजनीति या सेना से ताल्लुक रखते हों, सभी एक दूसरे पर उंगलियां उठा रहे हैं. ऐसे में इनकी हरकतों को देखना दिलचस्प होगा. लेकिन इसी दुश्मनी ने शरीफ़ और भुट्टो परिवार के संबंधों को बिगाड़ा है. ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे की टांग खींचने का मौक़ा नहीं गंवाएगा.

सेना प्रमुख जनरल अशफ़ाक़ कियानी भी इस पद के लिए अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं. यही बात पूर्व सेना प्रमुख एवं राष्ट्रपति परवेज़ मुर्शरफ़ के लिए भी कही जा सकती है. मुशर्रफ़ ने अपने बयान में कहा था, यह तय है कि मैं पाकिस्तान ज़रूर वापस आऊंगा. हालांकि इस मामले में वक़्त की काफ़ी अहमियत है. यह ख़ासतौर पर घरेलू परिस्थितियों पर निर्भर है. इस दरम्यान अमेरिका और पाकिस्तानी सेना के बीच हुआ समझौता मुसीबतों के समंदर में गोते लगा रहा है. यह सारा खेल पैसे का है. अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा पाकिस्तान को मदद जारी रखना चाहते हैं, ताकि तालिबान और अलक़ायदा के शीर्ष नेताओं पर शिकंजा कसा जा सके. अमेरिकी मदद के बावजूद अभी तक पाकिस्तान की ओर से कोई वादा नहीं किया गया है.

इसके विपरीत पाकिस्तान में यह मांग तेज़ी से बढ़ रही है कि सरकार और सेना को अमेरिकी दबाव के सामने समर्पण नहीं करना चाहिए. ज़ाहिर है, यह बात कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल. आख़िरकार जो मदद दे रहा है, उसे ही फ़ैसले लेने का अधिकार है. मदद लेने वाले के पास मना करने का कोई विकल्प ही नहीं होता है. इस बात का इंतज़ार करना और देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि तालिबान और अलक़ायदा को पकड़ने में पाकिस्तान के इंकार पर अमेरिकी प्रतिक्रिया क्या होती है. यदि पाकिस्तानी सेना इस मसले पर अड़ जाती है तो अमेरिका और उसके सहयोगी आतंक के ख़िलाफ़ जंग की मुहिम में ख़ुद को मुश्किल हालात में पाएंगे. इन मसलों से आगे की बात करें तो अमेरिकी पैसे का लालच और अमेरिकी सेना द्वारा हमले का ख़तरा देखकर पाकिस्तान पर कुछ असर पड़ सकता है. यदि ऐसा होता है तो बराक ओबामा अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान के हालात से कैसे निपटेंगे? पाकिस्तान पर पैनी नज़र रखने वाले कहते हैं कि क्या वह कोई दूसरी रणनीति अख्तियार करेंगे?

आसिफ़ अली ज़रदारीः मुसीबत बढ़ती ही जा रही हैं

(लेखक द ट्रिब्यून अखबार के पूर्व न्यूज़ प्रमुख हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

बालबुका को फ़कीरी चोला पहनने वाले साईं बाबा झूठे और मक्कार लगे. उनके अनुसार, उन्होंने कभी बाबा को देखा ही नहीं तो फिर परिचय कैसा?

साईं की रहस्यमयी अज्ञात सत्ता

आडंबर में विश्वास नहीं रखती: आशा भोसले

विकास कपूर, इंदिरा कपूर एवं आशा भोसले.

आठ सितंबर 1933 को महाराष्ट्र में जन्मी आशा भोसले का नाम किसी परिचय का मोहताज़ नहीं है. अपनी दिलकश और रोमांटिक आवाज़ से लाखों-करोड़ों लोगों के दिल पर राज करने वाली आशा जी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1968 में फ़िल्म दस लाख के गीत, *ग़रीबों की सुनो वह तुम्हारी सुनेगा* के लिए मिला था. उसके बाद से अब तक आशा जी को कई बार फ़िल्म फेयर और अन्य राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. पिछले दिनों मुंबई के संगीत स्टूडियों में शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन के एक एलबम की रिकार्डिंग के लिए आईं आशा जी ने लंबी बातचीत की. पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:

साईं बाबा की शिक्षा आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करती है?

मेरा सारा जीवन ही साईं को समर्पित है. साईं की शिक्षा सबका मालिक एक में मुझे पूरा विश्वास है. सादा जीवन उच्च विचार का आदर्श प्रस्तुत करने वाले साईं बाबा सच में भारतीय जनमानस के सच्चे सद्‌गुरु हैं. बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबुरी रखो, सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी.

आप बाबा की पूजा-अर्चना किस प्रकार करती हैं?

और लोगों की तरह नहीं. सच तो यह है कि मैं घंटी हिलाने और ज़ोर-ज़ोर से जय-जयकार करने को भक्ति नहीं मानती. मेरी दृष्टि में भक्ति हृदय की गहराइयों से की गई प्रार्थना है, जिसका स्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अवश्य सुनता है. आपके इस गीत को भी मैंने गाने से मना कर दिया था, परंतु जब धुन और गीत के बोल सुने तो तुरंत हामी भर दी.

लेकिन मना करने के बाद हामी भरने का कारण क्या था?

आपका गाना वही कह रहा है, जो साईं बाबा ने कहा है, मंदिर-मस्जिद में न बांटों अल्लाह को भगवान को, बन के परिंदा खुली हवा में उड़ने दो इंसान को. बाबा ने जातियों के बीच समानता की शिक्षा दी. ऊंच-नीच और पाखंड का विरोध किया. इस एलबम के गानों में भी मुझे साईं बाबा की शिक्षा दिखाई दी, इसलिए मैंने हामी भर दी.

आपकी आवाज़ की मिठास पिछले 60 सालों से जस की तस है, इसे भी क्या आप साईं बाबा की कृपा मानती हैं?

बिना कृपा के तो कुछ होता ही नहीं. लेकिन बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं कृपा उसी पर करता हूं, जो मेरी कृपा पाने के लिए प्रयास करे. मैं प्रयास भी करती हूं. आज भी रियाज़ और गुरुओं की संगत में बैठना मेरा नियम है. 1948 में हिंदी फ़िल्म चुनरिया से मेरा गायकी में प्रवेश हुआ, तबसे अब तक कृपा और रियाज़ की बदौलत ही मैं गाती जा रही हूं. और, साईं से यही प्रार्थना है कि गाती रहूं.

प्रस्तुति: विकास कपूर

साईं सार्वभौम हैं

उस दिन भी बाबा रोज़ की तरह भिक्षा मांगने निकले और शिरडी के अप्पा साहेब के घर जा पहुंचे. इत्तेफ़ाक़ से अप्पा के दोस्त बालबुका भी उसी दिन बंबई से शिरडी आए थे. अप्पा ने उन्हें साईं बाबा की महिमा के बारे में बताकर दर्शन कर लेने की प्रेरणा दी. जब अप्पा अपने दोस्त से बाबा का परिचय कराने लगे तो बाबा ने कहा कि तुझे इसका परिचय देने की ज़रूरत नहीं है अप्पा, इस बालबुका को तो मैं पिछले चार सालों से जानता हूं. बाबा की बात सुनकर बालबुका को फ़कीरी चोला पहनने वाले साईं बाबा झूठे और मक्कार लगे. उनके अनुसार, उन्होंने कभी बाबा को देखा ही नहीं तो फिर परिचय कैसा? बालबुका की बात सुनकर मुस्कराते हुए साईं ने उनसे अपनी याददाश्त पर ज़ोर देने को कहा, पर बालबुका को कुछ भी याद नहीं आया. तब साईं बाबा ने कहा कि याद कर बालबुका, आज से चार साल पहले बंबई के भयखला में तू अपने एक मित्र चित्रे के घर गया था. अपने मित्र के कहने पर ही तूने उसके पूजाघर में रखे मेरे चित्र को प्रणाम किया था. साईं बाबा के याद दिलाते वह घटना बालबुका के सामने चलचित्र सी नाच गई. वह साईं के चरणों में अपना सिर रखकर अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगा. तब साईं बाबा ने कहा कि बालबुका, मेरी तस्वीर या मेरी मूर्ति को सज़दा करना मेरे सामने सज़दा करने के बराबर है. जो एक बार मेरे या मेरी तस्वीर के सामने सिर झुकाता है, मैं उसका नाम उसी वक़्त अपने भक्तों की सूची में लिख लेता हूं. संसार के कण-कण में व्याप्त अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक साईं बाबा के सामने कहीं कुछ भी अज्ञात नहीं है. अज्ञात है तो केवल और केवल उनकी अपनी लीला.

आप अपने साईं अनुभव, साईं उत्सवों की सूचना और सवाल sai4world@rediffmail.com पर मेल कर सकते हैं.

असीम खेत्रपाल

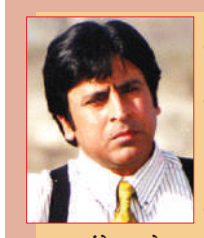

यह युग विज्ञान के चमत्कार का युग है. हर रोज़, हर चौबीस घंटे के भीतर संसार में एक नए सूर्य का उदय होता है. यह सूर्य आकाश अथवा अंतरिक्ष का नहीं है, बल्कि यह सूर्य है विज्ञान के नए-नए आविष्कारों का. वैज्ञानिक और वर्तमान पीढ़ी के लोग अपनी इन कामयाबियों पर फूले नहीं समाते. अपने प्रयोगों की सफलता पर यह पीढ़ी इतना इतराती है कि संसार में किसी सर्वोच्च सत्ता की उपस्थिति से इंकार कर देती है. लेकिन, जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, तब विज्ञान पर गर्व करने वाली यही पीढ़ी मायूस सी किसी अज्ञात सत्ता के चमत्कार के बारे में सोचती रह जाती है.

शिरडी के साईं बाबा इस संसार की सबसे रहस्यमयी और अज्ञात सत्ता के रूप में आज भी हमारे बीच हैं. आवश्यकता पड़ने पर वह अपने भक्तों की सहायता करने भागे चले आते हैं, जबकि उनके भौतिक शरीर की महासमाधि तो 1918 में ही हो गई थी. शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन 1999 से साईं नाथ महाराज की शिक्षाओं, जनचेतना और जनजागरण के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है. जनहित से जुड़े कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए फाउंडेशन ने सर्व शिक्षा, सुलभ चिकित्सा, सरल न्याय और बेसहारा लोगों की मदद के कार्यक्रम को एक आंदोलन के रूप में स्वीकार किया है. जातिपात, ऊंच-नीच के हर बंधन से मुक्त शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन के द्वार आपके लिए भी खुले हैं. आइए, अपनी सहभागिता से साईं भक्ति के प्रचार-प्रसार को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम बनिए.

शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन (रजि.)

फाउंडेशन के अध्यक्ष असीम खेत्रपाल

फाउंडेशन के उद्देश्य

- साईंबाबा की शिक्षा और संदेश को जन-जन तक पहुंचाना.
- वृंदावन में मथुरा गिरिराज साईं मंदिर, पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और धर्मशाला की स्थापना करना.
- चारों धामों में साईं मंदिर, पुस्तकालय, संग्रहालय, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और धर्मशाला की स्थापना करना.
- उचित स्थानों पर साईं वेलनेस सेंटर स्थापना करना.
- शिरडी साईंबाबा फाउंडेशन के तहत संपूर्ण विश्व में साईं भक्तों का परिवार बनाना.
- स्वर्गीय लक्ष्मी बाई शिंदे, जिन्हें शिरडी की पवित्र भूमि पर साईं बाबा ने समाधि में जाने से पूर्व नौ चांदी के सिक्के दिए थे, की स्मृति में मंदिर स्थापित करना.
- प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों की मदद करना.
- गांवों में प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मुफ़्त शिक्षा मुहैया कराना.
- ग़रीबों और ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोष स्थापित करना.

सदस्यता योजनाएं

इस फाउंडेशन का सदस्य बनने वाले व्यक्ति को उपहारस्वरूप फाउंडेशन द्वारा निर्मित फिल्म शिरडी साईं बाबा की वीसीडी, ऑडियो सीडी और साईं सच्चरित्र की पुस्तक दी जाएगी. इसके साथ ही वृंदावन मंदिर के फ्रेम में साईं बाबा की तस्वीर और शीघ्र प्रकाशित होने वाली अन्य सामग्री प्रदान की जाएगी. यह सब चुनी गई विभिन्न सदस्यता योजनाओं के आधार पर होगा.

आजीवन सदस्यता

कोई भी व्यक्ति या संस्था इस फाउंडेशन में आजीवन सदस्यता हासिल कर सकता है. इसके लिए आपको 25,000 रूपये का शुल्क देना होगा. इस योजना के तहत आपको मिलेगा:

- श्री शिरडी साईं बाबा की ताम्र की सिंहासन वाली प्रतिमा
- दो डीवीडी, साईं चरित्र (बड़ी)
- लॉकेट (बड़ा), चरण (मार्बल)
- चाबी का छल्ला
- साईं बाबा के पारदर्शी कर्णफूल
- अंगूठी, पटका, ब्रेसलेट, साईं बॉक्स, यूडीआई और घड़ी

विशेष सदस्य

फाउंडेशन का विशेष सदस्य बनने के लिए आपको 10,000 रूपये का शुल्क अदा करना होगा. और आपको मिलेगा:-

- सिंहासन के साथ साईं बाबा की प्रतिमा
- दो डीवीडी
- साईं चरित्र(बड़ी), लॉकेट (बड़ा), चरण (मार्बल)
- चाबी का छल्ला
- साईं बाबा के पारदर्शी कर्णफूल
- अंगूठी, पटका, ब्रेसलेट, साईं बॉक्स, यूडीआई और घड़ी

कार्यकारिणी सदस्य

कार्यकारिणी सदस्य बनने के लिए निर्धारित शुल्क 5,000 रूपये है. इसमें आपको मिलेगा:

- साईं बाबा की प्रतिमा
- दो डीवीडी, साईं चरित्र (बड़ी)
- लॉकेट (बड़ा), चरण (मार्बल)
- चाबी का छल्ला
- साईं बाबा के पारदर्शी कर्णफूल
- अंगूठी, पटका, ब्रेसलेट, साईं बॉक्स, यूडीआई और घड़ी

सामान्य सदस्य

सामान्य सदस्यता की अवधि तीन वर्ष और शुल्क 3,000 रूपये है. इसमें आपको मिलेगा:

- साईं बाबा की प्रतिमा
- दो डीवीडी, साईं चरित्र (बड़ी)
- लॉकेट (बड़ा), चरन (मार्बल)
- चाबी का छल्ला
- साईं बाबा के पारदर्शी कर्णफूल
- अंगूठी, पटका, ब्रेसलेट, साईं फोटो (कार के लिए), यूडीआई और घड़ी

नाम..
पता..
टेलीफोन.............................मोबाईल.............................
ई-मेल..

सदस्य बनने के लिए अपना पूरा विवरण निम्न पते पर अपने ड्राफ्ट के साथ भेजें

हस्ताक्षर

156, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065, फोन नं. 011-46567351/52

AUM Infrastructure & Developers
Booking of Villa / Flat / Plot
For Enquiries Contact:
Aum Infrastructure & Developers
Regd. Office:
156, Sant Nagar, East of Kailash
New Delhi- 110065
Tel.: 011-46594226 / 46594228
Email: shirdisaibabafounadation@gmail.com

Giriraj Sai Hills is a heavenly abode in the heart of Krishna nagri of Vrindavan it' s a lifestyle concept that provides for state of the art facilities amidst peaceful living environments. The project is a dream child of Shri Aushim Khetarpal, one of the ardent devotees of Shirdi Sai Baba who has an award winning movie on the life of Shirdi Sai Baba and a television serial to his credit.

The Temple : Live and Love in God's peculiar light at Vrinda Sai Dham with awe inspiring detailing in the structure. The temple has been designed with dedicated space for every deity, from Vishnu to Krishna and Gurus like Guru Nanak and Sai Baba, Shiva's Jyotirlinga and Sai Baba's Arti room. The Temple is ideally located at the Chatikra crossing at Vrindavan.
Belief is truth held in the mind; faith is a fire in the heart. The faith and belief in the eternal being has enabled us to plan The Sai Radhey Girdhari Temple - depicting Krishna Raas with Radha, also featuring Sai Dwarkamai, Sai Leela Hall, Meditation Centre, Amphitheatre, Museum, Goushala and Research Centre with a huge Krishna statue with Govardhan Parvat.

Features : Giriraj Sai Hills offers an innovative selection of Fully Furnished and Spacious Studio, One Bedroom and Two bedroom Apartments of sizes 360 sq.ft, 561 sq.ft and 997 sq.ft. respectively along with Expandable Furnished Villas of 1800 sq.ft.
Don't settle for the noise, congestion and traffic commercial surrounding, instead opt for the quiet convenience of prestigious Giriraj Sai Hills.
Below are few listed features:

- Eco Friendly Premises
- World Class Interiors
- Designed in accordance to tenets of Vaastu
- Provision for DTH in all homes
- CCTV facility
- Ample of parking space
- 24 hours uninterrupted water supply
- Reverse Osmosis water system for each apartment
- Earthquake resistant structure as per ISI codes
- Fire system installed at strategic points
- Rain Water Harvesting
- Children's Play Area
- Cab Facility
- Easy access to Commercial Health Care Centre offering Convenience Outlets, Restaurants, ATMs and state of the art Medical Facilities
- 24 hours flute music in all apartments
- Luxurious Hotel

आरती श्री शिरडी के साईंबाबा की

आरती श्री साईं गुरूवर की । परमानंद सदा सुरबर की ।।
जाकी कृपा विपुल सुखकारी। दुःख, शोक, संकट, भयहारी ।।1।।
शिरडी में अवतार रचाया। चमत्कार से तत्व दिखाया ।।2।।
कितने भक्त चरण पर आये। वे सुख-शांति चिरतंन पाये ।।3।।
भाव धरे मन में जैसा । पावत अनुभव वो ही वैसा ।।4।।
गुरू की लगावे तन को । समाधान लाभत उस मनको ।।5।।
साईं नाम सदा जो गावे । सो फल जग में शाश्वत पावे ।।6।।
गुरूबारसर करि पूजा-सेवा ।। उस पर कृपा करत गुरूदेवा ।।7।।
राम, कृष्ण, हनुमान रूप में ।। दे दर्शन जानत जो मन में ।।8।।
विविध धर्म के सेवक आते । दर्शन से इच्छित फल पाते ।।9।।
जय बोलो साईंबाबा की । जय बोलो अवधूतगुरू की ।।10।।
'साईंदास' आरती को गावे । घर में बसि सुख, मंगल पावे ।।11।।

spritualtravel.com, 9811037863, 9312266495
शिरडी यात्रा और वहां ठहरने की विशेष सुविधा उपलब्ध कराते हैं।

एक तरफ़ अंधेरा, दूसरी तरफ़ उजाला. सिर्फ़ उजाला. सभी कुछ भयमुक्त. साबरमती नदी ने शहर को कृष्ण और शुक्ल पक्ष में बदल दिया था.

करोड़ों का कला बाज़ार

अनंत विजय

अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल कुर्गमैन ने जब वैश्विक मंदी की आशंका जताई थी और बुश प्रशासन को आगाह किया था कि पूरा विश्व भयानक आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है तो उस वक़्त विश्व कला बाज़ार में भारतीय कलाकृतियों की क़ीमतें आसमान छू रही थीं और भारतीय कलाकारों की पेंटिंग्स करोड़ों रुपये में नीलाम हो रही थीं. लेकिन पिछले साल जब वित्त बाज़ार के अलावा रियलिटी सेक्टर में गिरावट आई तो उसका थोड़ा बहुत असर भारतीय कला बाज़ार पर भी दिखाई दिया. बाज़ार के जानकार इसे शेयर बाज़ार से जोड़कर भी देखने लगे थे. उनका तर्क था कि शेयर बाज़ार से कमाए गए पैसे लोग कला बाज़ार में निवेश करते थे, जो कि एक बेहद सुरक्षित विकल्प माना जाता था.

लेकिन अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कला बाज़ार में आर्थिक मंदी का कोई बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया. कुछ नामचीन भारतीय पेंटर हैं, जिनकी कलाकृतियां हमेशा से करोड़ों रुपये में बिकती हैं और वे सुर्ख़ियां बटोरती हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एम एफ हुसैन, रजा, तैयब मेहता जैसे महान चित्रकारों को ही करोड़ों रुपये के ख़रीददार मिलते हैं. इन समकालीन चित्रकारों के अलावा कई आधुनिक चित्रकार भी हैं, जिनकी कलाकृतियां करोड़ों रुपये में बिकती हैं, लेकिन इनके बारे में कम लिखा जाता है और इनका काम चर्चित नहीं हो पाता है. मसलन अगर हम देखें तो कुछ महीने पहले लंदन में नीलामी करने वाली कंपनी सॉदबी ने जोगेन चौधरी की कलाकृति डे ड्रीमिंग को तीन करोड़ रुपये में बेचा. जोगेन चौधरी की यह पेंटिंग इंक और पेस्टल वर्क का बेहतरीन काम था. पिछले महीने ही अकबर पद्मसी की एक पेंटिंग एक करोड़ सत्तासी लाख रुपये में बिकी. एफ एम सूजा की ओल्ड सिटी लैंडस्केप पौने दो करोड़ रुपये से ज़्यादा में नीलाम हुई. इन दोनों के अलावा सुबोध गुप्ता और वी एम गायतोंडे की पेंटिंग्स को भी एक करोड़ रुपये से ज़्यादा में ख़रीदने वाले ग्राहक मिले. इस नीलामी से अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो पिछले साल भी जाने माने पेंटर सुबोध गुप्ता की पेंटिंग सात समंदर पार सेवन के लिए लगभग पौने चार करोड़ रुपये की बोली लगी थी. सुबोध ने अपनी इस कलाकृति में मौजूदा समाज में इंसान के अहसास को अभिव्यक्त किया था. सुबोध के अलावा अनीश कपूर, टी वी संतोष, चिंतन उपाध्याय, रियास कोमू, रॉकिब शॉ और बोस कृष्णामचारी की कलाकृतियों को भी उम्मीद से ज़्यादा क़ीमत मिली थी. ग़ौरतलब है कि 2007 में सॉदबी ने रॉकिब शॉ की पेंटिंग गॉर्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स को इक्कीस करोड़ में बेचकर इतिहास रच दिया था. इसी तरह अनीश कपूर की एक पेंटिंग को अट्ठाइस लाख डॉलर, टी वी संतोष की कलाकृति टेस्ट टू को डेढ़ लाख डॉलर और रॉकिब शॉ की पेंटिंग को इक्यानवे हज़ार डॉलर मिले थे, जो कि नीलामीकर्ता की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा थे. यह फ़ेहरिस्त बेहद लंबी है. चिंतन उपाध्याय की पेंटिंग को तिहत्तर हज़ार डॉलर, रियास कोमू की पेंटिंग सिस्टमेटिक सिटीज़न फोर्टीन को उनासी हज़ार डॉलर और बोस कृष्णामचारी की पेंटिंग को चालीस हज़ार डॉलर मिले थे. इस फ़ेहरिस्त में हम अपर्णा कौर, युसूफ अरक्कमल, अतुल डोडिया और सुरेंद्र नायर को भी शामिल कर सकते हैं, जिनकी कलाकृतियां विदेशों के अलावा भारत में भी ख़ासी कमाई करती हैं.

उक्त क़ीमतें कला बाज़ार के ऐसे पक्ष से हमें रूबरू कराती हैं, जिसे लेकर भारतीय समाज में एक अनभिज्ञता की स्थिति व्याप्त है. भारतीय कलाकारों का एक बड़ा वर्ग है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कला बाज़ार में धाक है. लेकिन जानकारों का मानना है कि कला बाज़ार में तेजी का जो गुब्बारा है, वह जल्द ही फूट जाएगा. कला बाज़ार में इस तेजी के लिए जानकार रूस के आर्ट कलेक्टर की जमकर ख़रीददारी को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन साथ ही वे चेतावनी के लहज़े में नब्बे के दशक में कला बाज़ार की तेजी और फिर भारी गिरावट की याद दिलाते हैं. उस वक़्त जापानी ख़रीददारों की सक्रियता ने कला बाज़ार को काफ़ी ऊपर उठा दिया था, जो कि कृत्रिम था और थोड़े ही दिनों में वह मुंह के बल आ गिरा. लेकिन कला का जो बाज़ार है, उसमें ग्राहकों का मनोविज्ञान एक अहम भूमिका अदा करता है. अगर देश में राजनैतिक हालात बेहतर रहते हैं तो रईसों का विश्वास मज़बूत रहता है और वे बेफ़िक्र होकर निवेश करते हैं. अगर कला बाज़ार के जानकारों की मानें तो कला में निवेश करने वालों की तादाद बढ़ रही है और आने वाले समय में इस बाज़ार में बढ़ोतरी और स्थिरता अधिक देखने को मिल सकती है. घरेलू कला बाज़ार और सोना दो निवेश ऐसे हैं, जिनमें निवेशकों का विश्वास लगातार बना हुआ है. उधर अगर यूरोप और अमेरिकी कला बाज़ार में हाल की नीलामियों और प्रदर्शनियों का विश्लेषण करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वहां भी कला को लेकर ख़रीददारों और निवेशकों का विश्वास मज़बूत हुआ है. हालांकि ख़रीददार बेहद सतर्क होकर आगे बढ़ रहे हैं.

एक अनुमान के मुताबिक़, भारत का कला बाज़ार लगभग दो हज़ार करोड़ रुपये का है. शेयर बाज़ार में बेहतरी के संकेत से इस बाज़ार में भी भविष्य में और बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि मंदी के बावजूद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कला बाज़ार में मशहूर पेंटरों की कलाकृतियों को भारी–भरकम मूल्य पर ख़रीदने वाले रईस निवेशकों की कोई कमी नहीं है. मंदी ख़त्म होने के संकेत भी अब मिलने लगे हैं, जिससे निवेशकों का डगमगाता विश्वास भी लौटने लगा है. ज़रुरत इस बात की है कि भारत में अपने पेंटरों और उनकी कलाकृतियों को लेकर जो उदासीनता है, उसे दूर किया जाए और समकालीन एवं आधुनिक चित्रकारों के बीच बेहतर तालमेल हो, जिसका फ़ायदा दोनों को हो.

(लेखक आईबीएन7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

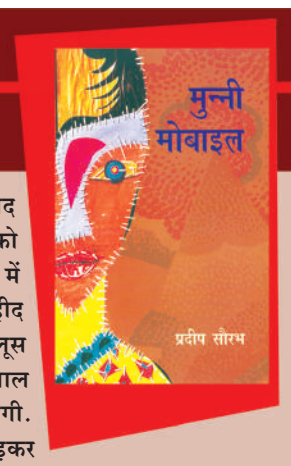

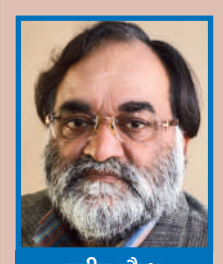

प्रदीप सौरभ

एक प्रचारक की इस इच्छा को जानकर उन्हें लगा कि वे संघ परिवार की निष्ठाओं से बंधे नहीं हैं. भविष्य में राजनीति ही उनका रास्ता है. यह बात दीगर है कि संघ परिवार के पूर्व सरसंघ चालक उर्फ गुरुजी राजनीति को पाखाने से ज़्यादा महत्व नहीं देते थे. वे कहते थे कि राजनीति समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है किंतु वह अंतिम सत्य नहीं है. राजनीति की भूमिका वैसी है जैसे किसी मनुष्य के लिए शौच जाना, जिसे टाला नहीं जा सकता. किंतु वहां बहुत देर तक बैठा नहीं जा सकता. मुलाक़ात के बाद आनंद भारती को लग गया था कि मोदी अपने आगामी जीवन में राजनीति के पाखाने में बैठने वाले हैं. पचास मिनट मोदी सरकार की इंजीनियरिंग को समझाते रहे. बात आई–गई और ख़त्म हो गई. मोदी का पटाक्षेप हो गया.

केशुभाई को हटवाकर मोदी स्वयं मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते थे. उन्होंने पूरा जोड़–तोड़ किया. वह पार्टी की नेचुरल च्वायस के तौर पर नहीं उभरे थे. फिर भी पार्टी को लगा कि मोदी होने वाले चुनाव में कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे. करिश्मा करने के लिए गोधरा की आग मोदी के लिए संजीवनी साबित हुई. मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायक बनने के लिए दो दिन पहले ही मोदी राजकोट विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे. तब तक उनमें करिश्मा नहीं था. साधारण से मुख्यमंत्री भर थे वह. इसीलिए साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड के बाद वह जब गोधरा स्टेशन मौक़ा–ए–वारदात पर पहुंचे, तो गुस्साई भीड़ उन पर चढ़ बैठी. उनके साथ गए उनके मंत्री अशोक भट्ट ने स्थिति को संभाला. गुस्साई भीड़ से पहला एनकाउंटर था वह मोदी के लिए. मोदी गमगीन मुद्रा में थे. उन्होंने गोधरा में मृतकों का पोस्टमार्टम कराने के बजाय लाशों को अहमदाबाद ले जाने का फ़ैसला किया. यदि मोदी यह फ़ैसला नहीं करते तो सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकती थी. असल में वह लाशों पर राजनीति की रणनीति बना रहे थे. पूरा ख़ाका उनके दिमाग़ में खिंच चुका था.

लाशें अहमदाबाद लाईं गईं. सरखेज गांधीनगर हाइवे स्थित सोला अस्पताल में लाशों के पहुंचने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए. पोस्टमार्टम के बाद लाशों को उनके परिवारों को सौंपने का सिलसिला शुरू हुआ. अहमदाबाद के बाहरी इलाक़े रामोल के जनता नगर के लगभग एक दर्ज़न कारसेवक वहां थे. सभी ग़रीब परिवार से थे. बताते हैं कि मरने वाले घूमने फिरने की गरज से अयोध्या गए थे. विश्व हिंदू परिषद वाले उन्हें मुफ़्त यात्रा के नाम पर पटा कर ले गए थे. अन्य मरने वाले भी निम्न मध्यवर्ग के ही थे. उनमें राम मंदिर बनाने का जज़्बा विश्व हिंदू परिषद के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं जैसा नहीं था. अयोध्या गए लोगों में अहमदाबाद के संभ्रांत इलाक़ों नवरंगपुरा और सेटेलाइट आदि से कोई नहीं था.

मौज–मस्ती के नाम पर मौत मिलेगी, यह मरने वालों के परिजनों को नहीं पता था. इसीलिए जब जनता नगर में एक दर्ज़न लाशों को लेकर हिंदू ब्रिगेड के कार्यकर्ता पहुंचे तो मरने वालों के घर वाले उन पर चढ़ गए. बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष हरेश भट्ट के साथ गुस्साई भीड़ हाथापाई पर उतर आई. स्थिति ख़राब होते देख भट्ट ने पैंतरा बदला. भावनात्मक रूप से भीड़ को समझाने की वे कोशिश करने लगे: सौगंध खाते हैं कि जिन्होंने हमारे लोगों को इस बेरहमी से मारा है, हम उनसे बदला लेकर रहेंगे. उनके इस वाक्य में भावों का ज्वार था.

भट्ट के ओजस्वी भाषण का असर हुआ और वहीं गुजरात के जलने की पहली चिंगारी चमक उठी. पहले से तैयार हिंदू ब्रिगेड के कार्यकर्ता आग से खेलने लगे. हाथों में तलवार और चाकू उग आए. हिंदू ब्रिगेड ने गोधरा कांड के विरोध में 28 फरवरी को गुजरात बंद का आह्वान किया था. छुट्टी होने के चलते तमाशबीन और हुड़दंगी भी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए. इस तरह मोदी की लाशों की राजनीति का पहला अध्याय सफल रहा.

उसके बाद बची हुई लाशों को भी उनके शहरों में भेजा गया. शहीद की तरह जुलूस निकाले गए. धमाल हुआ. आग लगी. सौराष्ट्र को छोड़कर पूरा गुजरात जलने लगा. और यह सब कुछ राम के नाम पर हुआ. हमला जयश्रीराम के उदघोष के साथ होता. मुसलमान निशाने पर होते.

अहमदाबाद में मुसलमानों की बसाहट साबरमती नदी के दूसरे हिस्से में है. साबरमती नदी शहर के बीचोंबीच बहती है. नदी के दो किनारों की अलग–अलग दास्तां है. नदी के दोनों किनारे एक शहर में होने के बावजूद दो मुक़म्मल शहर थे. एक किनारे पर शोक में डूबी बस्तियां थीं, तो दूसरे किनारे पर लाशों की दुर्गंध के बीच दीवाली मनाते लोगों के घर. एक तरफ़ अंधेरा, दूसरी तरफ़ उजाला. सिर्फ़ उजाला. सभी कुछ भयमुक्त. साबरमती नदी ने शहर को कृष्ण और शुक्ल पक्ष में बदल दिया था. पुलिस बल के संघीकरण के चलते दंगाइयों की सुरक्षा में वे तैनात हो गए थे. मुसलमानों को उनके घरों में क़ैद कर दिया गया था. खिड़की से सिर निकालते ही सेल दाग दिए जाते. दूध–पानी और राशन जैसी सुविधाओं से वे महरूम हो गए थे.

(अगले अंक में जारी)

feedback@chauthiduniya.com

केंद्र की मदद से प्रदेश की चिंता मिटी

डॉ.कमलकांत बुधकर

चर्चा कुंभनगर की

कुंभ अवधि के प्रथम पर्व के स्वागत की तैयारियां कमोबेश पूरी कर ली गई हैं. उक्त पंक्तियां लिखे जाने तक उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार को अस्थायी कुंभ जनपद घोषित कर दिया है. अब गढ़वाल मंडल के चार जनपदों के विभिन्न हिस्से मिलाकर यह नया अस्थायी जनपद बनाया गया है. इसमें पंचपुरी हरिद्वार के अलावा बहादराबाद, देहरादून का ऋषिकेश, टिहरी का मुनि की रेती, पौड़ी का स्वर्गाश्रम, लक्ष्मणझूला और नीलकंठ महादेव मंदिर आदि तक के सारे क्षेत्र शामिल कर दिए गए हैं. अब इस नए जनपद के ज़िलाधिकारी कुंभ के मेलाधिकारी आनंद वर्द्धन होंगे. यह अस्थायी जनपद कुंभ की समाप्ति यानी 30 अप्रैल तक अस्तित्व में रहेगा. बाद में भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से फिर पूर्व स्थिति लागू हो जाएगी.

इस बीच केंद्र सरकार ने प्राय: वे सभी मांगें स्वीकार कर ली हैं, जिन्हें लेकर उत्तराखंड में असमंजस और ऊहापोह की स्थिति थी और जिनके कारण भाजपा एवं कांग्रेस के बीच दावों–बयानों का घमासान जारी था. 2009 के अंतिम दिनों में दिल्ली में संपन्न हुई केंद्र और प्रदेश के उच्चाधिकारियों की बैठक में केंद्र की ओर से कई मदों में प्रदेश सरकार की मदद करना स्वीकार कर लिया गया है. वैसे केंद्र पहले ही कुंभ कार्यों के लिए चार सौ करोड़ रुपये देना स्वीकार कर चुका है. अब केंद्र के यही निर्देश हैं कि कुंभकार्य समय से, सख्ती से और मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं. कुंभ मेले के दौरान देश–विदेश से आने वाले आस्थावानों की संख्या संभावित रूप से विराट होगी. आगामी चार महीनों में सरकारी घोषणाओं के अनुसार, पांच से छह करोड़ लोग हरिद्वार आएंगे. आस्थावानों के इस भारी सैलाब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र ने तय किया है कि वह एपीएल योजना के अंतर्गत बीस हज़ार टन गेहूं और आठ हज़ार टन चावल उत्तराखंड को देगा. कुंभ मेले के लिए विशेष रूप से मेला अवधि में 140 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कराई जाएगी. मेला क्षेत्र में एंटी–माइंस एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दो दल हरिद्वार भेजे जाएंगे.

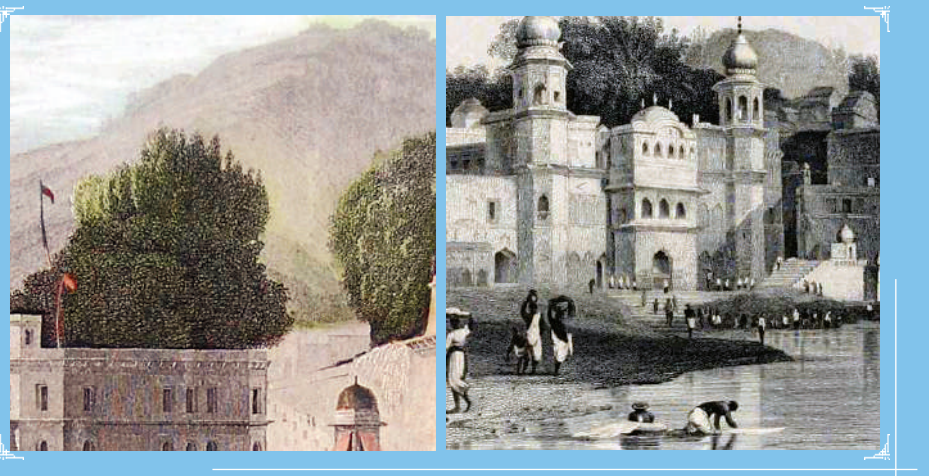

रॉबर्ट मांटगुमरी मॉर्टिन की पुस्तक इंडियन एंपायर भाग–3 में प्रकाशित 1837 एवं 1860 की बनी हरिद्धार के घाट की पेंटिंग्स

यही नहीं, मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए केंद्र महत्वपूर्ण स्नान दिवसों पर दो हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराएगा. इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षाबलों की नियुक्ति की जाएगी. इसके तहत केंद्रीय पुलिस बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, स्निफर डॉग स्क्वायड, एंटी माइंस स्क्वायड और एंटी टेररिस्ट स्क्वायड आदि की कुल पैंसठ कंपनियां कुंभ क्षेत्र में तैनात होंगी. लेकिन केंद्र के अनुसार, इन सबका ख़र्चा प्रदेश को देना होगा. यह क़रीब 70–80 करोड़ रुपये होगा.

प्रदेश की हालत पहले ही पतली है. ऐसे में यह ख़र्चा वहन करना उसके लिए कठिन है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने अलबत्ता यह छूट देकर प्रदेश को राहत दी है कि यह ख़र्चा वह धीरे–धीरे चुका दे. यह और बात है कि पिछले एकाधिक कुंभों में मिली केंद्रीय सहायता का क़र्ज़ अभी तक नहीं चुकाया जा सका है. केंद्र सरकार को लगातार कोसते आ रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक भी इन घोषणाओं से अब गदगद हैं, प्रसन्न और आश्वस्त हैं. अब उनके नेतृत्व में हो रहे हरिद्वार महाकुंभ में अर्थ और सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार को ज़्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा. उनकी अपनी न हींग लगेगी, न फिटकरी. रंग अलबत्ता चोख़ा ही चोख़ा होगा.

उधर अपनी अनंत और अथक आलोक यात्रा पर निकले भगवान सूर्यनारायण, जो अब तक दक्षिणायन में हैं, के उत्तरायण में संक्रमण का मांगलिक पर्व मकर संक्रांति 14 जनवरी 2010 के दिन आने को है. इसे सुखद संयोग ही मानेंगे कि सारा उत्तराखंड और पर्वतीय समाज इस मकर संक्रांति पर्व को विशेष महत्व देता है. पर्वतीय समाज के लोग इस अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करके सुपात्रों को दान–दक्षिणा देते, तिल–गुड़–खिचड़ी बांटते और स्वयं ग्रहण करते हैं. इस बार यह मकर संक्रांति पर्वतवासियों के उत्तराखंड में महाकुंभ को न्यौता देते हुए आ रही है. मकर संक्रांति को यूं भी संवत्सर मुख कहा जाता है. यानी वह पर्व, जिसके आने से प्रकृति में भी नवीनता भरने लगती है. मौसम गुलाबी होने लगता है और वसंती हवाएं नए साल को आवाज़ देने लगती हैं.

मकर संक्रांति के अगले ही दिन यानी 15 जनवरी को मौनी अमावस्या के साथ–साथ सूर्यग्रहण भी पड़ रहा है. इसके बाद 20 जनवरी को वसंत पंचमी और 30 जनवरी को माघ स्नान की संपन्नता की सूचक माघी पूर्णिमा पड़ेगी. यानी कुल मिलाकर जनवरी पूरी होते–होते कुंभकाल के ग्यारह में से चार स्नान संपन्न हो चुके होंगे.

यह वर्ष हरिद्वारवासियों के लिए भी अत्यंत विशेष है. यहां के साधु–संन्यासी और उनके मठ–मंदिर, अखाड़े, पंडे–पुजारी, छोटे–बड़े व्यापारी, ठेकेदार, दुकानदार, मिस्त्री–मज़दूर, कर्मचारी–अधिकारी, राजनेता और सामान्यजन ग्यारह बरसों से इस महाकुंभ की प्रतीक्षा में हैं. अब अवसर आया है कि उनकी कामनाओं का कुंभ भी वांछित अमृत से भरे. समाज का हर वर्ग कुंभ को लेकर उत्साहित और सक्रिय है. यह सारी सक्रियता और उत्साह कुंभ कमाने के लिए है. होता होगा दुनिया भर के लिए कुंभ पुण्य स्नान के रास्ते मोक्ष प्राप्ति का पर्व, लेकिन हरिद्वार वालों के लिए तो यह पर्व अर्थ प्राप्ति का स्वर्ण अवसर है. इस धर्मनगरी में हर कोई ग्यारह बरसों से यही प्रतीक्षा कर रहा है कि कब कुंभ आए और कब वह कमाए. भिखारियों से लेकर मंत्रियों तक के लिए यह अवसर धनागम का अवसर है, इसलिए हर कोई आगंतुकों को निचोड़ने की पूरी तैयारी में है.

आइए, सर्वप्रथम भगवा जगत की चर्चा करें. महाकुंभ का सर्वाधिक आकर्षण होते हैं भगवा वस्त्रधारी साधु–संन्यासी और उनकी जमातें. अखाड़ा व्यवस्था के अंतर्गत कुंभ स्थल पर सबसे पहले अखाड़े के रमतापंचों का आगमन होता है. इसके बाद बाजे–गाजे, हाथी, घोड़े, रथ पालकियों और बैलगाड़ियों सहित अखाड़े के साधु–संन्यासी जब मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उस शोभायात्रा को पेशवाई कहा जाता है. अब तो प्राय: सभी अखाड़ों की पेशवाइयां निकलने लगी हैं, पर यह परंपरा संन्यासियों के सात अखाड़ों में रूढ़ है. पेशवाइयों के आगमन के बाद शुभ मुहूर्त में अखाड़ा स्थल पर धर्मध्वजा की स्थापना होती है. यह धर्मध्वजा बावन फुट ऊंची होती है. इसके लिए कुंभ प्रशासन वन विभाग से विशेष अनुरोध करके लकड़ियों की व्यवस्था करता है. धर्मध्वजाओं की स्थापना के साथ–साथ अखाड़े अपने–अपने आराध्य देवताओं की स्थापना करते हैं और फिर शुरू हो जाती है शाही स्नानों की प्रतीक्षा.

हरिद्वार में अभी तक श्री पंचदशनाम जूना भैरव अखाड़े के रमता पंच आ चुके हैं. बिजनौर के मार्ग से आकर वे पहले कनखल स्थित आशारोड़ी गए और फिर उसके बाद अब उनका डेरा परंपरागत स्थान ज्वालापुर के पांडेवाला में लग चुका है. जूना अखाड़े के बाद अब धीरे–धीरे शेष अखाड़ों के रमता पंचों और पेशवाइयों के आने की बारी है. उम्मीद है, जनवरी के अंत तक प्राय: सभी अखाड़ों का कुंभ क्षेत्र में प्रवेश हो जाएगा.

kk@budhkar.in

एचसीएल एमई-45 मल्टी टच गेसचर टच पैड से लैस है, जिससे यूजर्स अपनी उंगलियों के एक टच से पिक्चर्स को एक्सपैंड और रोटेट कर सकते हैं. डाटा चोरी से बचने के लिए इस लैपटॉप में लॉक करने की भी सुविधा है.

माइक्रोसॉफ्ट की कंप्यूटर पेरीफेरल्स

भारत की जनता को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशल लाइफ ऑन द गो सीरीज़ कंप्यूटर पेरीफेरल्स लांच किया है. यह धूल और गंदगी प्रतिरोधी है और अधिक गर्मी में भी काम करता है. इसके तहत कंपनी ने कई चीज़ें लांच की हैं.

वायर्ड कीबोर्ड 200

छह फुट केबल वायर के साथ हाइट एडजस्टेबल, विंडोज स्टार्ट बटन और बिना आवाज़ के रेस्पांस देने वाले इस कीबोर्ड की क़ीमत माइक्रोसॉफ्ट ने मात्र 500 रुपये तय की है.

लाइफकैम कैमरा 720

पी हाई डेफीनेशन सेंसर हाई वेल्यू की बेहतरीन वीडियो क्वालिटी वाले इस पीसी कैमरे में बेहतरीन फीचर्स हैं. इसमें ऑटो फोकस, ग्लास एलीमेंट लेंस, क्लीयर स्मूथ वीडियो के लिए क्लीयर फ्रेम टेक्नोलॉजी, डिजिटल नॉयज कैंसलिंग माइक्रोफोन और ईजी टिल्ट वाली कड़ी का बेस है. इसकी क़ीमत कंपनी ने केवल तीन सौ रुपये रखी है.

वायरलेस मोबाइल माउस

इसमें ब्ल्यू ट्रैक टेक्नोलॉजी के साथ नैनो ट्रांस रिसीवर जैसी ख़ूबियां हैं. 2.4 गीगाहर्ट्ज माइक्रोसॉफ्ट वायरलेस सपोर्ट होने की वजह से इसे कंप्यूटर की 30 फीट की रेंज में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस माउस को बिना किसी अवरोध के एक बैट्री पर दस महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका बैट्री स्टेटस इंडीकेटर बता देता है कि बैट्री लो हो गई है. इसकी क़ीमत 1200 रुपये है और टैक्स अलग.

ऑप्टिकल माउस 200

बेहतरीन स्पीड, एक्यूरेसी के साथ हाथ के शेप जैसा यह माउस इस तरह से बनाया गया है कि दोनों हाथों से इस्तेमाल करने पर भी आरामदायक रहे. बिना किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए यह किसी भी प्रकार की सतह पर बिना अवरोध के काम करता है. इस वंडर माउस की क़ीमत 430 रुपये है.

लाइफ चैट एलएक्स 1000

अपने पर्सनल कंप्यूटर से किसी भी प्रकार की ऑडियो जैसे म्यूज़िक, गेमिंग और पीसी कॉल्स आदि सुनने के लिए यह पोर्टेबल हैंडसेट बेहद सुविधाजनक है. नॉयज कैंसलिंग माइक्रोफोन की साफ़ आवाज़ के साथ इसका इनलाइन वोल्यूम एडजस्ट सिस्टम आवाज़ के उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करता है. केवल 850 रुपये की क़ीमत पर मिलने वाले इस हैंडसेट का हेयरबैंड भी काफ़ी आरामदायक है.

वायरलेस डेस्कटॉप 3000

इसमें लगे हाई डेफीनेशन लेजर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ज़्यादा अच्छे, जल्दी रेस्पांस देने वाले हैं. वे आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं. इंटरनेट हॉट कुंजी के साथ मीडिया कंट्रोल करने वाली कुंजियां आसानी से एक म्यूज़िक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में शिफ्ट, प्ले, पॉस और वॉल्यूम कंट्रोल कर देती हैं. इसके अलावा आप एक बटन टच के साथ ही डाक्यूमेंट खोल सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं. मैग्नीफायर से प्वाइंट आउट और क्लिक करके अपनी इच्छानुसार डिटेल्स को बड़ा और एडिट कर सकते हैं. इसकी क़ीमत मात्र 3100 रुपये है.

एचसीएल की विंटर कार्निवाल लैपटॉप रेंज

एचसीएल इंफोसिस सिस्टम लिमिटेड ने एमई सीरीज़ के नए लैपटॉप लांच किए हैं. इसमें कंपनी ने थ्री जी इनेबल्ड एमई सीरीज़ नोटबुक एचसीएल एमई-06 और एचसीएल एमई-45 लांच की है. आजकल के युवाओं के व्यक्तित्व से मेल खाती एचसीएल नोटबुक एमई-06 थ्री जी क्षमता के साथ इंटरनेट को बिना किसी रुकावट और तेज़ी से जोड़ती है. एनर्जी स्टार 5.0 से सर्टिफाइड एचसीएल एमई-06 में 2 जीबी की एक्सपैंडेबल रैम है. इंटीग्रेटेड कैमरा और ब्ल्यूटूथ के साथ इसमें लेड ब्लैक लीड वाली 10.1 इंच एलसीडी पैनल स्क्रीन है. यह बाज़ार में हॉट रेड, डैशिंग ब्ल्यू और रॉयल ब्लैक रंगों में 19 हज़ार 990 रुपये की क़ीमत पर उपलब्ध है. एचसीएल एमई-45 मल्टी टच गेसचर टच पैड से लैस है, जिससे यूजर्स अपनी उंगलियों के एक टच से पिक्चर्स को एक्सपैंड, रोटेट कर सकते हैं. डाटा चोरी से बचने के लिए इस लैपटॉप में लॉक करने की भी सुविधा है. इसमें पड़ी फाइलें बिना आपकी आज्ञा के किसी और एक्सटरनल स्टोरेज डिवाइस, यूएसबी मेमोरी स्टिक, सीडी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एवं हार्ड डिस्क ड्राइव में कॉपी नहीं हो सकती. सिक्योर भी एक कारगर साधन है, जिससे अपने लैप्पी पर किसी भी एप्लीकेशन जैसे इंटरनेट ब्राउज़र, पावर प्वाइंट आदि को लॉक किया जा सकता है. यूजर्स अपने डाटा को इंक्रिप्ट कर सकते हैं और उसे किसी अन्य को देखने या जानने से रोक सकते हैं. इसमें 1.3 मेगा पिक्सल कैमरा और ब्ल्यूटूथ, 320 जीबी एचडीडी हार्डडिस्क, 4 जीबी की एक्सपैंडेबल रैम और 15.6 इंच का एलसीडी लेड डिस्प्ले स्क्रीन जैसे ख़ास फीचर्स हैं. इसकी क़ीमत है 39 हजार 990 रुपये.

कॉमिक्स का जादू मोबाइल पर

बच्चों के पसंदीदा बेन 10, द पावरफुल गर्ल्स, जॉनी ब्रेवो और डेक्सटर आदि कार्टून कॉमिक अब आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध होंगे. बच्चों के प्रिय चैनल कार्टून नेटवर्क द्वारा नन्हें मुन्नों के कार्टून रॉकस्टार की कॉमिक्स मोबाइल पर एयरटेल, आइडिया, टाटा डोकोमो और रिलायंस टेलीकॉम सर्विसेस पर उपलब्ध होगी. मोबाइल पर कार्टून नेटवर्क कॉमिक्स को जीपीआरएस कनेक्शन द्वारा प्रतिदिन एक रुपये, प्रति सप्ताह 10 रुपये और प्रतिमाह 30 रुपये की दर से डाउनलोड किया जा सकता है. टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि. के वाइस प्रेसीडेंट सिद्धार्थ जैन ने कहा कि देश के 63 प्रतिशत बच्चे सप्ताह में कम से कम एक बार मोबाइल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं. इससे पता चलता है कि बच्चों की दुनिया में भी मोबाइल ने अपनी जगह बना ली है. ऐसे में उसे ही क्यों न बच्चों के मनोरंजन का साधन बना दिया जाए. इस ख्याल के साथ कि बच्चे अपने मनपसंद कार्टून आसानी से मोबाइल पर पढ़ सकें, इस तकनीक को लांच किया गया है. भारत में कार्टून नेटवर्क का प्रसारण चार भाषाओं यानी हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में होता है.

टाटा इंडीकॉम का मीट एंड ग्रीट आमिर ऑफर

टाटा टेली सर्विसेज़ लिमिटेड के सीडीएमए ब्रांड टाटा इंडीकॉम ने अपने ग्राहकों के लिए नई मूल्य वर्धित सेवा मीट एंड ग्रीट ने आमिर ख़ान की घोषणा की है. इस नए ऑफर की बदौलत ग्राहकों को न सिर्फ़ हर रोज़ नक़द पुरस्कार जीतने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे अपने मनपसंद सितारे आमिर ख़ान से मिलने का मौक़ा भी पा सकते हैं. इस ऑफर में भागीदारी के इच्छुक ग्राहकों को टाटा ज़ोन से नया गेम 3 इडियट्स-रैंचो रन डाउनलोड करना होगा. 3 इडियट्स-रैंचो रन गेम काफ़ी अनूठा है. इसे खेलने वाले राजू के पिता को समय पूरा होने से पहले अस्पताल पहुंचाने में रैंचो की मदद करनी है. उसे शहर के भीड़भाड़ वाले ट्रैफिक को पार करना है यानी यह रेस समय के ख़िलाफ़ एक अभियान की तरह होगी. यह तेज़ रफ़्तार गेम शहर के ट्रैफिक के बीच 5 स्तरों पर आधारित है. खिलाड़ी को इस रेस से अंक जुटाने होंगे और गेम आगे बढ़ाने के लिए टाइम बोनस प्राप्त करना होगा. टाटा इंडीकॉम के वे सभी ग्राहक, जिनके पास ब्रू हैंडसेट है, आगामी 24 जनवरी 2010 तक टाटा ज़ोन एक्सेस कर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. इस गेम को सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड करने वाले ग्राहक को 1,000 रुपये का दैनिक नक़द पुरस्कार मिलेगा. ऑफर के तहत मासिक विजेता चुने जाने वाले ग्राहक को 3 इडियट्स मूवी के अभिनेता आमिर ख़ान से मिलने का मौक़ा मिलेगा. इस सर्विस के लिए तीन अवसरों के बदले मात्र 10 रुपये का शुल्क लिया जाएगा.

टाटा टेली सर्विसेज़ लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रमुख उत्तर एवं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दिल्ली सर्कल विनीत भाटिया ने कहा कि 3-इडियट्स साल की बहुप्रतीक्षित फ़िल्म है और उन्हें ख़ुशी है कि वह अपने ग्राहकों के लिए इस मूवी पर आधारित गेम पेश कर रहे हैं.

फोटो-पीटीआई

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैंड्रिक ली और मार्केटिंग हेड दिनेश वर्मा चेन्नई में सीडीएमए मोबाइल लांच करते हुए

सैमसंग का नया सीडीएमए फोन

सैमसंग इंडियन इलेक्ट्रानिक्स अगले साल तक लगभग 2 मिलियन सीडीएमए फोन को बाज़ार में लाने की योजना बना रही है. इसी क्रम में कंपनी ने सैमसंग कॉर्बी स्पीड मॉडल लांच किया है. यह सीडीएमए श्रृंखला में पहला फोन होगा जो टचस्क्रीन फीचर से लैस होगा. यह फोन 2.4 ऐबीपीएस तक का डाटा ट्रांसफर स्पीड देता है. इतना ही नहीं इस फोन के फीचर भी लाजवाब हैं. अगर कैमरे की बात करें तों आपको इसमें 2 मेगापिक्सल का बेहतरीन कैमरा फीचर बेहतर जूमिंग क्वालिटी के साथ मिलता है. साथ ही 2.2 इंच का लार्ज डिस्प्ले भी मौजूद है, जिस पर बड़े साइज़ पर पिक्चर्स देखने का अपना ही मजा है. इसके फीचर अभी यहीं ख़त्म नहीं होते, इसका म्यूज़िक प्लेयर एक्स्ट्रासाउंड के साथ आपको थिरकने पर मजबूर कर देगा. जी भर के गाने सुनिए और मेमोरी की तो सोचिए ही मत! क्योंकि कंपनी इस फोन पर 80 एमबी की इनबिल्ट मेमोरी दे रही है. अगर यह भी कम है तो जरा इसकी ऐक्सपेंडेबल क्षमता पर भी ग़ौर फरमाइए. इस फोन पर आप 8 एमबी तक का मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. तो देर मत कीजिए, आज ही ले आइए इस खूबसूरत गैजेट को.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सेरेना उस वक़्त विवादों में घिर गईं, जब मैच के दौरान फुट-फॉल्ट होने पर वह रेफरी और क्लाइसटर्स से भिड़ पड़ीं.

2009 के 09 खलनायक

खेलों की दुनिया में विवादों का होना कोई नई बात नहीं है. कुछ लोग मानते हैं कि विवाद भी खेलों के आकर्षण का ही एक हिस्सा है, जिसके ज़रिए खिलाड़ी आम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. साल 2009 भी खेलों के इन विवादों से अछूता नहीं रहा. कई जाने माने खिलाड़ी भी ख़ुद को विवादों से दूर नहीं रख सके.

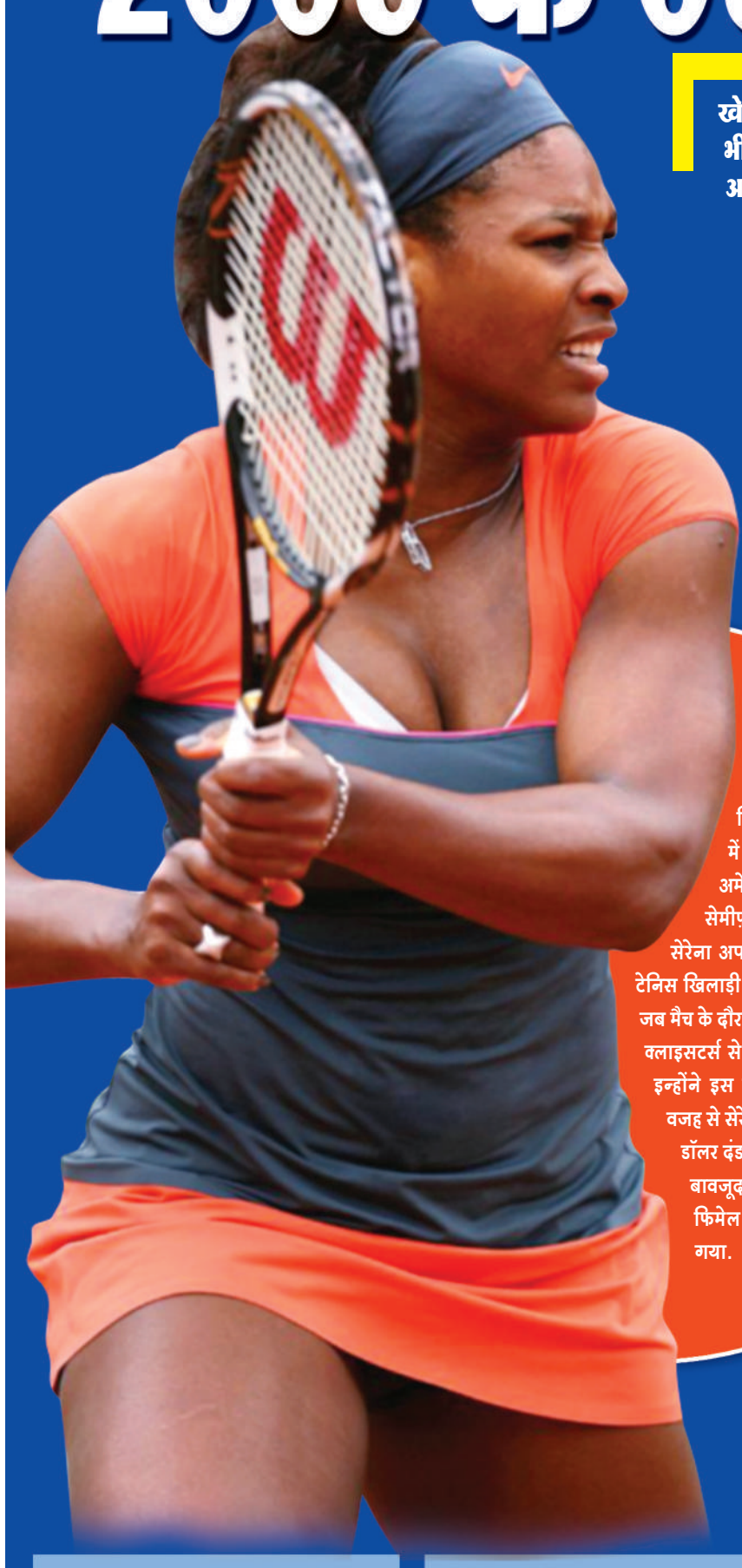

सेरेना विलियम्स

विवादित खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाली यह दूसरी अमेरिकी खिलाड़ी हैं. यूएस ओपन के सेमीफ़ाइनल में किम क्लिस्टर्स के हाथों सेरेना अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाईं. शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सेरेना उस वक़्त विवादों में घिर गईं, जब मैच के दौरान फुट-फॉल्ट होने पर वह रेफरी और क्लाइसटर्स से भिड़ पड़ीं. कुछ लोगों की मानें तो इन्होंने इस दौरान गालियां भी दीं. जिसकी वजह से सेरेना को रिकॉर्ड 82,500 अमेरिकी डॉलर दंड के तौर पर चुकाना पड़ा. इसके बावजूद सेरेना को साल के बेहतरीन फ़िमेल एथलीट से नवाजा गया.

टाइगर वुड्स

एक तरफ़ टाइगर वुड्स की सफलता ने उन्हें दशक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का ख़िताब दिलाया. वहीं उनके कारनामे ने उनकी निजी ज़िंदगी में सूनामी सरीख़ा तूफान ला दिया. हॉलीवुड अभिनेत्री जेसिका सिंपसन सहित कुल 14 महिलाओं से अवैध संबंधों की वजह से ही वुड्स सदी के सबसे खलनायक खिलाड़ी बनते नज़र आ रहे हैं. अब तो बॉलीवुड बाला लारा दत्ता से भी उनकी संबंधों की अफवाहें उड़ने लगी हैं. इन संबंधों का सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ा है और इन्हीं संबंधों की वजह से टाइगर वुड्स साल 2009 के विवादित खिलाड़ियों की सूची में नंबर एक पर हैं.

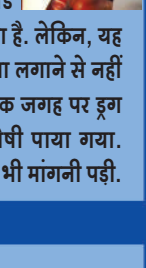

माइकल फेलेप्स

माइकल फेलेप्स को कुछ लोग दुनिया का सबसे महान ओलंपिक खिलाड़ी बताते हैं. फेलेप्स ओलंपिक खेलों में अभी तक कुल 14 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और उनके इस रिकॉर्ड के आसपास भी कोई खिलाड़ी नज़र नहीं आता है. इस अमेरिकी तैराक ने अभी तक कुल 37 विश्व रिकॉर्ड तोड़कर उन कीर्तिमानों को अपने नाम किया है. लेकिन, यह तैराक भी ख़ुद को विवादों के समंदर में गोता लगाने से नहीं रोक पाया. फेलेप्स को ख़ुलेआम सार्वजनिक जगह पर ड्रग यानी प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का दोषी पाया गया. अपनी इस हरकत के लिए फेलेप्स को माफ़ी भी मांगनी पड़ी.

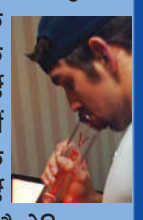

सारा ग्रोनर्ट

सारा 22 वर्षीय ख़ूबसूरत जर्मन टेनिस खिलाड़ी हैं. जन्म के समय उनमें पुरूष और महिला दोनों जननांग थे, लेकिन बाद में इन्होंने पुरूष जननांग की सर्जरी करा ली और अब वह क़ानूनी तौर पर एक महिला हैं. पर विवाद उनके टेनिस कॅरियर को लेकर है. टेनिस के कई कोच भी मानते हैं कि सारा महिलाओं के वर्ग में खेलने के क़ाबिल नहीं हैं. वह जिस तरह से सर्विस करती हैं, उतनी मज़बूती से तो वीनस विलियम्स भी नहीं करती हैं. पुरूषों की तरह तेज़ खेलने वाली इस खिलाड़ी का महिलाओं के वर्ग में खेलने को लेकर विवाद गरमाया हुआ है. इसी विवाद की वजह से वह फिलहाल टेनिस कोर्ट से बाहर हैं.

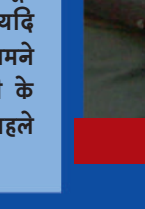

आंद्रे अगासी

कभी दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी रहे आगासी उस वक़्त विवादों में घिर गए, जब उनकी आत्मकथा दुनिया के सामने आई. इसमें अगासी ने करियर के दौरान प्रतिबंधित दवाओं के सेवन की बात क़बूलकर टेनिस की दुनिया में सनसनी मचा दी. यह विवाद उस वक़्त और भी गहरा गया जब आगासी ने यह बात कही कि वह अधिकारियों से झूठ बोलकर बच निकले थे. यदि उनका यह सच उस दौरान सामने आ गया होता तो अगासी के करियर का सूरज उगने से पहले ही अस्त हो जाता.

थियरे हेनरी

हैंड ऑफ गॉड यानी डिएगो माराडोना ने हैंड गोल से ही अर्जेंटीना को विश्वकप का ख़िताब जीतने में मदद की थी. यही कारनामा मशहूर फ्रेंच फुटबॉलर थियरे हेनरी ने किया है. हेनरी के हैंड गोल की वजह से फ्रांस विश्वकप तो नहीं जीत सका, लेकिन 2010 के विश्वकप के लिए उसने क्वालिफाई ज़रूर कर लिया. आयरलैंड के ख़िलाफ़ हुए मुक़ाबले में हेनरी ने दो बार हाथ का सहारा लिया, वह भी गेंद को गोल तक पहुंचाने के लिए. हेनरी के इस हैंड बॉल के कारण ही फ्रांस जीत दर्ज़ कर विश्वकप के लिए क्वालिफाई कर सका.

ब्रैड हैडिन

एडम गिलक्रिस्ट के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में विकेटकीपर का दायित्व संभाल रहे हैं, हैडिन. कंगारू खिलाड़ी अपनी छवि को लेकर हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं. साल 2009 में छवि बदलने की पूरी कोशिश की कंगारूओं ने, लेकिन साल के अंत अंत तक अपना सही चेहरा सामने ला ही दिया. वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन विकेटकीपर हैडिन वेस्टइंडीज़ टीम के स्पिनर सुलेमान बेन से जा भिड़े. यहां तक कि उनकी गिरेबां भी पकड़ लिया. कप्तान पोंटिंग ने अपने खिलाड़ियों के व्यवहार पर मीडिया में एतराज़ भी जताया, लेकिन फिर भी सज़ा मिली बेन को.

मोक्गादी कास्टर सेमेन्या

सेमेन्या ने वर्ष 2009 में एथलेटिक्स के महिला वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल का ख़िताब जीता. लेकिन विवादों ने सेमेन्या का भी पीछा नहीं छोड़ा. विवाद की वजह है सेमेन्या का एथलेटिक्स के महिला वर्ग में हिस्सा लेना. विवाद यहां तक बढ़ गया कि सेमेन्या को अपना जेंडर टेस्ट भी करना पड़ा ताकि लोगों को पता चल सके वह महिला हैं या पुरुष. इस प्रसंग ने आगे चलकर नस्लभेदी विवाद का रूप ले लिया. बावजूद इसके दिसंबर 2009 में ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने एक सर्वेक्षण के बाद इस दक्षिण अफ्रीकी एथलीट को 800 मीटर की दौड़ का सर्वश्रेष्ठ एथलीट करार दिया.

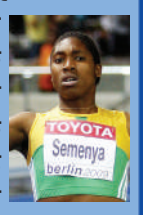

पाकिस्तान में श्रीलंकाई टीम पर हमला

यह एक ऐसी घटना है, जिसने खेल, खेल भावना और राजनयिक मर्यादा, सभी को कलंकित करने का काम किया. आतंकियों ने श्रीलंकाई टीम पर हमला किया जिसमें उसके कई खिलाड़ी बुरी तरह घायल हो गए. 2009 के मार्च महीने में खिलाड़ियों पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. इसलिए इस साल के नौवें खलनायक के तौर पर आतंकवादी हमले का माना जाता है.

खेलों की दुनिया में सफलता हासिल करने वाले खिलाड़ी भूल जाते हैं कि सफलता हासिल करने से ज़्यादा मुश्किल उसे सहेजना होता है. जो ऐसा नहीं कर पाते उनकी सफलता पर बदनामी के कलंक भी लग जाते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

खिलाड़ी अब भिखारी नहीं रहेंगे

एस. बिजेन सिंह

भारत में खिलाड़ियों की उपेक्षा कोई नई बात नहीं है. जो खिलाड़ी अपने खेल जीवन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और देश को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, एक वक़्त ऐसा आता है जब वे खिलाड़ी गुमनामी के अंधेरे में जीने को मजबूर हो जाते हैं. खेलों से संन्यास लेने के बाद रोज़गार के अभाव में इन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं. लेकिन भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर ने खिलाड़ियों की इसी समस्या को दूर करने की शुरुआत की है. इसे खिलाड़ियों की हालत सुधारने की दिशा में एक अहम क़दम माना जा रहा है. मणिपुर के मुख्यमंत्री ओ इबोबी सिंह ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख़िताब जीतने वाले 109 खिलाड़ियों को नौकरी देने का फ़ैसला किया है. अपने इसी फ़ैसले के तहत गत 30 दिसंबर को नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी स्कूल का उद्घाटन करने के दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इन खिलाड़ियों को शिक्षा, गृह और युवा एवं खेल मामले के विभागों में नौकरी दी गई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर ने स्पोर्ट्स और कल्चर को हमेशा से तरजीह दी है और यह बाक़ी राज्यों के लिए यह एक मिसाल है. नौकरी पाने वाले खिलाड़ियों में अधिकतर महिला खिलाड़ी हैं. गौरतलब है कि राज्य के हर विभाग में नौकरी का पांच फ़ीसदी कोटा खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहता है.

यह ध्यान देने वाली बात है कि कोई खिलाड़ी पूरी ज़िंदगी भर नहीं खेलता है. उनकी खेल आयु बहुत ही छोटी होती है. ऐसे में उन्हें हमेशा भविष्य की असुरक्षा का एहसास होता रहता है. सरकार न तो उनकी और न ही उनके परिवार की कोई खोज ख़बर लेती है. ऐसे में भारत की सेवन सिस्टर राज्यों में एक मणिपुर से दूसरे राज्यों को सीख लेने की ज़रूरत है, जिसने अपने खिलाड़ियों को राज्य सरकार में नौकरी देकर देश का सम्मान बढ़ाने वालों की कद्र की है. ऐसे फैसलों से ही लोग खेल को अपना करियर बनाने को प्रेरित होंगे और बेफ़िक्र होकर अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकेंगे.

bijen@chauthiduniya.com

फोटो– बुल्लु राज

खिलाड़ियों को सम्मानित करते मणिपुर के मुख्यमंत्री.

ICC Cricket World Cup 2011

विश्वकप 2011 के असफल होने की आशंका है !

चंदन कुमार

तारीख़ थी 13 मार्च 1996. मैदान कोलकाता का इडेन गार्डेन. 90,000 दर्शकों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच विश्वकप का सेमीफ़ाइनल मुक़ाबला चल रहा था. दूसरी पारी में भारतीय टीम बल्लेबाज़ी करने उतरी. उसके सामने 252 रनों का आसान, लेकिन चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था. क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले इस मैदान पर दर्शक भारत की जीत देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे थे. पर उनकी हसरतों पर पानी फिर गया, यानी सेमीफ़ाइनल के इस मैच में भारत को श्रीलंका के हाथों मुंह की खानी पड़ी. हालांकि यह मैच पूरा नहीं खेला गया, फिर भी जीत का सेहरा श्रीलंका के सिर पर बंधा. इस मैच में आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी थी. जब 35वें ओवर में 120 के स्कोर पर भारतीय टीम का आठवां विकेट गिरा तो दर्शकों का धीरज जवाब देने लगा. उन्होंने मैदान में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया और खिलाड़ियों पर पानी की खाली बोतलें फेंकने लगे. नतीजतन मैच को बंद करना पड़ा और श्रीलंका को जीत से नवाजा गया. जब दर्शक उत्पात मचा रहे थे तो उस वक़्त भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज़ विनोद कांबली मैदान पर आंसू बहा रहे थे. आठ विकेट गिर जाने के बाद भी उन्हें यक़ीन था कि वह अपने बूते पर ही टीम की नैया पार लगा देंगे, लेकिन दर्शक तो अपने कारनामों से कुछ और ही बयां कर रहे थे.

फोटो– प्रभात पाण्डेय

मुमकिन है एक बार फिर यही वाकया दोहराया जा सकता है. 27 दिसंबर 2009 को नईदिल्ली में श्रीलंका के साथ मुक़ाबले में मैच रद्द होने के बाद दर्शकों ने स्टेडियम में जो उत्पात मचाना शुरू किया, उससे शक़ की कोई गुंजाइश भी नहीं रह जाती है. लेकिन पूरे मसले में क्रिकेट प्रशासक कहीं ज़्यादा कसूरवार नज़र आते हैं. यदि इसी तरह बीसीसीआई ग़ैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाती रही तो एकबार फिर भारत में क्रिकेट पर कलंक लगने से कोई नहीं रोक सकता है. दरअसल बीसीसीआई समेत तमाम राज्यों के खेल पदाधिकारी सिर्फ़ पैसा बनाने की जुगत में लगे हैं और 2011 के विश्वकप की तैयारियों को लेकर कोई भी संजीदा नज़र नहीं आ रहा है. 27 दिसंबर को भारत और श्रीलंका के बीच मैच के दौरान जो कुछ हुआ उससे तैयारियों की सारी पोल खुल जाती है. न खेलने वाले पिच पर मैच कराकर खेल प्रशासकों की पैसा कमाने की तरकीब उल्टी पड़ गई. मुमकिन है दिल्ली के क्रिकेट प्रशंसकों को 2011 में कोटला मैदान पर होने वाले विश्वकप मैच देखने से महरूम होना पड़े, क्योंकि आईसीसी इस मैदान पर डेढ़ से दो साल तक का प्रतिबंध लगा सकती है. बात सिर्फ़ इसी मैदान की नहीं है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विश्वकप का फ़ाइनल मुक़ाबला खेला जाना है. लेकिन, इस स्टेडियम की पिच अभी तक नहीं बनी है और न ही स्टेडियम पूरी तरह बनकर तैयार हुआ है. यदि दिल्ली की ही तरह लापरवाही बरती गई तो अंजाम क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं है. जिस गति से पिच तैयार की जा रही है, उससे तो हर हाल में क्रिकेट ही कलंकित होगी और साथ में बदनाम होगा भारत. दरअसल विश्वकप होने में बमुश्किल से साल भर बचे हैं और पिच बन कर तैयार नहीं हुआ है. किसी भी पिच को खेलने लायक़ तभी माना जाता है, जब उसके बनने के बाद उस पर कम से कम एक सत्र तक घरेलू स्तर का मैच खेला जाता है. नहीं तो अंजाम कोटला के ग्राउंड जैसा होता है. गेंदबाज़ गेंद नहीं, गोले बरसाने लगते हैं और बल्लेबाज़ घायल होकर अस्पताल में होते हैं. इस दरम्यान दर्शकों की कारगुजारी किसी छिपी नहीं रहती. वहीं इडेन गार्डेन की ही बात करें तो श्रीलंका के साथ भारत का डे-नाइट मुक़ाबला चल रहा था और मैच के बीच में ही स्टेडियम की बत्ती गुल हो गई थी. ये विश्वकप की तैयारियों की कुछ नज़ीर भर हैं. इनसे सीख लेने की ज़रूरत है, नहीं तो कहीं एकबार फिर ऐसा न हो जाए कि कोई और विनोद कांबली मैदान पर आंसू बहाने लगे.

chandan@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 11 जनवरी–17 जनवरी 2010

साधारण नैन-नक्श वाली तनिशा के बारे में यही कहा जाता है कि बॉलीवुड में उनको अपने फेमिली बैकग्राउंड की बदौलत काम मिला है. जबकि तनिशा इस बात को नकारती हैं.

गुल पनाग का फैंस फंडा

डिंपल गालों वाली गुल पनाग फिल्म *डोर* के बाद अब रामगोपाल वर्मा की फ़िल्म *रण* में दिखेंगी. मिस इंडिया क्राउन से लेकर टेलीविजन एवं फ़िल्मों तक के सफर में सिल्वर स्क्रीन पर बहुत कम नज़र आने के बावजूद गुल पनाग ने बी-टाउन में अपनी अलग छवि बनाई है. फैंस के साथ जुड़े रहने की वजह से इन दिनों वह ट्विटर पर भी लगातार बनी रहती हैं और यह जानना रुचिकर होगा कि वह बेहद सामाजिक एवं तकनीक पसंद हैं. ट्विटर और अपनी ब्लॉगिंग बेवसाइट के ज़रिए वह सामाजिक विषयों पर काफ़ी रुचिकर एवं ज़िम्मेदारी भरी टिप्पणियां करती हैं. क्राउन से फ़िल्मों तक के रास्ते को गुल एक सक्सेसफुल जर्नी कहती हैं. उनका मानना है कि इस दरम्यान उन्हें अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाने का मौक़ा मिला. इसके साथ ही अपने अंदर झांककर अपनी ग़लतियों को सुधारने का अवसर मिला. बीते दिनों मैक्सीम मैगजीन के लिए हॉट एंड बोल्ड फोटो शूट करके उन्होंने अपनी साइड रोल वाली सिंपल गर्ल की छवि बदल दी है. बिकनी में अपनी ख़ूबसूरत काया के जलवे दिखाकर गुल ने जता दिया कि वह ग्लैमरस भी हैं और सेक्सी भी. वैसे बी-टाउन में अपनी काया का प्रदर्शन ही सफलता की कुंजी है. कहीं इसी गलती को सुधारने की बात तो नहीं कर रही थीं गुल!

परिवार का सहारा काम न आया

बॉलीवुड पर कई दशकों से राज करने वाले एक परिवार की बेटी तनिशा मुखर्जी को वह मुक़ाम हासिल नहीं हुआ है, जो उनके परिवार के सदस्यों को मिला है, लेकिन तनिशा ने हार नहीं मानी है. वह अब भी इस बात पर यक़ीन करती हैं कि एक दिन उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी. वह कबीर सदानंद द्वारा निर्देशित फिल्म *तुम मिलो तो सही* में नज़र आएंगी. इस फिल्म से उन्हें काफ़ी उम्मीद है. वह कहती हैं कि आप इस फ़िल्म में मुझे एकदम नए किरदार में देखेंगे. साधारण नैन-नक्श वाली तनिशा के बारे में यही कहा जाता है कि बॉलीवुड में उनको अपने फैमिली बैकग्राउंड की बदौलत काम मिला है. जबकि तनिशा इस बात को नकारती हैं. उनके मुताबिक़, फैमिली आपकी एक-दो बार तो मदद कर सकती है, लेकिन आगे का सफर आपको ख़ुद तय करना होता है. मालूम हो कि तनिशा काजोल की हैं और काजोल ने उन्हें फिल्म *नील एंड निक्की* में काम दिलाया था. फिल्म तो नहीं चली, लेकिन उनके और उदय चोपड़ा के बीच फिल्माए गए चुंबन दृश्यों की ख़ूब चर्चा हुई. लगभग ग्यारह फिल्मों में दिखने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में अपेक्षित पहचान नहीं मिल सकी है. अपने समय की बेहतरीन अदाकारा तनुजा की बेटी तनिशा ने हर हथकंडे आजमाए, ताकि उन्हें सफलता मिल जाए. वह चाहे मल्टीस्टारर फ़िल्म *सरकार* में काम करना हो या *नील एंड निक्की* में अंग प्रदर्शन. इतना ही नहीं, उन्होंने दक्षिण भाषा की फ़िल्म *कांत्रि* में भी काम किया, लेकिन परिणाम वही रहा. देखना यह है कि उनकी आने वाली फ़िल्म से कितने फैंस तनीशा को कहते हैं कि तुम मिलो तो सही.

मां बनना चाहती हैं शिल्पा

कई अटकलों के बाद आख़िरकार शिल्पा ने चख ही लिए शादी के लड्डू. चलिए यह तो ख़ुशखबरी है, पर शादी के बाद उनकी नई चाहत क्या है? क्या वह मुंबई स्थित अपनी फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी को आसमान की बुलंदी तक ले जाना चाहती हैं या फिर कुंद्रा परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती हैं? आप सोचते रहिए. फ़िलहाल सच तो यह है कि वह कुंद्रा परिवार के सदस्यों की गिनती बढ़ाना चाहती हैं. उनका अरमान है कि जल्द से जल्द जूनियर राज या लिटिल शिल्पा को दुनिया में लाया जाए. वह कहती हैं कि मां बनने के लिए मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती. उन्होंने मलाइका अरोड़ा, करिश्मा कपूर, महिमा चौधरी, काजोल देवगन, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, सोनाली बेंद्रे और रवीना टंडन जैसी ग्लैमरस मॉम बनने की ठान ली है. मां बनने की चाहत तो ठीक है शिल्पा, लेकिन फिर आपके फिल्मी कैरियर का क्या होगा? क्योंकि बॉलीवुड में काजोल के अलावा मॉम एक्ट्रेस का करियर कुछ अच्छा नहीं रहा है.

शिल्पा का अरमान हैं कि जल्दी से जल्दी जूनियर राज या लिटिल शिल्पा को दुनिया में लाया जाए. वह कहती हैं कि मां बनने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकती.

आने वाली फ़िल्म

वीर

अनिल शर्मा निर्देशक के तौर पर देओल परिवार के साथ ही काम करते रहे हैं, लेकिन इस बार वह सलमान खान के साथ फिल्म *वीर* लेकर आ रहे हैं. अनिल फिल्मों में एक्शन और रोमांस की चाशनी डालते हैं. इस बार भी उन्होंने यही किया है. साथ में पीरियड स्टोरी का तड़का भी दे दिया है. फिल्म की कहानी सलमान ने खुद लिखी है. गौरतलब है कि वह इससे पहले भी *बागी* की कहानी लिख चुके हैं. फिल्म में सलमान के अलावा सोहेल खान, मिथुन चक्रवर्ती, नीना गुप्ता और जैकी श्राफ भी हैं. सलमान खान जहां *वीर* का केंद्रीय किरदार निभा रहे हैं, वही उनकी प्रेमिका की भूमिका में विदेशी बाला जरीन खान हैं. फिल्म का प्लॉट 1880 के समय का है, जब देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी. उसी दौरान कई रियासतों के रणबांकुरों ने आजादी के लिए आवाज और तलवार उठाई थी. उन्हीं बहादुर सिपाहियों में एक वीर भी है, जो अपने पिता एवं भाई के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक गाथा रचता है. साथ ही अपनी प्रेमिका को भी हासिल करता है. 40 करोड़ रुपये के बजट में बन रही इस फिल्म की निर्माता एवं वितरक इरोज कंपनी है. 155 मिनट की अवधि की इस फिल्म में वे सारे फॉर्मूले हैं, जो *गदर* में थे. संगीत तैयार किया है सलमान की चहेती जोड़ी साजिद-वाजिद ने और गीत लिखे हैं ऑस्कर विजेता गीतकार गुलज़ार ने. फिल्म 22 जनवरी को प्रदर्शित हो रही है.

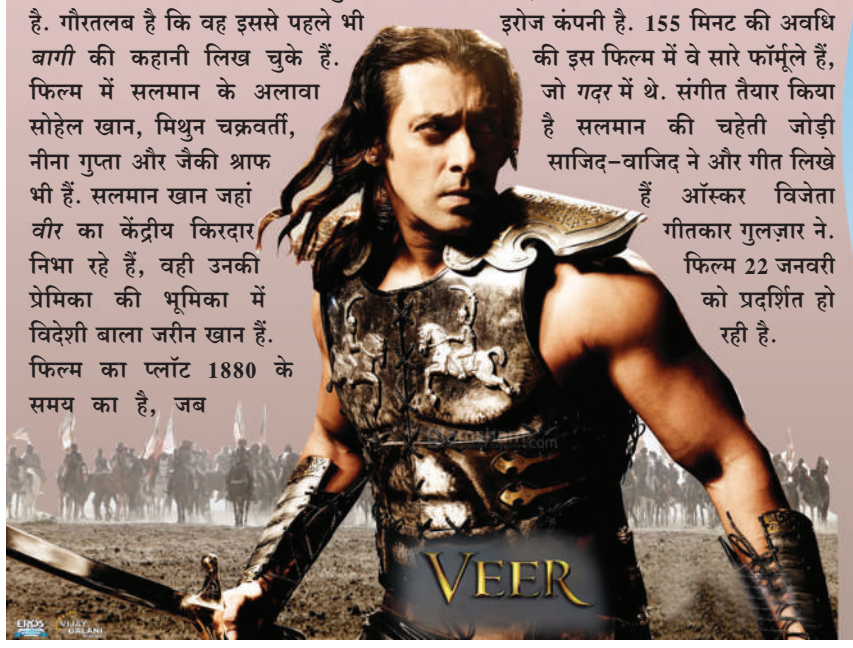

सुष्मिता सेन का लैटिन कनेक्शन

ब्यूटी क्वीन सुष्मिता सेन एक साथ कई चीजों में अपना ध्यान लगाए रखती हैं. चाहे वह फ़िल्म हो, अपनी प्रोडक्शन कंपनी हो, विज्ञापन हों, बिजनेस हो या नन्हीं परी को गोद लेना. फ्लॉप फ़िल्मों की एक लंबी लिस्ट के बाद भी कॉन्फिडेंट सुश कर्म के साथ भगवान को भी मानती हैं. रैंप वॉक के अंदाज़ से समझ में आता है कि वह कॉन्फिडेंट एवं स्टाइलिश गर्ल हैं. उनके हाथों पर बने टैटू से पता चलता है कि वह भगवान पर कितना यकीन करती हैं. उनकी दाईं कलाई पर सामने की तरफ़ से बने टैटू में लैटिन भाषा में सॉली डियो लॉरिया लिखा है, जिसका मतलब बड़े गर्व से सुष्मिता बताती हैं कि आई लिव फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड है. यानी मैं प्रभु के यश के लिए जीती हूं. दूसरे हाथ में कोहनी पर अंदर की ओर बने हुए टैटू का मतलब है टेंपटेशन और इसी हाथ पर कलाई में अंदर की तरफ़ से लिखा है आई एम यानी मैं हूं. सुश के पास वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं है, बस कमी है तो एक पति की. देखते हैं कि सुश के दिल की यह हसरत जाने कब पूरी होगी!

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

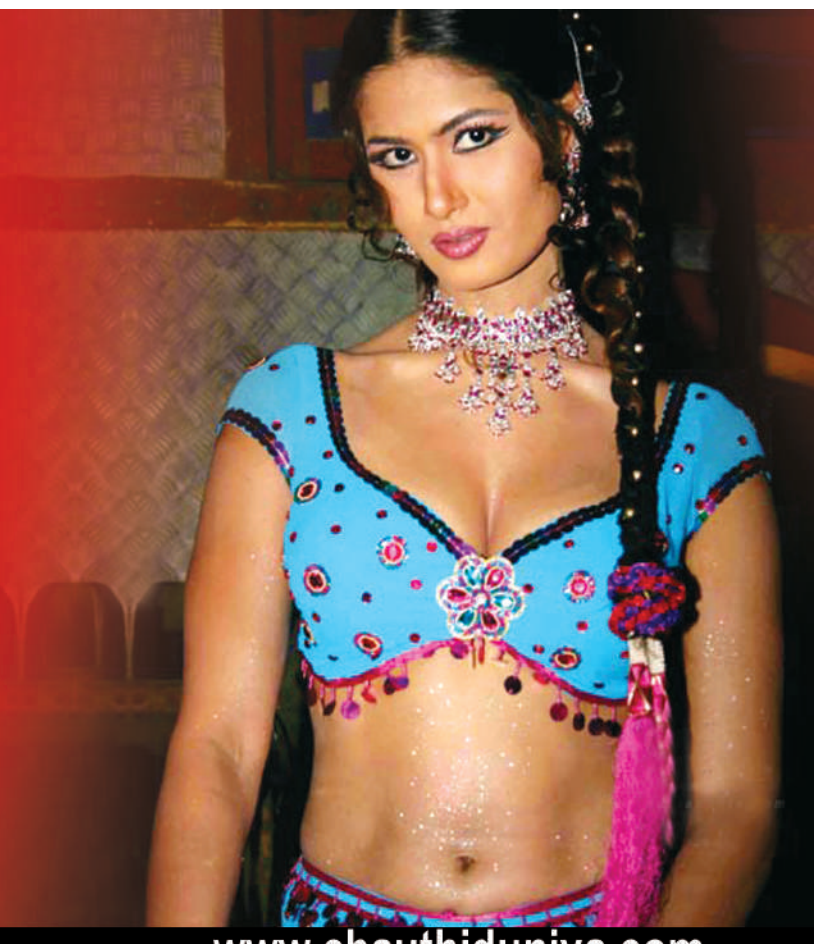

दिल्ली, 11 जनवरी-17 जनवरी 2010

www.chauthiduniya.com

शिक्षक बहाली में भ्रष्टाचार से शिक्षा चौपट

सरोज सिंह

जा का गुरु अंधला, चेला खरा निरंध. अंधे-अंधे ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत...! कबीर की यह पंक्ति बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बिलकुल सही बैठती है. राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आंकड़ों में चाहे जितनी शेखी बघार लें, लेकिन यह एक बड़ी सच्चाई है कि ग़लत बहाली नीति के कारण राज्य की बुनियादी शिक्षा का स्तर तेज़ी से गिर रहा है और चौपट होने के कगार पर है. पहले झटपट बहाली ने, फिर उसके बाद परीक्षा ने तो और भी बेड़ा गर्क कर दिया है. राज्य के कई निजी स्कूलों में एक तरफ जहां अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर की पढ़ाई कराई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा के नाम पर सिर्फ़ खानापूर्ति की जा रही है. यहां के ज़्यादातर स्कूलों की स्थिति यह है कि भवन है, तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है, तो भवन नहीं, और जहां दोनों है, वहां बच्चे नहीं हैं. हाल यह है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था एक भद्दा मज़ाक बनकर रह गई है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय प्रतीत हो रहा है. शहर स्थित स्कूलों में जहां शिक्षकों का जमावड़ा है, वहीं सुदूर ग्रामीण इलाक़ों में कई स्कूल शिक्षक के अभाव में बंद हैं. स्कूलों में शिक्षा स्तर की स्थिति यह है कि सातवीं और आठवीं कक्षा के बच्चे ठीक से नाम लिखना भी नहीं जानते और तो और, शिक्षकों का भी यही हाल है. विशेषकर हाल में नवनियुक्त शिक्षकों की स्थिति तो काफी खास्ता है.

हालांकि यह सच है कि नीतीश सरकार ने शिक्षा में सुधार के नाम पर सरकारी थैली का मुंह पूरी तरह खोल दिया है. साल 2002-03 में राज्य सरकार द्वारा जहां 3259.58 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च किए गए थे, वहीं साल 2006-07 में 5358.99 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में 7293.84 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए. राज्य सरकार द्वारा बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.

इसमें सरकार काफी हद तक सफल भी रही, लेकिन इससे बच्चों के शिक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. शिक्षा स्तर में सुधार के मामले में यह सरकार फिसड्डी साबित हुई है. इसकी सबसे बड़ी वजह अयोग्य शिक्षकों की बहाली है. सरकार की ग़लत शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से न सिर्फ़ यहां के बच्चे अच्छे शिक्षकों से वंचित रह गए, बल्कि इससे भ्रष्टाचार का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया है, जिसने शिक्षा व्यवस्था के साथ ही यहां पंचायती राज की भी दुर्गती कर दी है. शिक्षक नियुक्ति के नाम पर राज्य भर में करोड़ों-अरबों रुपये का खेल हुआ, जिसमें कथित रूप से कई ज़िला शिक्षा अधीक्षक, विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर शिक्षा विभाग के अदना कर्मचारी एवं कई सफेदपोश तक संलिप्त नज़र आए. हाल-फिलहाल तक साइकिल की सवारी करनेवाले कई पंचायत प्रतिनिधियों के दरवाजे पर चार पहिया वाहन दिखाई पड़ने लगा. वहीं 50 हज़ार से दो लाख रुपये देकर शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले शिक्षकों के चेहरे पर नौकरी प्राप्त करने के बाद दक्षता परीक्षा के नाम पर हवाइयां उड़ने लगीं. लोगों ने सोचा था कि एक दो साल बाद उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा एवं उनका वेतन पांच हज़ार रुपये मासिक से बढ़कर 25 हज़ार रुपये हो जाएगा, लेकिन ऐसे लोग अब निराश होने लगे हैं.

आश्चर्य होता है कि यही नीतीश कुमार जब रेलमंत्री थे, तब रेलवे में गैंगमैन की बहाली के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान कराया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के लिए प्राप्तांक को आधार बनाया. नतीजा यह हुआ कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति में आधे से अधिक ऐसे लोगों को शिक्षक बनाया गया, जिनका सालों पहले किताबों से नाता टूट चुका था. यह वह दौर था जब मैट्रिक की परीक्षा में परीक्षार्थी के साथ पांच सात चिटार्थी यानी परीक्षा में नकल कराने वाले भी साथ जाया करते थे. परीक्षा केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ही अधिक हुआ करता था, क्योंकि इसके लिए मोटी रक़म खर्च की जाती थी. परीक्षार्थियों को पुर्जा बनाकर दे दिया जाता था, जबकि कमजोर छात्र सीधे कापी ही बाहर भेज देते थे, जहां पूरी कॉपी सही उत्तर से रंग दी जाती थी. तेज-तर्रार अभिभावक यहीं नहीं रुकते थे, वे परीक्षा के बाद पोटली में सत्तू बांधकर कॉपी की पैरवी के लिए निकल पड़ते थे. ऐसे में स्वाभाविक है कि जो जितना बड़ा पैरवीकार होता था, उसके बच्चों को उतने अधिक नंबर मिलते थे.

> **आश्चर्य होता है कि यही नीतीश कुमार जब रेलमंत्री थे, तब रेलवे में गैंगमैन की बहाली के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान कराया था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के लिए प्राप्तांक को आधार बनाया.**

लालू सरकार में बिहार में पहली बार 1944 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई. उसके बाद पुन:1999 में भी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई. इस बीच दो और अनसूचित जाति/जनजाति तथा ट्रेंड शिक्षकों के लिए बीपीएससी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई. यही वजह है कि इस दौर में यहां जो भी शिक्षक नियुक्त हुए, उनकी प्रतिभा पर उंगली नहीं उठाई जाती है. आज भी राज्य के अधिकतर स्कूलों एवं ज़िला शिक्षा कार्यालयों का दारोमदार उन्हीं शिक्षकों पर है.

लेकिन नीतीश सरकार ने शिक्षक नियुक्ति में वही पुरानी पद्धति अपनाते हुए प्रथम चरण में दो लाख 12 हज़ार शिक्षकों को नियुक्ति किया, जबकि अभी एक लाख और शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है. इसके लिए काउंसिलिंग हो चुकी है. इस दौरान नियुक्ति में नंबर को आधार बनाया गया. सरकार का सीधा फंडा है- प्रमाणपत्र दिखाओ, नौकरी पाओ भले ही प्रमाणपत्र जाली ही क्यों न हो. जाली प्रमाणपत्र पर नौकरी पाने के कई मामले उजागर होने के बाद तो यही कहा जा सकता है. हालत यह है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान भी राज्य भर में पैसों के लेने- देने का खेल खेला जा रहा है. बरबीघा के रमेश कुमार ने बताया कि एक मुखिया ने उनसे पंचायत शिक्षक में नौकरी लगवाने के नाम पर एक लाख रुपया लिया. सौदा दो लाख रुपये में तय हुआ है. बाक़ी का एक लाख नौकरी लगने के बाद देना होगा.

इसी तरह राजेश नाम के एक युवक ने बताया कि उसकी कपड़े की दुकान है. एक लाख रुपये रिश्वत दे देने से उसका व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है. दूसरे चरण के पंचायत शिक्षकों की नियुक्ति कब होगी, इस बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है. जहां तक शिक्षकों के ज्ञान स्तर का सवाल है, शेरघाटी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक को यह भी पता नहीं कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे. नवनियुक्त शिक्षकों में से तक़रीबन 70 प्रतिशत शिक्षक ठीक से अंग्रेजी पढ़ भी नहीं पाते हैं. मिड डे मील ने तो और भी हालत ख़राब कर दी है. कई स्कूलों में इस फंड की बंदरबांट की होड़ लगी रहती है. अभी हाल में ही भाजपा के मीडिया प्रभारी वीरेंद्र झा ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस योजना में फैले भ्रष्टाचार से अवगत कराया था. सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले से भी राज्य सरकार को झटका लगा है और नियोजन की चल रही प्रक्रिया अधर में लटकती नज़र आ रही है. स्थिति यह है कि दुनिया को ज्ञान बांटने वाला राज्य बिहार आज स्वयं अंधकार में भटक रहा है. प्राप्तांकों के आधार पर बहाल शिक्षकों ने अगर गंभीरता न दिखलाई और सरकार ने मौजूदा बहाली प्रक्रिया में तुरंत बदलाव न किए तो बिहार की अगली पीढ़ी नए ज़माने की दौड़ में सबसे पीछे नज़र आएगी.

feedback@chauthiduniya.com

बिहार का मालभोग केला, तसर सिल्क, कतरनी चावल जैसे कई ऐसे उत्पाद हैं, जिसकी अगर सही तरीक़े से मार्केटिंग की जाए, तो ये दुनिया के बाज़ार में छा जाएंगे.

बहुमत की गणित बनाए रखने के लिए शिबू सोरेन को विभिन्न मामलों में फ़ैसला लेते समय कई बार सोचना पड़ेगा.

ग्रामीण संस्कृति की झलक नाबार्ड हाट में दिखी

नाबार्ड हाट के उद्घाटन के मौक़े पर लोगों को संबोधित करते चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय.

मेले में चौथी दुनिया के स्टॉल पर लगी भीड़.

गांधी जी बड़े उद्योगों के विकास में नहीं, बल्कि लघु एवं हस्तशिल्प के विकास में विश्वास रखते थे. उनका मानना था कि छोटे उद्योगों के विकास से ही गांव में समृद्धि आ सकती है, लेकिन यह दुख की बात है कि देश की आज़ादी के बाद गांधी के इस सपने को साकार करने की कोशिश नहीं की गई. नतीजा यह है कि आज़ादी के बाद बिहार में स्थापित कई बड़े उद्योग बंद हो गए, लेकिन मिथिला पेंटिंग एवं यहां के कई हैंडीक्राफ्ट्स आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं.

ये बातें बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद ने 22 दिसंबर को गांधी मैदान में स्वयंसेवी संस्था अम्बपाली की ओर से आयोजित नाबार्ड हाट के उद्घाटन करते हुए कहीं. इसके उद्घाटन के लिए राज्य के राज्यपाल देवानंद कुंवर को आना था, लेकिन किसी कारण वश वे नहीं पहुंच सके. इस मौक़े पर दिल्ली से आए चौथी दुनिया के संपादक संतोष भारतीय ने कहा कि अजीब विडंबना है कि इस तरह के ग्रामीण परिवेश से जुड़े मेलों में तथाकथित वीआईपी कहे जाने वाले लोग क़दम रखना पसंद नहीं करते. उन्हें डर लगता है कि कहीं घास पर चलते हुए उनके जूते गंदे न हो जाएं या फिर उनकी क़ीमती कपड़ों की चमक कम न हो जाए. शायद यही कारण रहा कि महामहिम राज्यपाल जी ने मेले में आने की तक़लीफ नहीं उठाई. दरअसल वीआईपी लोग कॉरपोरेट घरानों के चकाचौंध में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें समाज के वंचित और सबसे पिछली कतार में खड़े ग्रामीण महिलाओं एवं हस्तशिल्पियों के मायूस और मुरझाए चेहरे दिखाई नहीं पड़ते. उन्होंने कहा कि काश! महामहिम राज्यपाल एक बार यहां आकर देखते. सुदूर देहात से आई इन महिला हस्तशिल्पियों के मुरझाए चेहरे पर उनकी उपस्थिति से चंद पल के लिए जो ख़ुशी उभरती, उसके सामने बड़ी-बड़ी पार्टियों की दमक भी फीकी पड़ जाती.

ग्रामीण परिवेश से जुड़े मेलों में तथाकथित वीआईपी कहे जाने वाले लोग क़दम रखना पसंद नहीं करते. उन्हें डर लगता है कि कहीं घास पर चलते हुए उनके जूते गंदे न हो जाएं या फिर उनकी क़ीमती कपड़ों की चमक कम न हो जाए. शायद यही कारण रहा कि महामहिम राज्यपाल जी ने मेले में आने की तक़लीफ नहीं उठाई.

नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर संदीप घोष ने कहा कि उनका प्रयास होगा कि हर साल इस तरह के मेले का आयोजन किया जाए. राज्य में बहुत सारे शिल्प कला ग़ायब होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उचित प्रदर्शन का मौक़ा नहीं मिला. मधुबनी पेंटिंग को तो दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल है, लेकिन भागलपुर की मंजूषा कला आज भी अपनी प्रसिद्धि की बाट जोह रही है. इसी तरह बिहार का मालभोग केला, तसर सिल्क, कतरनी चावल जैसे कई उत्पाद हैं, जिसकी अगर सही तरीक़े से मार्केटिंग की जाए, तो यह दुनिया के बाज़ार में छा जाएंगे. इस दौरान नाबार्ड के चीफ मैनेजर ने स्वयं सेवी संस्था नई धरती को ग्रामीण प्रोडक्ट बेचने के लिए एक वैन की चाबी सौंपी. इस अवसर पर डॉ. आशा सिंह, संदीप घोष, एके राय, एसएस चोपड़ा, अर्चना सिंह, बी पांडे आदि मौजूद थे.

राजधानी में पहली बार भारत ग्राम का नज़ारा दिखा. हस्तशिल्पी स्थानीय हैंडीक्राफ्ट के साथ-साथ अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं को भी साथ लाए थे. राजधानी में यह पहला मौक़ा था, जब किसी मेले में देशभर के ग्रामीण इलाक़ों से आए हस्तशिल्पियों ने अपने हाथों से बने उत्पादों के साथ मेले में शिरकत की. राजस्थान का कठपुतली नाच मेले का मुख्य आकर्षण रहा. मेले के मुख्य द्वार के सामने जयपुर से आए गोगी एवं अंकित का यह स्टॉल मेले को राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति का स्वरूप प्रदान कर रहा था. रंग-बिरंगे कपड़ों से बने कठपुतली एवं कठपुतली शो ने दर्शकों का मन मोह लिया. गुनगुनी धूप और मृदंग का लुत्फ़ उठा रहे दर्शकों की फ़रमाइश पर गोगी के गीत *चलो-चलो रे ड्राइवर गाड़ी होले-होले, अंजन की सिटी में मारो मन डोले...* सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गए. इस मेले में लगभग एक सौ तीस स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें लगभग सौ स्टॉल उन ग्रामीण महिलाओं के थे, जो स्वयं सेवी सहायता समूह बनाकर विभिन्न तरह की चीज़ों का निर्माण कर आजीविका कमा रही हैं.

मेले में बिहार के अलावा मणिपुर, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली और राजस्थान से आए हस्तशिल्पियों ने शिरकत की. जमुई के एक ग्रामीण इलाक़े से आई चिंता देवी ने बताया कि वे लोग समूह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर चप्पल, चादर और जूता आदि बनाते हैं. गुजरात की ही राधा बीड्स वर्क, हैंड एंब्रोएडरी, झूमर, कार हैंगिंग, तोरण द्वार, डोर हैंगिंग आदि बनाती हैं. जितेंद्र गोरखपुर के हैं एवं ग्राहकों को लुभाने के लिए अपने साथ टेराकोटा से बने टेबल लैंप, फ्लावर पॉट, लालटेन, झूमर आदि बनाते हैं. मेले के समापन के क्षणों में सभी की आंखों में गहरी उदासी दिख रही थी. इन कलाकारों ने कहा कि यह मेला दो-चार दिन और रहता तो काफ़ी अच्छी बिक्री हो जाती.

गुजरात से आई ताराबेन एवं मनिबेन अपने समूह की महिलाओं के साथ ख़ूबसूरत गुजराती टॉप, पैच वर्क, पीट वर्क आदि बनाती हैं. मनिबेन को पहली बार बिहार आने का मौक़ा मिला है. मेले में हुई बिक्री से वह काफ़ी संतुष्ट दिखीं. मंदरजीत सिंह मणिपुर के हैं उनके स्टॉल पर पूरे मेले के दौरान भारी भीड़ नज़र आई. कौना घास से बने महीन बुनाई वाला हैंड बैग, शॉपिंग बैग, डस्टबीन, वॉल हैंगिंग ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल रहा. इनमें से ज़्यादातर स्टॉल ग्रामीण परिवेश से आई महिला हस्तशिल्पियों की थी एवं उनमें से अधिकतर पहली बार पटना आई थीं. ग्राहकों की भीड़ एवं सामानों की अच्छी बिक्री से उत्साहित गोगली ने बताया कि अगली बार जब मौक़ा मिला तो यहां ज़रूर आऊंगी.

अनुनेहा/रश्मि
feedback@chauthidunya.com

शिबू सरकार का रास्ता आसान नहीं

झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की आस पूरी हो गई. भाजपा, जदयू और आजसू ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया. गत 30 दिसंबर को राज्यपाल के शंकर नारायणन ने रांची के मोहराबादी मैदान में उन्हें राज्य के सातवें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. उनकेसाथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रघुवर दास एवं आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथग्रहण समारोह के पहले राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया था. शिबू सोरेन की शर्तों पर भाजपा और आजसू का समर्थन के लिए तैयार हो जाना राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है.

राज्यपाल के. शंकर नारायण से मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते शिबू सोरेन.

गठबंधन सरकार को चलाना शिबू सोरेन के लिए बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है. बहुमत की गणित बनाए रखने के लिए शिबू सोरेन को विभिन्न मामलों में फ़ैसला लेते समय कई बार सोचना पड़ेगा. भाजपा हर हाल में अपनी छवि से कोई समझौता नहीं करेगी, क्योंकि बिहार का चुनाव उसके सिर पर है. आजसू की अति महत्वाकांक्षा से भी गुरुजी को निपटना होगा. इसके साथ ही प्रशिनाथ हत्याकांड का भूत भी शिबू सोरेन को परेशान करता रहेगा.

चुनाव पूर्व गठबंधन के लिहाज़ से कांग्रेस-झारखंड विकास मोर्चा गठबंधन को सर्वाधिक 25 सीटें मिली थीं. सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़कर शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा 18 सीटों पर विजयी हुई थी. जबकि भाजपा-जदयू गठबंधन 20 सीटों पर सिमट कर रह गया. आंकड़ों की गणित बता रही थी कि झामुमो को साथ लिए बग़ैर कोई भी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है. ऐसे में शिबू सोरेन की मुख्यमंत्री बनने की लालसा बलवती हो गई. उन्होंने साफ़ ऐलान कर दिया कि जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगा, वह उसी को समर्थन देंगे. कांग्रेस इस शर्त पर राजी नहीं हुई, लेकिन भाजपा तुरंत तैयार हो गई, जबकि शिबू सोरेन के साथ उसकी कुंडली पहले कभी नहीं मिली थी. दरअसल, बाबूलाल मरांडी के ख़ौफ़ ने उसे इस बेमेल गठबंधन के लिए तैयार किया. मरांडी के झामिमो ने पहली बार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया. कांग्रेस केसाथ गठबंधन में उसे 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौक़ा मिला, जिनमें से 11 सीटों पर उसने जीत हासिल की और 7 सीटों पर कांटे की टक्कर देते हुए वह दूसरे स्थान पर रहा. इस प्रदर्शन को देखकर भाजपा और झामुमो के कान खड़े हो गए. उन्हें लगा कि यदि बाबूलाल सत्ता में आ गए तो वह भाजपा और झामुमो दोनों को हाशिए पर ढकेल देंगे. इसलिए कांग्रेस-झामिमो को सत्ता में आने से रोकने के लिए हाथ मिला लिया. वैसे दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत है. भाजपा एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है, जबकि झामुमो अपनी अराजकता, पदलोलुपता और सौदेबाज़ी के लिए चर्चित रहा है.

बहरहाल यह भयजनित अवसरवादी गठबंधन कितना लंबा खिंचेगा, किस मोड़ पर आकर आपसी तकरार और खींचातानी शुरू हो जाएगी, जनता का इसे कितना विश्वास हासिल हो पाएगा, यह सब कहना कठिन है. लेकिन, इस सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. पिछले नौ वर्षों की राजनीतिक अस्थिरता और लूटखसोट-भ्रष्टाचार के कारण बेपटरी हो चुकी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उसे काफ़ी ज़द्दोज़हद करनी पड़ेगी. सत्ता के दलालों को उनकी सीमाओं में रखना होगा. विकास का चक्का कई वर्षों से थमा हुआ है. वित्तीय वर्ष की समाप्ति में मात्र तीन माह रह गए हैं और योजना मद की मात्र 35 प्रतिशत राशि ही ख़र्च हो सकी है. औद्योगीकरण की गति एमओयू और माइंस आवंटन से आगे नहीं बढ़ पाई है. आधारभूत संरचना कोई आकार नहीं ले सकी है. विधि व्यवस्था की समस्या गंभीर है. उग्रवाद चरम पर है. नौकरशाही भ्रष्टाचार में डूबी है. पूर्व मंत्री घोटालों के नए रिकॉर्ड बना गए हैं. उनके विरुद्ध जांच-पड़ताल और न्यायिक मामले चल रहे हैं. इनमें से कुछ ने शिबू सरकार को बिना शर्त समर्थन भी दे दिया है. यह सब प्रमुख चुनौतियां हैं. केंद्र सरकार का नक्सल विरोधी अभियान शुरू हो चुका है. शिबू सोरेन झारखंड में इसे कितना सफल होने देंगे? भाजपा का इस मुद्दे पर क्या रुख़ होगा? शिबू सरकार इन चुनौतियों से किस हद तक निपट सकेगी? इन्हीं तमाम बिंदुओं पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं. अभी फ़िलहाल इन सवालों पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन यदि यह सरकार झारखंड गठन को लेकर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल रही तो सूबे पर लंबे समय तक इस गठबंधन का राज क़ायम रह सकता है. इसमें कोई संदेह नहीं है.

नवल किशोर सिंह
feedback@chauthidunya.com

कुंदन के सरेंडर से सियासी सरगर्मी बढ़ी

विकास कुमार

उत्तर बिहार के पच्चीस हज़ार के इनामी अपराधी कुंदन सिंह के आत्मसमर्पण के साथ ही समस्तीपुर ज़िले में राजनीतिक समीकरण भी बनने और बिगड़ने लगे हैं. वर्ष 2001 में बहुचर्चित रोसड़ा नरसंहार के मुख्य आरोपी कुंदन सिंह का नाम जब इस घटना से जुड़ा था, उसी वक़्त से वह भूमिगत होकर पुलिस की नज़रों से बच रहा था. इस दौरान वह पर्दे के पीछे रहकर राजनीति में सक्रिय रहा और अपनी पत्नी सुनीता सिंह को बहेड़ी विधानसभा से चुनाव में खड़ा किया. वहां सफलता नहीं मिली. इसके बाद उसने सुनीता सिंह को समस्तीपुर ज़िला परिषद क्षेत्र सं.-48 से चुनाव में खड़ा करवाया जहां से उसने जीत हासिल की. बाद में तत्कालीन ज़िला परिषद उपाध्यक्ष रोमा भारती के विधान परिषद में चले जाने के कारण रिक्त पड़े उपाध्यक्ष पद पर सुनीता सिंह ने पूरे दम-ख़म के साथ अपनी उम्मीदवारी पेश की और अपने बाहुबली पति कुंदन सिंह के रसूख़ से ज़िला परिषद के उपाध्यक्ष पद पर क़ब्ज़ा जमाया. 19 दिसंबर 2009 को कुंदन सिंह ने बेहद नाटकीय अंदाज़ में अपने ख़ास सहयोगी विट्ठल गिरि उर्फ़ संतोष उर्फ़ पटेल के साथ समस्तीपुर ज़िले के रोसड़ा में एसडीओएम के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया. कुंदन सिंह के आत्मसमर्पण के पीछे राजनीतिक मक़सद बताया जा रहा है. चर्चाओं का बाज़ार गर्म है कि अगामी विधानसभा चुनाव में कुंदन सिंह किसी दल से या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भाग्य आज़मा सकता है. अगर कुंदन सिंह चुनावी अखाड़े में उतरता है, तो ज़िले के कई दिग्गज़ों के राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा सकते हैं.

कुंदन सिंह के आत्मसमर्पण में उनकी पत्नी सुनीता सिंह की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है. विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान एवं ज़िला परिषद उपाध्यक्ष का पदभार संभालते समय उन्होंने अपने शुभचिंतकों से कहा था कि उनके पति बेक़सूर हैं और क़ानून में विश्वास रखते हैं. उन्होंने ज़िलावासियों से वादा किया था कि मेरे पति शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर देंगे. सुनीता ने कहा कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और अब लोगों को सोचना है कि क्या सही है और क्या ग़लत. उन्होंने देर सवेर न्याय मिलने का भरोसा जताया. कुंदन का भी यही कहना है कि वह समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते थे, बस उचित अवसर का इंतज़ार था. उन्होंने रोसड़ा नरसंहार में अपनी संलिप्तता को सिरे से नकारते हुए उसे साज़िश क़रार दिया. उन्होंने कहा कि हत्यारों ने साज़िश के तहत नरसंहार को अंजाम देने के बाद कुंदन सिंह ज़िन्दाबाद का नारा लगाया था. हसनपुर थाना क्षेत्र के निवासी कुंदन का कहना है कि उन्होंने हमेशा से ग़रीबों के मान-सम्मान की लड़ाई लड़ी है. इस दौरान हुई किसी भी प्रकार की ग़लती के लिए उन्होंने खेद जताया तथा माफ़ी मांगी.

पुलिस हिरासत में कुख्यात कुंदन सिंह.

अगामी विधानसभा चुनाव में कुंदन सिंह किसी दल से या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भाग्य आजमा सकता है. अगर कुंदन सिंह चुनावी अखाड़े में उतरता है, तो ज़िले के कई दिग्गजों के राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा सकते हैं.

कुंदन सिंह ने 90 के दशक में भी राजनीति में अपना भाग्य आज़माया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के ख़िलाफ़ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से पूरे दम-ख़म के साथ चुनाव लड़ा था. एक ज़माने में वह तत्कालीन बिहार पीपुल्स पार्टी के संस्थापक आनंद मोहन के भी ख़ासमख़ास रह चुका है. कुंदन के आत्मसमर्पण करने पर उसके गृह विधानसभा क्षेत्र हसनपुर में लोग कयास लगाने लगे हैं कि राजनीति में प्रवेश करने की मंशा से उसने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया है. उसके क़रीबी लोगों का कहना है कि कुंदन सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में हसनपुर, वारिसनगर और हायाघाट तीनों में किसी एक विधानसभा क्षेत्र से दलीय या निर्दलीय किसी भी रूप में अपना भाग्य आज़माना चाहते हैं. हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में कुंदन सिंह के दबदबा को देखते हुए राजनीतिक समीकरण बनने-बिगड़ने शुरू हो गए हैं.

बहरहाल कुंदन के आत्मसमर्पण के मामले को जनमानस चाहे जिस नज़रिये से देखे, लेकिन उसने यह साबित कर दिया है कि अपराधी को पकड़ना सचमुच मुश्किल है. नौ वर्षों तक चकमा खाती रही पुलिस को आत्ममंथन करना होगा कि आख़िर इतने संसाधनों और अधिकार के बाद भी वह कुंदन को पकड़ क्यों नहीं पाई.

feedback@chauthidunya.com

रोसड़ा नरसंहार क्या है?

पंद्रह जनवरी 2001 की शाम समस्तीपुर ज़िला के रोसड़ा शहर स्थित सिनेमा चौक पर आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई में शहर में पहली बार एके-47 राइफ़ल का खुलेआम प्रदर्शन हुआ था. छह की संख्या में आए अपराधियों ने रोसड़ा क्षेत्रीय विकास समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद सिंह समेत सात लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मुरारी सिंह के अलावा उनके चाचा हरिशंकर सिंह, बबलू नायक, हीरा सिंह, अनिल राय, कुलदीप साह (बैंककर्मी) और सुनील महतो की मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद हमलावरों ने भागते वक़्त कुंदन सिंह ज़िन्दाबाद का नारा लगाया था. कुंदन सिंह का नाम रोसड़ा नरसंहार से जुड़ा और तभी से वह सुर्ख़ियों में है. कुंदन सिंह के अलावा तहलका पत्रिका के मालिक तरूण तेजपाल की हत्या की साज़िश में गिरफ़्तार अवधेश त्यागी का भी नाम आया था. अवधेश की गिरफ़्तारी के बाद रोसड़ा न्यायालय लाकर टीआई पैरेड कराकर नरसंहार में उसकी संलिप्तता साबित की गई थी. बाद में न्यायालय में दिए गए बयान में त्यागी ने कहा कि इस शहर में मैं आज पहली बार पुलिस द्वारा लाया गया हूं. रोसड़ा नरसंहार, कुंदन सिंह, मुरारी सिंह को मैं जानता तक नहीं. बाद में अवधेश त्यागी को पुलिस ने हरिद्वार में मुठभेड़ में मार गिराया था. विगत वर्ष आपराधिक वर्चस्व की होड़ में एक शादी समारोह में घटना के एक अन्य संदेहास्पद अभियुक्त फंटुश सिंह उर्फ़ प्रेम कुमार इस्सर की हत्या कर दी गई थी.

घटना के अन्य संदेहास्पद अभियुक्त पप्पू सिंह, संजीव प्रधान, रतन लाल एवं दीपक सिंह फ़िलहाल ज़मानत पर बाहर हैं. इन सभी पर ट्रायल चल रहा है. घटना से संबंधित मुक़दमे में अभी तक किसी भी गवाह ने न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान में किसी भी अपराधी की संलिप्तता की चर्चा नहीं की है.

सुशासन में निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर बिहार के शांतिप्रिय जनता एवं सीवान जिलावासियों और जदयू के समस्त कर्मवीर कार्यकर्ताओं -नेताओं को

नववर्ष की हार्दिक शुभकामनायें

शुभेच्छु
आलोक कुमार सिंह
जिला महासचिव
जदयू सीवान (बिहार)
मो.9386074033

श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री
बिहार

जकरिया एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, सीवान
की ओर से समस्त जिलावासियों
को
नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं !
सामाजिक उत्थान के प्रति कृतसंकल्पित

शौकत अली खाँ
सचिव
मो. 9955954980

मुजफ्फर जकरिया
अध्यक्ष

श्रीमती सोनिया गांधी

श्री मनमोहन सिंह

माननीय राहुल गांधी

कांग्रेस

झारखंडवासियों को नववर्ष
की हार्दिक शुभकामनायें
सुबोधकान्त सहाय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
सह सांसद रांची लोकसभा क्षेत्र

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 11 जनवरी–17 जनवरी 2010

पिछले चार सालों में रोहतास से दुबई जाने वाली युवतियों की संख्या 15 से 20 हो गई है. वे वहां बार बाला तो नहीं, लेकिन पैरों में घुंघरू बांधकर शेखों की महफ़िलों में थिरकती हैं.

टिकट टू हॉलीवुड

एक ज़माना था, जब भोजपुरी सिनेमा अपने मुक़ाम के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज उसके सितारे हॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं. यक़ीन नहीं आता, मगर सच्चाई यही है. अब दिव्या द्विवेदी को ही लीजिए. हाल में उन्होंने एक हॉलीवुड फ़िल्म साइन की है. इस अनाम फ़िल्म में उनका लीड रोल है. अभी तक लोग उन्हें भोजपुरिया बॉम्बशेल और सेक्स सायरन के नाम से पुकारते थे, पर इस हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बाद उन्हें फिरंगी बाला कहने लगे हैं. दरअसल दिव्या इस फ़िल्म में एक न्यूड सीन कर रही हैं. पिछले दिनों मुंबई में एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने इस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का ख़ुलासा किया. दिव्या के मुताबिक़, वह इसकी स्क्रिप्ट से संतुष्ट हैं. इस सीन पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है. कहानी की मांग के हिसाब से वह इस सीन के लिए तैयार हुई हैं. ग़ौरतलब है कि फ़िल्म में दिव्या अकेली भारतीय अभिनेत्री हैं. अन्य पुरुष कलाकार अमेरिकी हैं और बाकी दो लड़कियां जर्मन हैं. उन्हें गर्व है कि उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया. दिव्या बताती हैं कि इस फ़िल्म में वह अपने पति के साथ यूएस में रहती हैं, लेकिन एक दुर्घटना में पति की मौत हो जाती है. बस उसके बाद वह अपने अनुभवों से सबक लेते हुए अपने औरत होने का इस्तेमाल करती हैं. सुनने में तो उनकी भूमिका काफ़ी बोल्ड लगती है. हो भी क्यों न! एक तो हॉलीवुड की फ़िल्म है, दूसरे आजकल जो दिखता है वही बिकता है का फॉर्मूला चलता है. चलिए, इसी बहाने दिव्या को हॉलीवुड के दर्शन हो जाएंगे.

बार बालाओं का रुख़ दुबई की ओर

सोलहवें सावन की दहलीज पर क़दम रखने वाली ऐसी कौन सी बाला होगी, जो अपने सपनों के राजकुमार के साथ दुनिया नहीं बसाना चाहती हो. यह अलग बात है कि उसकी क़िस्मत में यह क्षण कब आएगा? गाजे-बाजे के साथ मायके से विदा होकर ससुराल जाने की ख्वाहिश हर लड़की में होती है. वह चाहती है कि उसे पति का प्यार और ससुराल में ढेर सारी ख़ुशियां मिलें. लेकिन पेट की आग और हालात के चलते कुछ लड़कियां नाचने-गाने के लिए विवश हैं. यहां हम बात कर रहे हैं रोहतास के विभिन्न गांवों में रहने वाली गणिकाओं की. भूख की ज्वाला ने पहले उनसे पुश्तैनी कारोबार छीना. उसके बाद बेघर होकर वे अपने ही देश में लोगों के मनोरंजन का साधन बन गईं. जब कहीं भी ठिकाना नहीं मिला तो उन्होंने सीधे सात समंदर पार पहुंच कर अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए.

नाचना-गाना रोहतास के दर्ज़नों गांवों में रहने वाली गणिकाओं का पुश्तैनी धंधा रहा है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं थीं. कभी वे रईसों की महफ़िल में तबले की थाप पर थिरका करती थीं. उस वक़्त चेहरे पर आई मुस्कान दिखावटी न होकर असली हुआ करती थी, क्योंकि वहां मिले चांदी के खनकते सिक्कों से पेट की आग आसानी से बुझ जाती थी. धीरे-धीरे हालात बदलते गए. सभी ने उनके काम अलग-अलग नाम देना शुरू कर दिया. रोहतास के अमरा, अमरी, विश्रामपुर, कठडिहरी, पचसवा, अगरेर, बेदा, सबराबाद, मसीहाबाद, बरेहटा और धनगाईं सहित ऐसे कई गांव हैं, जहां इनकी संख्या हज़ारों में है. कुछ परिवारों के पास खेती की ज़मीन भी है, लेकिन उससे पेट की भूख नहीं मिटती. इसलिए लड़कियों ने परिवार की परवरिश के लिए पैरों में घुंघरू बांधकर महफ़िलों में थिरकना शुरू कर दिया. महफ़िल में थिरकते-थिरकते वे थियेटरों तक पहुंच गईं. महंगाई धीरे-धीरे आसमान चढ़ती गई और नाचने-गाने से परिवार का पालन पोषण मुश्किल होता चला गया. इसी बीच मुंबई के सैकड़ों बार मालिकों की नज़र रोहतास के इन गांवों पर पड़ी, जहां गणिकाओं के परिवार किसी तरह से गुज़र-बसर कर रहे थे. इसी क्रम में उनके परिवार में पढ़ने-लिखने का माहौल भी शुरू हो गया, लेकिन जैसे ही मुंबई के बारों से मिलने वाली मोटी रक़म नज़र आई तो पढ़ाई छोड़कर दर्ज़नों की संख्या में युवतियों ने सासाराम से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ ली. सोनम (काल्पनिक नाम) कहती है कि शाम के वक़्त शराब के दौर के बीच थिरकने के बाद उन्हें ज़बरन देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाता था. इसी तरह पिंकी (काल्पनिक नाम) की व्यथा है. उसने जब देह व्यापार से इंकार किया तो उसके बदन पर बेल्ट से प्रहार किया गया. अभी यह सब कुछ चल ही रहा था, तभी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहर टूटा और वहां बार बालाओं के रूप में काम करने वाली दर्ज़नों युवतियों को वापस अपने घर लौटना पड़ा.

इसी तंगहाली में फिर से ज़िंदगी बसर करने की विवशता सामने थी. आगे-पीछे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था. इसी बीच किसी ने उन्हें दुबई का रास्ता दिखाया और वहां जाने के लिए पासपोर्ट का इंतजाम भी कराया. पिछले चार सालों में रोहतास से दुबई जाने वाली युवतियों की संख्या 15 से 20 हो गई है. वे वहां बार बाला तो नहीं, लेकिन पैरों में घुंघरू बांधकर शेखों की महफ़िलों में थिरकती हैं. उनके द्वारा भेजी गई मोटी रक़म के लालच में नई पीढ़ी भी फंसती नज़र आ रही है, परिणाम यह है कि अभी भी इन परिवारों में शिक्षा का प्रतिशत 15 से 20 के आसपास है. अनुमानत: मात्र 5 प्रतिशत युवक ही स्नातक हैं, जबकि युवतियों का प्रतिशत 2 के आसपास सिमट कर रह गया है.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

बाणगंगा बनी काली गंगा

बाणगंगा का पानी दिनोंदिन काला होता जा रहा है, जिसके चलते इस नदी के अस्तिव पर संकट गहराता जा रहा है. विडंबना यह है कि इस ऐतिहासिक नदी की दुर्दशा के प्रति शासन-प्रशासन और राजनेताओं ने चुप्पी साध रखी है. इस नदी के तट पर कई बाज़ार, कस्बे, शहर और सैकड़ों गांव बसे हैं. तटीय घनी बस्तियों में गंदे पानी के कारण समय-समय पर ख़तरनाक बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते तटीय बस्तियों के नाले-नालियों का गंदा पानी और कचरा इस नदी में निरंतर समाहित होता जा रहा है, जिससे इसका पानी अब ज़हरीला हो गया है. हालांकि इस तथ्य का ख़ुलासा एक दशक पहले हो गया था, जब स्थानीय स्वयंसेवी संस्था विकास भारती ने इसके नमूने का परीक्षण कराया था. रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ कि गंदगी के कारण बाणगंगा में जहरीले पदार्थ उत्पन्न हो गए हैं. इसके जल में बीओडी 5 प्रतिशत, सल्फर 4.3 प्रतिशत और कार्बोनिक अवशिष्ट 8 प्रतिशत घुले हैं. इसमें एसिडिक अम्ल की मात्रा भी 1.5 प्रतिशत हो गई है, जिससे जल का जैव पर्यावरणीय नियंत्रण समाप्त होने लगा है. जानकारों का कहना है कि बीते एक दशक से यह नदी निरंतर जहरीली होती जा रही है.

इस प्राचीन नदी का प्रचलित नाम दाहा नदी भी है, लेकिन इसका ऐतिहासिक नाम बाणगंगा कैसे पड़ा? यह काफ़ी दिलचस्प है. कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की बारात अयोध्या से चली थी. रास्ते में बारातियों को प्यास लगी. यह बात किसी ने लक्ष्मण को बताई तो उन्होंने तुरंत अपने बाण से धरा को वेध डाला. वहां से तुरंत जलवेग निकल पड़ा. उसके बाद बारातियों ने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई. यह वही जगह है, गोपालगंज ज़िले के सासामुसा की वीरान चंवर. उस जगह से आज भी एक मोटे छिद्र से वेगमय जलधारा निकलती रहती है, जो बाणगंगा का उद्गम स्थल है. सबसे अच्छी बात यह कि जलवेग की धारा आज भी स्वच्छ एवं निर्मल है. यह नदी तीन ज़िलों गोपालगंज, सीवान और सारण से गुज़रती है. यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और फुलवरिया के समीप सरयू नदी में मिल जाती है. दाहा नदी के तट पर बसे घनी आबादी वाले सैकड़ों गांवों के अलावा सासामुसा, थावे, मीरगंज, सीवान, आंदर, हसनपुरा एवं रघुनाथपुर आदि बाज़ार, कस्बे और शहर बसे हैं.

इन क्षेत्रों की आबादी तक़रीबन 12 लाख है. नदी के प्रदूषण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव इन बस्तियों के बच्चों पर पड़ रहा है. नदी का जल पशुओं को भी पिलाया जाता है. जबकि परीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक़, इस नदी के दूषित जल में मछलियों और अन्य जलीय जीव-जंतुओं का जीना मुहाल हो गया है. नदी की सतह पर मच्छरों, बैक्टीरिया और रोगाणु वाहक वायरस की तादाद बढ़ती जा रही है. इन अवांछित पदार्थों के घुलने से लोराइड्स, क्लोराइड्स और नाइट्रेट की मात्रा कम हो गई है. इस नदी के गंदे जल में रोटा वायरस, बीकोलाई, इकोलाई, साइलेजा और गिनीवर्म जैसे परजीवी रोगाणु मौजूद हैं, जिनसे मलेरिया, फाइलेरिया, पीत ज्वर, काला ज्वर, मस्तिष्क ज्वर आदि रोग फैल रहे हैं, लेकिन शासन-प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं. बाणगंगा का जल देखकर अब लोग इसे काली गंगा भी कहने लगे हैं.

सीवान नगर के बीच से प्रवाहित होता बाणगंगा का काला पानी.

धनंजय मिश्र
feedback@chauthiduniya.com